भारतीय वैश्विक
परिषद

अमरीका-चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा

पक्ष और संभावनाएं

तीन निबंध

अरुण के. सिंह
श्रीकांत कोंडापल्ली
चिन्तामणि महापात्रा

भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली
2023

भारतीय वैश्विक परिषद

अमरीका-चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा

पक्ष और संभावनाएं

तीन निबंध

अरुण के. सिंह
श्रीकांत कोंडापल्ली
चिन्तामणि महापात्रा

भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली
जुलाई 2023

© आईसीडब्ल्यूए जुलाई 2023

अस्वीकरण: इन लेखों में विचार, विश्लेषण और सिफारिशें लेखकों के हैं।

विषय-वस्तु

प्राक्कथन 5

चीन के प्रति अमरीकी रणनीति में विकास
अरुण के. सिंह 7

संयुक्त राज्य अमरीका-चीन प्रतिस्पर्धा पर परिप्रेक्ष्य
श्रीकांत कोंडापल्ली 29

अमरीका-चीन संबंध: अस्थिर वर्तमान और परिवर्तनशील भविष्य
चिंतामणि महापात्रा 47

लेखकों के बारे में 65

प्राक्कथन

अमरीका और चीन ने तीव्र आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी और सैन्य प्रतिस्पर्धा के दौर में प्रवेश किया है। उनके संबंधों को अब 'सामरिक प्रतिस्पर्धा' कहा जा रहा है, जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी है। इसका उभरती हुई विश्व व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस संदर्भ में, अमरीका-चीन संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर इसके प्रभाव को समझना और विश्लेषण करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

आईसीडब्ल्यूए के इस विशेष प्रकाशन में, प्रतिष्ठित भारतीय विशेषज्ञ अमरीका-चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा और इसके परिणामों के कारकों और कारणों की जांच की गई है। अमरीका में भारत के पूर्व राजदूत अरुण के. सिंह द्वारा लिखा गया पहला निबंध चीन के प्रति अमरीकी रणनीति के विकास की जांच करता है, जिसमें तर्क दिया गया है कि चीन पर अमरीकी नीति ओबामा, ट्रम्प और बाइडन प्रशासन के दौरान प्रगति पर है, हालांकि दीर्घकालिक प्रवृत्ति तीव्र प्रतिद्वंद्विता की है। यह अमरीका-चीन गतिशीलता की पृष्ठभूमि में अपने हिंद-प्रशांत सहयोगियों और भागीदारों के साथ अमरीकी संबंधों की भी पड़ताल करता है। श्रीकांत कोंडापल्ली का दूसरा निबंध दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा के क्षेत्रों का विश्लेषण करता है और इस विषय को इसके ऐतिहासिक और समकालीन संदर्भ में जांचता है। उनका तर्क है कि इस तरह की गहन प्रतिस्पर्धा का परिणाम शक्ति संतुलन, शक्ति संक्रमण और उभरती विश्व व्यवस्था में परिलक्षित होने की आशा है, जिसका भारत सहित कई देशों पर प्रभाव पड़ेगा। प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा के तीसरे शोध-पत्र में तर्क दिया गया है कि अमरीका और चीन दोनों एक सूक्ष्म और परिष्कृत पारस्परिक नियंत्रण रणनीति अपनाएंगे जो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को जटिल बना देगा और अन्य देशों को कठिन विकल्प बनाने की जटिल स्थिति में डाल देगा। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष को समकालीन चीन के बारे में अमरीकी धारणा में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में वर्णित किया; ताइवान एक फ्लैश पॉइंट के रूप में; और सॉफ्ट पावर दोनों देशों के बीच सूक्ष्म संघर्ष के क्षेत्र के रूप में।

आईसीडब्ल्यूए को आशा है कि यह विशेष प्रकाशन विद्वानों, चिकित्सकों और नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी होगा जो अमरीका-चीन सामरिक प्रतिस्पर्धा की गतिशीलता और इसके दूरगामी प्रभावों को समझना चाहते हैं।

राजदूत विजय ठाकुर सिंह

महानिदेशक
भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस
जुलाई 2023

चीन के प्रति अमरीकी रणनीति में क्रमिक विकास

अरुण के. सिंह

अमरीका और चीन पिछले कुछ समय से एक गहन आर्थिक, तकनीकी, राजनयिक और सुरक्षा प्रतिस्पर्धा में संलग्न हैं। बीजिंग का बढ़ता एकतरफा और मुखर व्यवहार, विशेष रूप से अपने पड़ोस में, और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, और यूरोप सहित अन्य जगहों पर इसका बढ़ता प्रभाव, अपने स्वयं के निरंतर वैश्विक नेतृत्व और विश्वसनीयता के अमरीकी आकलन के लिए चुनौतियां पैदा करता है।

हालांकि, चीन की बढ़ती चुनौतियों के प्रति अमरीका की प्रतिक्रियाओं को अक्सर हिचकिचाहट, उलटफेर से चिह्नित किया गया है, भले ही संबंधों का चाप अनिवार्य रूप से प्रतिद्वंद्विता की ओर बढ़ गया हो। 1971 में उद्घाटन और 1979 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से चीन के प्रति अमरीका की प्रारंभिक रणनीति का उद्देश्य इस आशा में "जुड़ाव" को गहरा करना था कि इससे चीन में आर्थिक और राजनीतिक उदारीकरण होगा। अमरीकी नीति निर्माता और विश्लेषक अब बार-बार घोषणा करते हैं कि यह रणनीति और अपेक्षा विफल रही। राष्ट्रपति शी के तहत चीन को तेजी से सत्तावादी के रूप में देखा जाता है, और आर्थिक नीतियों को राज्य और सीसीपी नियंत्रण को तेज करने के रूप में देखा जाता है, जिससे अमरीका और पश्चिमी कंपनियों को हानि होती है।

चीन से संबंधित चिंताओं की पहली शूट, जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन के दौरान दिखाई दी। 2000 के राष्ट्रपति पद की दौड़ के दौरान, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने चीन को 'सामरिक भागीदार' कहने के लिए बिल क्लिंटन की आलोचना की और इसके बजाय इसे 'सामरिक प्रतियोगी' कहा, हालांकि, स्वर कुछ हद तक बदल गया क्योंकि अमरीका ने 2001 के 11 सितंबर के हमलों के मद्देनजर, 2003 में इराक पर आक्रमण के लिए इसकी योजनाएं और उत्तर कोरिया परमाणु मुद्दे से निपटने के लिए चीनी समर्थन मांगा[1]। भारत के साथ 2008 में हस्ताक्षरित असैन्य परमाणु सहयोग समझौता चीन की उभरती हुई दीर्घकालिक चुनौती से निपटने के लिए तैयार की जाने वाली प्रतिक्रियाओं का एक संकेतक था।

इसके बाद ओबामा, ट्रंप और बाइडेन प्रशासन को दंडात्मक उपायों या प्रोत्साहनों के सही मिश्रण से जूझना पड़ा, जिसे अमरीकी व्यापारिक समुदाय के भीतर अलग-अलग हितों और अमरीकी सहयोगियों और भागीदारों की आर्थिक, राजनीतिक या सुरक्षा मजबूरियों में अंतर के बीच यथासंभव व्यापक समर्थन मिलेगा।

बीजिंग का बढ़ता एकतरफा और मुखर व्यवहार, विशेष रूप से अपने पड़ोस, और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, और यूरोप सहित अन्य जगहों पर इसका बढ़ता प्रभाव, अपने स्वयं के निरंतर वैश्विक नेतृत्व और विश्वसनीयता के अमरीकी आकलन के लिए चुनौतियां पैदा करता है।

2010 तक, चीन जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। इसे अवसर के रूप में देखा गया था, लेकिन अमरीका में कुछ चिंता भी पैदा हुई।

ओबामा, ट्रम्प और बाइडन प्रशासन में चीन के प्रति अमरीकी रुख का प्रगतिशील सख्त होना

बराक:2009-2017

ओबामा प्रशासन ने शुरू में चीन को "सामरिक आश्वासन" की बात की, यह संकेत देते हुए कि वह सहकारी ढांचे में चीन के उदय को समायोजित करने के लिए तैयार था। हालांकि, बाद में यह एशिया में "धुरी" या "पुनर्संतुलन" की अभिव्यक्ति पर स्थानांतरित हो गया, एक संकेत के रूप में कि यह निर्धारित कर रहा था कि चीन की तीव्र चुनौती का उत्तर देने के लिए संसाधनों को स्थानांतरित करना और सहयोगियों और भागीदारों के साथ पुनर्निर्माण करना आवश्यक है।

ओबामा 2008 में राष्ट्रपति चुने गए थे जब वित्तीय संकट ने विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया था, और उनके प्रशासन ने शुरू में अमरीका-चीन संबंधों को प्राथमिकता दी थी। 2010 तक, चीन जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था[2]। इसे अवसर के रूप में देखा गया था, लेकिन अमरीका में कुछ चिंता भी पैदा हुई। यह स्पष्ट हो रहा था कि दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र हैं, लेकिन वे संभावित प्रतिद्वंद्वी भी हैं। ओबामा ने नवंबर 2009 में बीजिंग का दौरा किया, कार्यालय के पहले वर्ष में ऐसा करने वाले पहले अमरीकी राष्ट्रपति बने। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में ओबामा ने कहा, 'अमरीका विश्व मंच पर बड़ी भूमिका निभाने में चीन के प्रयासों का स्वागत करता है[3]। दक्षिण एशिया का उल्लेख करते हुए संयुक्त बयान में अमरीका और चीन के बीच सहयोग का आह्वान किया गया ताकि 'पूरे दक्षिण एशिया में अधिक स्थिर, शांतिपूर्ण संबंध' बनाए जा सकें। इस संदर्भ ने भारत में एक नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न की, जिसने 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद इसी तरह के घोषित इरादे की यादें ताजा कीं, जब भारत-अमरीका संबंध बहुत निचले स्तर पर थे। संपर्क किए जाने पर प्रशासन ने दावा किया कि यह अनजाने में हुआ था, चीनियों ने बातचीत के अंतिम चरण में गलती की और वे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं देने के लिए सावधान रहेंगे। स्पष्टीकरण की वैधता जो भी हो, अमरीका-चीन के संयुक्त बयान में दक्षिण एशिया में एक साथ काम करने का ऐसा कोई संदर्भ सामने नहीं आया है।

ओबामा ने बार-बार व्यक्त किया कि संयुक्त राज्य अमरीका "चीन के उदय" का स्वागत करता है जो शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और वैश्विक मामलों में एक जिम्मेदार नायक है[4]। ओबामा प्रशासन द्वारा मई 2010 में जारी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति (एनएसएस) में भारत और रूस के साथ चीन को "21 वीं सदी के प्रभाव के केंद्र" के रूप में उल्लेख किया गया था[5]। 2015 में जारी एनएसएस में कहा गया है, "संयुक्त राज्य अमरीका एक

स्थिर, शांतिपूर्ण और समृद्ध चीन के उदय का स्वागत करता है। हम चीन के साथ रचनात्मक संबंध विकसित करना चाहते हैं जो हमारे दोनों लोगों के लिए लाभ प्रदान करता है और एशिया और दुनिया भर में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देता है[6]।

13 फ़रवरी 2009 को न्यूयॉर्क की एशिया सोसाइटी में बोलते हुए, विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा, "... कुछ लोगों का मानना है कि चीन आगे बढ़ रहा है, परिभाषा के अनुसार, एक विरोधी है। इसके विपरीत, हम मानते हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका और चीन एक-दूसरे की सफलताओं से लाभ उठा सकते हैं और योगदान दे सकते हैं। यह हमारे हित में है कि हम साझा चिंता और साझा अवसरों के क्षेत्रों का निर्माण करने के लिए कड़ी मेहनत करें[7]। 1995 में बीजिंग में अपने भाषण में चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की खुलकर आलोचना करने वाली हिलेरी ने फरवरी 2009 में चीन की राजधानी की अपनी पहली यात्रा के दौरान कहा था कि उनका उद्देश्य चीनी नेतृत्व के साथ रचनात्मक संबंध विकसित करना है और मानवाधिकारों के बारे में चर्चा को अमरीका-चीन एजेंडे के अन्य मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए[8]। वह 1960 के दशक के बाद एशिया को अपना पहला गंतव्य बनाने वाली पहली विदेश मंत्री थीं।

हालांकि, अक्तूबर 2011 में विदेश नीति के लिए एक लेख में, हिलेरी क्लिंटन ने चीनी राजनीतिक और आर्थिक प्रवेश का उत्तर देने के लिए एशिया-प्रशांत पर ओबामा प्रशासन के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की बात कही[9]। उन्होंने तर्क दिया, "जैसा कि इराक में युद्ध समाप्त हो गया है और अमरीका अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस लेना शुरू कर रहा है, संयुक्त राज्य अमरीका एक धुरी बिंदु पर खड़ा है... इसलिए अगले दशक में अमरीकी शासन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक एशिया-प्रशांत क्षेत्र में कूटनीतिक, आर्थिक, सामरिक और अन्य रूप से काफी अधिक निवेश करना होगा।

ओबामा प्रशासन द्वारा 2012 के रक्षा सामरिक मार्गदर्शन में क्षेत्र में 'पुनर्संतुलन' की घोषणा के बाद से एशिया के साथ संबंधों का विस्तार करना अमेरिकी नीति निर्माताओं के लिए प्राथमिकता बन गया है। इस प्रकार, एशिया के लिए अमरीका की धुरी या एशिया में पुनर्संतुलन, अपने दूसरे चरण में ओबामा के राष्ट्रपति पद का केंद्र बिंदु बन गया।

उन्होंने नवंबर 2011 में ईस्ट-वेस्ट सेंटर, होनोलूलू में अपने भाषण में इसी दृष्टिकोण को दोहराया, जहां उन्होंने कहा, "21वीं सदी अमरीका की प्रशांत सदी होगी, इस गतिशील, जटिल और परिणामी क्षेत्र में अभूतपूर्व आउटरीच और साझेदारी की अवधि होगी[10]। ओबामा प्रशासन द्वारा 2012 के रक्षा सामरिक मार्गदर्शन में क्षेत्र में अपने "पुनर्संतुलन" की घोषणा के बाद से एशिया के साथ संबंधों का विस्तार करना अमरीकी नीति निर्माताओं के लिए प्राथमिकता बन गया[11]। इस प्रकार, एशिया के लिए अमरीका की धुरी या एशिया में पुनर्संतुलन, अपने दूसरे चरण में ओबामा के राष्ट्रपति पद का केंद्र बिंदु बन गया। नवंबर 2015 में ओबामा की एशिया यात्रा के दौरान

प्रशासन के पुनर्संतुलन दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया था क्योंकि "नवंबर 2015 में राष्ट्रपति ओबामा की एशिया और प्रशांत की नौवीं यात्रा अमरीकी राष्ट्रीय हितों के लिए इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व और हमारी व्यापक क्षेत्रीय रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसे पुनर्संतुलन के रूप में जाना जाता है[12]।

जुलाई 2011 में अपनी भारत यात्रा के दौरान हिलेरी ने चेन्नई में एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने एशिया-प्रशांत में भारत की भूमिका के बारे में बात की थी। भारत की 'लुक एट ईस्ट' नीति का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का नेतृत्व एशिया-प्रशांत के भविष्य को सकारात्मक रूप से आकार देने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, 'हिंद से प्रशांत महासागर तक भारत का जलक्षेत्र में दखल हमारे लिए इन जलमार्गों का प्रबंधक है' उन्होंने कहा कि ओबामा प्रशासन भारत को इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण साझेदार मानता है।

फिर भी, चीन की आकांक्षाओं के लिए आवास दिखाने के प्रयास जारी रहे। 8 जून 2013 को, कैलिफोर्निया के सनीलैंड्स में ओबामा और शी जिनपिंग के बीच एक बैठक में, शी जिनपिंग ने अमरीका और चीन के बीच "नए प्रकार के महान शक्ति संबंधों" का आह्वान किया[13], जो चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है और देश विश्व व्यवस्था में स्वयं को कैसे देखता है। ओबामा प्रशासन ने विशेष रूप से इस सूत्रीकरण का विरोध नहीं किया। वास्तव में, नवंबर 2013 में "एशिया में अमरीका का भविष्य" शीर्षक से एक भाषण में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसान ई राइस ने कहा, "जब चीन की बात आती है, तो हम प्रमुख शक्ति संबंधों के एक नए मॉडल को संचालित करना चाहते हैं[14]। नवंबर 2014 में बीजिंग में ओबामा और शी की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में शी जिनपिंग के हवाले से कहा गया है, 'हम चीन और अमरीका के बीच प्रमुख देशों के संबंधों के एक नए मॉडल के विकास को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए[15]। ओबामा ने शी चिनफिंग द्वारा 'नया मॉडल' तैयार किए जाने का विरोध नहीं किया और कहा कि 'चीन के साथ एक मजबूत, सहयोगात्मक संबंध एशिया की हमारी धुरी के केंद्र में है। प्रशासन ने कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की संप्रभुता के दावों की अनदेखी करते हुए 2015 में दक्षिण चीन सागर में कुछ विशेषताओं के चीनी सैन्यीकरण के लिए कोई प्रभावशीलता के साथ उत्तर नहीं दिया।

चूंकि ओबामा प्रशासन धीरे-धीरे, लेकिन लगातार नहीं, "सामरिक आश्वासन" से "धुरी" या "पुनर्संतुलन" में स्थानांतरित हो गया, यहां तक कि यह भी किसी भी प्रभावशीलता या बोधगम्य तरीके से नहीं किया जा सका, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमेरिकी व्यस्तता जारी रही, और 2014 में यूक्रेन/क्रीमिया से संबंधित रूस की कार्रवाइयों ने यूरोपीय सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।

चूंकि ओबामा प्रशासन धीरे-धीरे, लेकिन लगातार नहीं, "सामरिक आश्वासन" से "धुरी" या "पुनर्संतुलन" में स्थानांतरित हो गया, यहां तक कि यह भी किसी भी प्रभावशीलता या बोधगम्य तरीके से नहीं किया जा सका, क्योंकि पश्चिम एशिया में अमरीकी व्यस्तता जारी रही, और 2014 में यूक्रेन/क्रीमिया से संबंधित रूस की कार्रवाइयों ने यूरोपीय सुरक्षा मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।

डोनाल्ड ट्रम्प:2017-2021

2016 में राष्ट्रपति पद के लिए ट्रम्प अभियान के दौरान और उनके प्रशासन के कई चरणों में स्वर बदल गए। उन्होंने अनुमान लगाया कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से अपने एकध्रुवीय वैश्विक प्रभुत्व के चरण के दौरान चीन में नौकरियों और विनिर्माण के दुरुपयोग से अमरीका द्वारा चीन में नौकरियों और विनिर्माण के दुरुपयोग से नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। उन्होंने चीन को उसकी अनुचित और हिंसक आर्थिक नीतियों के लिए दोषी ठहराया, उस पर जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा की चोरी, मुद्रा हेरफेर और अमरीका के साथ व्यापार असंतुलन पैदा करने का आरोप लगाया[16]।

2017 में जारी ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कहा गया था, 'दशकों से अमेरिकी नीति इस विश्वास में निहित थी कि चीन के उदय और युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में उसके एकीकरण का समर्थन चीन को उदार बनाएगा। हमारी उम्मीदों के विपरीत, चीन ने दूसरों की संप्रभुता की कीमत पर अपनी शक्ति का विस्तार किया।

2017 में जारी ट्रंप प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कहा गया था, 'दशकों से अमेरिकी नीति इस विश्वास में निहित थी कि चीन के उदय और युद्ध के बाद की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में उसके एकीकरण का समर्थन चीन को उदार बनाएगा। हमारी उम्मीदों के विपरीत, चीन ने दूसरों की संप्रभुता की कीमत पर अपनी शक्ति का विस्तार किया। रणनीति ने चीन को "सामरिक प्रतियोगी" के रूप में लेबल किया[17], और कहा कि "संयुक्त राज्य अमरीका अब आर्थिक आक्रामकता या अनुचित व्यापार प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा।

ट्रम्प प्रशासन ने "हिंद-प्रशांत" क्षेत्र में चीन के प्रति अपने दृष्टिकोण को आकार देने की कोशिश की, जिसे उसने "संपूर्ण-सरकार" रणनीति कहा[18]। 2017 एनएसएस ने चीन (रूस के साथ) को एक "संशोधनवादी" शक्ति के रूप में वर्णित किया जो "हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमरीका को विस्थापित करना चाहता है, अपने राज्य-संचालित आर्थिक मॉडल की पहुंच का विस्तार करना चाहता है, और क्षेत्र को अपने पक्ष में पुनर्व्यवस्थित करना चाहता है। 2018 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में कहा गया है कि "चीन एक सामरिक प्रतियोगी है जो दक्षिण चीन सागर में सुविधाओं का सैन्यीकरण करते हुए अपने पड़ोसियों को डराने के लिए हिंसक आर्थिकी का उपयोग कर रहा है[19]। ट्रम्प के तहत, यूएस पैसिफिक कमांड ने अपना नाम बदलकर इंडो-पैसिफिक कमांड कर लिया, और एशिया-प्रशांत नामकरण के उपयोग को "इंडो-पैसिफिक" द्वारा बदल दिया गया, एक कदम जिसे चीन[20] का

मुकाबला करने के लिए रणनीतियों और ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से देखा गया, और क्षेत्र में भारत की साझेदारी के मूल्य को भी मान्यता दी गई। राष्ट्रपति पद के पिछले दो वर्षों के दौरान उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, सीआईए और एफबीआई के निदेशकों सहित कई उच्च स्तरीय अधिकारियों ने चीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लेते हुए हाई-प्रोफाइल भाषण दिए।

ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अधिक व्यापार संरक्षणवाद की भी वकालत की। इसने चीन के खिलाफ कई तरह की कार्रवाई की, जिसमें टैरिफ बढ़ाना, निर्यात नियंत्रण को कड़ा करना, निवेश स्क्रीनिंग बढ़ाना, कुछ प्रमुख चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियों को लक्षित करना और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित चिंताओं को दिखाना शामिल है। राष्ट्रपति पद की शुरुआत में, 2017 में, वाणिज्य सचिव विल्बर रॉस ने व्यापार और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में चीन के साथ अमरीकी असंतुलन के बारे में चिंता व्यक्त की, "एकतरफा" संबंधों की चेतावनी दी[21], और बाद में मिल्केन इंस्टीट्यूट 2020 एशिया शिखर सम्मेलन में, उन्होंने चीन को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में "प्रमुख सैन्य और आर्थिक खतरा" कहा[22]। विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने जुलाई 2020 में रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी एंड म्यूजियम में एक भाषण में कहा था, "चीन ने हमारी बेशकीमती बौद्धिक संपदा और व्यापार रहस्यों को खंडित कर दिया, जिससे पूरे अमरीका में लाखों (खोई) नौकरियां हुईं", और यह कि, "... हमने चीन से निपटने के लिए विदेश मंत्रालय में नीतियों का एक नया सेट तैयार किया है, जो निष्पक्षता और पारस्परिकता के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प के लक्ष्यों को आगे बढ़ा रहा है, दशकों में बढ़े असंतुलन को फिर से लिख रहा है[23]।

ओबामा ने चीन के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरती थी, हालांकि तनाव बढ़ाए बिना चीन की परिधि में आने वाले देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए कुछ प्रयास किए गए थे। 2001 के बाद से अमरीका के "आतंकवाद के खिलाफ युद्ध" की निरंतर व्यस्तता, इराक पर 2003 के आक्रमण की विरासत, और 2008 के आर्थिक संकट ने सामरिक प्रतियोगी के रूप में चीन को प्रभावशाली प्रतिक्रियाओं को अपनाने में बाधा डाली। हालांकि, ट्रम्प की घरेलू राजनीतिक रणनीतियों ने ओबामा युग के संयम के लिबास को हटा दिया, और उनके प्रशासन में कई लोगों ने चीन की सामरिक चुनौती को पहचाना।

शुरुआत में, जब ट्रम्प सत्ता में आए, तो कुछ चिंताएं थीं कि उनका प्रशासन एशिया में अमरीकी "पुनर्संतुलन" से अलग हो सकता है। शपथ लेने के कुछ ही दिनों के भीतर, वह ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप 24 से हट गए[24], जिसे ओबामा प्रशासन ने क्षेत्र में एक गैर-चीन आर्थिक समूह को मजबूत करने के तरीके के रूप में आगे बढ़ाया था। हालांकि, ट्रंप प्रशासन ने 2019 हिंद-प्रशांत रणनीति 25 में 'एक स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत' की दिशा में पिछले प्रशासनों के अपेक्षाकृत निरंतर दृष्टिकोण को बरकरार रखा[25]। इसने 31 दिसंबर 2018 को एशिया आश्वासन पहल अधिनियम (एआरआईए) भी लाया[26], जिससे परियोजना सहायता के लिए 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर को अधिकृत करके दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया को एक केंद्र बिंदु बना दिया गया।

इनके बावजूद, भारत-प्रशांत क्षेत्र में प्रशासन का रिकॉर्ड मिश्रित रहा। ओसाका में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति के साथ जून 2019 की बैठक में, उन्होंने शी से मध्य-पश्चिम राज्यों में अधिक कृषि उपज खरीदने के लिए कहा, ताकि उन्हें 2020 के चुनावों में जीतने में मदद मिल सके। सामान्य प्रोटोकॉल के विपरीत, जनवरी 2020 में, बड़ी धूमधाम के साथ, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से एक चीनी उप प्रधानमंत्री के साथ चरण 1 व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, "अमरीकी सामानों की पर्याप्त अतिरिक्त खरीद" के चीनी वादों (बाद में पूरा नहीं) के साथ कुछ चीनी आयातों पर टैरिफ कम किया, और "संरचनात्मक सुधार और चीन के आर्थिक और व्यापार शासन में अन्य बदलाव" किए। ट्रम्प की "अमरीका फर्स्ट" नीति[27], उनके तात्कालिक राजनीतिक झुकाव और हिंद-प्रशांत में प्रशासन की महत्वाकांक्षाओं के बीच असंगति का मतलब था कि रणनीति का कार्यान्वयन कम हो गया।

जो बाइडन:2021-

बाइडन को चीन के साथ समय-समय पर प्रतिस्पर्धा तेज करने की नीति पिछले प्रशासन से विरासत में मिली थी। उन्हें ट्रम्प के वोट आधार का दोहन करने की कोशिश करने के लिए इसे बनाए रखना पड़ा और अमरीकी घरेलू विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और तकनीकी बढ़त को पुनर्जीवित करने के लिए कानून पारित करने के लिए अमरीकी कांग्रेस में बाद में द्विदलीय समर्थन भी उत्पन्न करना पड़ा। बहरहाल, बाइडन ने बाद में "प्रतिस्पर्धा" और "सहयोग" को शामिल करके चीन के प्रति दृष्टिकोण को फिर से संरेखित करने की कोशिश की है[28], जबकि "संचार" को बनाए रखते हुए सुरक्षा प्रदान करने के लिए "संचार" बनाए रखा है, और जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य जैसे कुछ डोमेन में चीन के साथ सहयोग के महत्व पर जोर दिया है।

ट्रम्प की घरेलू राजनीतिक रणनीतियों ने ओबामा युग के संयम के आवरण को हटा दिया, और उनके प्रशासन में कई लोगों ने चीन की सामरिक चुनौती को पहचाना।

बाइडन के एनएसएस ने स्पष्ट रूप से कहा कि "पीआरसी एकमात्र प्रतियोगी है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से आकार देने का इरादा है और तेजी से, आर्थिक, राजनयिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति है। बीजिंग की महत्वाकांक्षा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव का एक बढ़ा हुआ क्षेत्र बनाने और दुनिया की अग्रणी शक्ति बनने की है।

जब बाइडन ने अक्तूबर को अपनी 2022 राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी की[29], तो दुनिया ट्रम्प के सत्ता में रहने की तुलना में काफी अलग थी। बाइडन प्रशासन ने रूस द्वारा यूक्रेन पर संभावित आक्रमण की संभावना का हवाला देते हुए फरवरी 2022 में एनएसएस जारी करने में देरी की थी[30]। यूक्रेन में युद्ध का मतलब था कि अमरीका की वैश्विक चिंताएं उनके बीच बढ़ते आर्थिक और राजनीतिक सहयोग की पृष्ठभूमि में रूस और चीन

से अलग-अलग चुनौतियों से एक साथ निपटने के लिए दो-तरफा हो गईं। यूरोप में रूस से दबाव और तत्काल चुनौती के बावजूद, बाइडन के एनएसएस ने स्पष्ट रूप से कहा कि "पीआरसी एकमात्र प्रतियोगी है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से आकार देने का इरादा है और तेजी से, आर्थिक, राजनयिक, सैन्य और तकनीकी शक्ति है। बीजिंग की महत्वाकांक्षा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव का एक बढ़ा हुआ क्षेत्र बनाने और दुनिया की अग्रणी शक्ति बनने की है। बाइडन प्रशासन का अंतरिम रणनीति दस्तावेज, जो जनवरी 2021 में बाइडन के पदभार संभालने के तुरंत बाद मार्च 2021 में जारी किया गया था, ने चीन का वर्णन करने के लिए इसी तरह की भाषा का प्रयोग किया था[31]। अक्तूबर में जारी 2022 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति, चीन को "पेसिंग चुनौती" और रूस को "तीव्र खतरे" के रूप में प्राथमिकता देती है[32]।

बाइडन प्रशासन में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी गठजोड़ और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं।

फरवरी 2022 में जारी बाइडन की हिंद-प्रशांत रणनीति अपनी शुरुआती पंक्ति में जोर देकर कहती है कि हिंद-प्रशांत अमरीका के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है[33]। चीन के संदर्भ में, रणनीति में कहा गया है, "पीआरसी की जबरदस्ती और आक्रामकता दुनिया भर में फैली हुई है, लेकिन यह हिंद-प्रशांत में सबसे तीव्र है" और "अगले दशक में सामूहिक प्रयास यह निर्धारित करेंगे कि क्या पीआरसी उन नियमों और मानदंडों को बदलने में सफल होता है जिन्होंने हिंद-प्रशांत और दुनिया को लाभान्वित किया है।

एनएसएस और एनडीएस भी चीन का मुकाबला करने के लिए आम सहमति बनाने और सहयोगियों और भागीदारों के साथ कार्य करने के महत्व को स्वीकार करते हैं।

अपने हिंद-प्रशांत सहयोगियों/भागीदारों के साथ अमरीकी संबंध

व्यापार, प्रौद्योगिकी और सैन्य मोर्चे पर चीन के साथ अमरीकी तनाव के साथ-साथ ताइवान, जापान, दक्षिण चीन सागर और भारत के पास इसकी सैन्य उपस्थिति और गतिविधियों में तेजी से मुखर चीनी राष्ट्रवाद, अमरीका-चीन प्रतिद्वंद्विता को तेज करने की क्षमता का प्रतीक है।

हिंद-प्रशांत में अमरीका के पांच संधि सहयोगियों में जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस और थाईलैंड शामिल हैं। बाइडन प्रशासन में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमरीकी गठजोड़ और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जा रहे हैं।

थाईलैंड

बैंकॉक के 2014 के तख्तापलट और उसके बाद "लोकतांत्रिक गिरावट" ने अमरीका के साथ आदान-प्रदान के लिए

चुनौतियां पेश कीं, जबकि बीजिंग के साथ इसके बढ़ते आर्थिक और सुरक्षा अभिसरण ने चीन-थाई संबंधों को गहरा कर दिया। थाईलैंड का चीन के साथ कोई क्षेत्रीय विवाद नहीं है और परिणामस्वरूप, चीन को सैन्य खतरे के रूप में नहीं मानता है, इस पर अमरीका में ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन थाईलैंड अमरीका के साथ अपने लंबे समय के गठबंधन को महत्व देता है क्योंकि अमरीका के साथ संबंध उपयोगी है जब वह बीजिंग पर अपनी निर्भरता को सीमित करना चाहता है[34]। इसलिए, थाईलैंड दोनों देशों के साथ घनिष्ठ सुरक्षा संबंधों को प्राथमिकता देता है[35]।

जबकि वाशिंगटन चीन को एशिया में एक प्राथमिक चुनौती के रूप में देखता है, थाईलैंड ऐसा नहीं करता है।

रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बैंकॉक में रुकने के एक महीने बाद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जुलाई 2022 में दौरा किया था। ब्लिंकन ने अपने थाई समकक्ष 36 के साथ एक सामरिक गठबंधन पर एक संयुक्त विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर किए[36], जबकि ऑस्टिन ने नाममात्र सहयोगियों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने की मांग की। हालांकि, यह टिप्पणी करना महत्वपूर्ण है कि चीन को संयुक्त विज्ञप्ति या ऑस्टिन की यात्रा की आधिकारिक विज्ञप्ति में कोई उल्लेख नहीं मिला है[37]। जबकि वाशिंगटन चीन को एशिया में एक प्राथमिक चुनौती के रूप में देखता है, थाईलैंड ऐसा नहीं करता है[38]।

फ़िलिपींस

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमरीका-फिलीपींस गठबंधन ने आतंकवाद का प्रतिकार करने और दक्षिण चीन सागर में बढ़ते चीनी सैन्य दबाव का उत्तर देने में सहयोग किया है। हिंद-प्रशांत में पांच अमरीकी संधि सहयोगियों में से, फिलीपींस ताइवान के सबसे करीब है और इसलिए, अमरीकी सेना के लिए बहुत सामरिक हित है।

अमरीका और फिलीपींस के बीच संबंधों में पिछले राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते के कार्यकाल में खटास आ गई थी, जिन्होंने चीन के प्रति पहल की थी और उन्हें अमरीका विरोधी बयानबाजी और सैन्य संबंधों को कम करने की धमकी के लिए जाना जाता था[39]। दुतेर्ते ने अपने छह साल के कार्यकाल के दौरान चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और अमरीका से दूरी बनाकर देश की विदेश नीति को नाटकीय रूप से बदल दिया। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के नेतृत्व में नई सरकार, जो 2022 में सत्ता में आई थी, ने हालांकि, अमरीका के साथ संबंधों को मजबूत करने की अपनी इच्छा का संकेत दिया है।

फरवरी 2023 में, फिलीपींस ने ताइवान के प्रति चीन के इरादों और विवादित दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के व्यापक दावों पर बढ़ती चिंता के बीच संयुक्त राज्य अमरीका को अपने सैन्य ठिकानों तक अधिक पहुंच प्रदान की[40]। अमरीका के पास पहले से ही पांच साइटों तक पहुंच है। विश्लेषकों का कहना है कि विस्तारित पहुंच इस क्षेत्र में अमरीकी स्थिति में एक महत्वपूर्ण खाई को पाट देगी, और इसे दक्षिण चीन सागर और ताइवान के पास

चीनी गतिविधि की बेहतर निगरानी करने में सक्षम बनाएगी।

फरवरी 2023 में, फिलीपींस ने संयुक्त राज्य अमरीका को अपने सैन्य ठिकानों तक अधिक पहुंच प्रदान की।

29 अप्रैल 2023 को, अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने दक्षिण चीन सागर में हाल ही में "फिलीपीन जहाजों के पीआरसी उत्पीड़न और धमकी" का उल्लेख करते हुए, पुष्टि की कि "प्रशांत क्षेत्र में एक सशस्त्र हमला, जिसमें दक्षिण चीन सागर शामिल है, फिलीपीन सशस्त्र बलों, सार्वजनिक जहाजों या विमानों पर, जिसमें तटरक्षक बल भी शामिल हैं, अमरीकी पारस्परिक रक्षा प्रतिबद्धताओं का आह्वान करेगा"।

जापान

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमरीका-जापान गठजोड़ सबसे महत्वपूर्ण है। चीन, कोरियाई प्रायद्वीप और ताइवान के करीब जापान की भू-सामरिक स्थिति और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमरीका के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का इतिहास इसे इस क्षेत्र में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। दशकों पुरानी अमरीका-जापान सुरक्षा संधि के तहत, संयुक्त राज्य अमरीका जापान की रक्षा करने का वचन देता है, जो बदले में, अपने सैन्य ठिकानों तक पहुंच प्रदान करता है जिसका उपयोग वाशिंगटन एशिया में गहराई से शक्ति पेश करने के लिए करता है।

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने गठबंधन में जापान के वित्तीय योगदान पर विवाद को बढ़ा दिया, सार्वजनिक रूप से टोक्यो पर अमरीकी सैनिकों को रखने के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया[41], लेकिन बाइडन प्रशासन ने अब तक संबंधों में इस तरह के किसी भी मतभेद को कम कर दिया है। अमरीका-जापान गठबंधन की स्थिर पुनर्परिभाषा जापान को क्षेत्रीय सुरक्षा में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए एक वैध कवर देती है। पिछले कई वर्षों में, जापान ने अपनी सैन्य क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

2022 के अंत में, जापानी सरकार ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रीय रक्षा रणनीति और रक्षा निर्माण कार्यक्रम को संशोधित किया, जिसने अपनी रक्षा रणनीति को फिर से परिभाषित किया, जो एक अधिक कार्यकर्ता दृष्टिकोण की ओर अपनी प्रगति का संकेत देता है[42]। नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में कहा गया है कि चीन जापान के लिए "अभूतपूर्व और सबसे बड़ी सामरिक चुनौती" पेश करता है।

तीन दस्तावेजों को जापान के सैन्य विस्तार का मार्गदर्शन करने के लिए पेश किया गया है। नई रणनीतियों को मंजूरी देकर, प्रधान मंत्री किशिदा फुमियो ने 1954 में देश के आत्मरक्षा बलों (एसडीएफ) के निर्माण के बाद से जापान में सैन्य शक्ति के सबसे महत्वाकांक्षी और तेजी से विस्तार की योजना बनाई है। जापान प्रमुख सुरक्षा सुधारों को अपनाता है, जिसमें एक काउंटर स्ट्राइक क्षमता भी शामिल है जो देश के विशेष रूप से आत्मरक्षा-केवल युद्ध के बाद के सिद्धांत से अलग है। इसके अलावा, नई रणनीतियों के तहत, जापान लंबी दूरी की

क्रूज मिसाइलों को तैनात करना शुरू करने की योजना बना रहा है जो चीन में संभावित लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं, पांच साल के भीतर अपने रक्षा बजट को वर्तमान 1% से सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% के नाटो मानक तक लगभग दोगुना कर सकते हैं, और साइबरस्पेस और खुफिया क्षमताओं में सुधार कर सकते हैं। जापान की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने एक बयान जारी कर जापान को साहसिक और ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए बधाई दी[43]। बयान में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि रक्षा निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि करने के जापान के उद्देश्य अमरीका-जापान गठबंधन को मजबूत और आधुनिक बनाएंगे।

पदभार संभालने के तुरंत बाद, राष्ट्रपति बाइडन और जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने व्हाइट हाउस रोज गार्डन में एक संयुक्त समाचार वरीयता में चीन से चुनौतियों का सामना करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की[44]। जनवरी 2023 में, अमरीका ने घोषणा की कि वह ओकिनावा पर एक समुद्री तटीय रेजिमेंट बनाएगा क्योंकि जापान ने रयुकु द्वीप समूह में अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है[45]। जबकि द्विपक्षीय सुरक्षा प्रतिबद्धताएं इस साझेदारी का आधार बनी हुई हैं, अमरीका और जापान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए अपने संयुक्त प्रभाव को पेश करने के लिए गठबंधन को एक साधन के रूप में देखते हैं। टोक्यो वर्तमान में उन लोगों में से एक है जो स्पष्ट रूप से चीनी व्यवहार की आलोचना करने के इच्छुक हैं[46]।

ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के साथ अमरीकी गठबंधन का महत्व सितंबर 2021 में एयूकेयूएस की घोषणा के साथ स्पष्ट हो गया। अमरीका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी का उद्देश्य ब्रिटेन को पारंपरिक रूप से सशस्त्र, परमाणु संचालित पनडुब्बी क्षमता प्रदान करना है। एक नए पनडुब्बी बेड़े को तैनात करने की संभावना के साथ, ऑस्ट्रेलिया प्रशांत क्षेत्र में अमरीका के नेतृत्व वाले गठबंधन में कहीं अधिक महत्वपूर्ण सामरिक नायक बनने के लिए तैयार है। कंसोर्टियम का बड़ा उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना और चीन से बढ़ते खतरे का उत्तर देना है।

जबकि द्विपक्षीय सुरक्षा प्रतिबद्धताएं इस साझेदारी का आधार बनी हुई हैं, अमरीका और जापान हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और कानून के शासन को बढ़ावा देने के लिए अपने संयुक्त प्रभाव को पेश करने के लिए गठबंधन को एक साधन के रूप में देखते हैं। टोक्यो वर्तमान में उन लोगों में से एक है जो चीनी व्यवहार को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए तैयार हैं।

बाइडन ने 2021 सितंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन

के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान कहा था, "अमरीका के पास ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा करीबी या विश्वसनीय सहयोगी नहीं है[47]। निर्विवाद रूप से, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण प्रशांत के पश्चिमी किनारे पर निरोध का एक उपयोगी कार्य करता है। बाइडन प्रशासन ऑस्ट्रेलिया में और अधिक लड़ाकू विमानों, बमवर्षकों और अन्य सैन्य संपत्तियों को तैनात करने का इरादा रखता है[48]। राष्ट्रपति बाइडन ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत का मुकाबला करने के लिए मार्च 2023 में एक और कदम उठाया, औपचारिक रूप से ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के साथ परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों को विकसित करने और तैनात करने की योजना का अनावरण किया[49]।

दक्षिण कोरिया

ऐतिहासिक रूप से, अमरीका-आरओके सुरक्षा गठबंधन कोरियाई प्रायद्वीप पर दबाव वाली सुरक्षा जरूरतों के प्रत्यक्ष उत्तर में बनाया गया था। उत्तर कोरिया से निरंतर परमाणु और मिसाइल चुनौती, चीन के नेतृत्व वाले क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के उदय, और अमरीका और चीन के बीच जटिल आर्थिक निर्भरता के विकास ने दक्षिण कोरिया को अमरीकी आधिकारिक अमरीकी नीति के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है। साथ ही कोरियाई प्रायद्वीप"; "बड़ी हिंद-प्रशांत रणनीति के भीतर एक महत्वपूर्ण नोड, एक रणनीति जो क्षेत्र और उससे परे चीन के विस्तारवादी और अनुदार दृष्टिकोण का मुकाबला करने पर केंद्रित है"[50]।

ऑस्ट्रेलिया के साथ अमेरिकी गठबंधन का महत्व सितंबर 2021 में एयूकेयूएस की घोषणा के साथ स्पष्ट हो गया।

ट्रम्प प्रशासन के लेन-देन और लोकलुभावन दृष्टिकोण ने दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच कुछ विभाजन खोले। हालांकि, बाइडन प्रशासन नुकसान की भरपाई के लिए काम कर रहा है।

ट्रम्प प्रशासन के लेन-देन और लोकलुभावन दृष्टिकोण ने दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच कुछ विभाजन खोले। हालांकि, बाइडन प्रशासन नुकसान की भरपाई के लिए काम कर रहा है। 26 अप्रैल, 2023 को आरओके राष्ट्रपति यून का राजकीय यात्रा पर स्वागत किया गया, जो बाइडन प्रेसीडेंसी में केवल दूसरे ऐसे आगंतुक थे (नवंबर 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रॉन थे)। दक्षिण कोरिया और जापान के जटिल इतिहास और एक-दूसरे के बारे में नकारात्मक धारणाओं ने उनके और अमरीका के बीच घनिष्ठ त्रिपक्षीय सहयोग को बाधित किया है बाइडन प्रशासन ने अमरीका-जापान-दक्षिण कोरिया सहयोग को प्राथमिकता दी है और मेल-मिलाप की दिशा में उनके हालिया कदमों का स्वागत किया है[51]।

सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के अलावा, बाइडन प्रशासन ने क्षेत्र के देशों को सकारात्मक अवसर प्रदान करने के लिए क्वाड (भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमरीका) और आईपीईएफ (इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क) के माध्यम से और अधिक करने की भी मांग की है।

अमरीका-चीन संबंधों की वर्तमान स्थिति

हालांकि अमरीका में चीन पर नजर रखने वाले कई लोगों का तर्क है कि ट्रम्प चरण के बाद से अमरीका-चीन की रणनीति काफी हद तक सुसंगत रही है, लेकिन बाइडन के तहत दृष्टिकोण में मामूली लेकिन उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं: कुछ उदाहरणों में रुख सख्त करना, और दूसरों में नरमी।

अप्रैल 2021 में, अमेरिकी सीनेट ने चीन का मुकाबला करने की मांग करते हुए 2021 के सामरिक प्रतिस्पर्धा अधिनियम को मंजूरी दे दी। अधिनियम ने बीजिंग का मुकाबला करने के लिए राजनयिक और सामरिक पहल को अनिवार्य कर दिया, जो चीन के साथ व्यवहार पर कठोर द्विदलीय भावना को दर्शाता है।

बाइडन के पदभार संभालने के तुरंत बाद अमरीकी दूरसंचार नियामक ने 2019 के कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा आधार पर हुआवेई समेत पांच चीनी कंपनियों को काली सूची में डाल दिया था[52]। मार्च 2022 में अलास्का में बाइडन के नेतृत्व में अमरीकी और चीनी अधिकारियों की पहली उच्च स्तरीय बैठक की शुरुआत काफी हंगामेदार रही थी[53]। बैठक के दौरान, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, "चीन के साथ संयुक्त राज्य अमरीका के संबंध प्रतिस्पर्धी होंगे जहां यह होना चाहिए, सहयोगी जहां यह हो सकता है, जहां यह होना चाहिए, वहां प्रतिकूल होगा। बैठक संयुक्त बयान जारी किए बिना समाप्त हो गई।

अप्रैल 2021 में, अमरीकी सीनेट ने चीन का मुकाबला करने की मांग करते हुए 2021 के सामरिक प्रतिस्पर्धा अधिनियम को मंजूरी दे दी। इस अधिनियम ने बीजिंग का मुकाबला करने के लिए राजनयिक और सामरिक पहलों को अनिवार्य कर दिया, जो चीन के साथ व्यवहार पर कठोर द्विदलीय भावना को दर्शाता है[54]। जून 2021 तक, अमरीकी सीनेट ने 2021 के नवाचार और प्रतिस्पर्धा अधिनियम को पारित किया था, जिसका उद्देश्य अमरीकी अर्धचालक विनिर्माण को बढ़ावा देकर चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करना था[55]।

अक्तूबर 2022 में एक बड़े कदम में, अमरीकी वाणिज्य विभाग ने चीन को उन्नत कंप्यूटिंग और अर्धचालक पर निर्यात नियंत्रण लागू किया। नए निर्यात नियंत्रणों के लिए कंपनियों को चीन में अमरीका निर्मित उन्नत कंप्यूटिंग और अर्धचालक उत्पादों को निर्यात करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह सैन्य अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाने वाले कुछ उच्च स्तरीय चिप्स खरीदने और निर्माण करने की चीन की

क्षमता को प्रतिबंधित करेगा। इसलिए, नए निर्यात नियंत्रणों को हाल के वर्षों में चीन के खिलाफ सबसे सख्त अमरीकी कार्रवाइयों में से एक माना जा सकता है[56]। अमरीकी चिप उपायों को जापान और नीदरलैंड सहित महत्वपूर्ण भागीदारों द्वारा भी समर्थित किया गया है, जो उन्नत अर्धचालक पारिस्थितिकी तंत्र में दो अन्य प्रमुख नायक हैं। यह भी संकेत दिया गया है कि प्रशासन चीन में उच्च तकनीक क्षेत्रों में अमरीकी निवेश को अवरुद्ध करने के लिए नियमों पर काम कर रहा है।

गुब्बारे की घटना एक और संकेतक थी कि दोनों पक्षों के पास मतभेदों को संभालने के लिए किसी भी सहमत तंत्र की कमी थी।

अगस्त 2022 में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद, बीजिंग ने द्वीप के चारों ओर सैन्य अभ्यास शुरू किया और संयुक्त राज्य अमरीका के साथ आठ आधिकारिक सैन्य-स्तरीय संवाद और सहयोग चैनलों को निलंबित या रद्द कर दिया[57]। जब बाइडन और शी ने नवंबर 2022 में बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर अपनी पहली व्यक्तिगत बैठक की थी, तो इस बात पर सहमति बनी थी कि संचार के चैनल खुले रखे जाएंगे और विदेश मंत्री प्रक्रिया को जारी रखने के लिए बीजिंग का दौरा करेंगे।

जब रिपब्लिकन ने 2023 में कांग्रेस का नियंत्रण संभाला, तो द्विदलीय समर्थन के साथ उन्होंने चीन के साथ प्रतिस्पर्धा पर एक नई कांग्रेस चयन समिति बनाई। समिति तकनीकी क्षमता, बौद्धिक संपदा संरक्षण और अनुसंधान सुरक्षा सहित अमरीका और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता के आसपास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है।

'गुब्बारा घटना' के कारण संबंधों पर गिरावट आई है, जब एक अमरीकी लड़ाकू जेट ने एक चीनी जासूसी गुब्बारे को मार गिराया जो अमरीकी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में उड़ गया था। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो फरवरी 2023 में चीन की यात्रा करने वाले थे, को अपनी यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित करनी पड़ी[58]। फरवरी 2023 के मध्य में म्यूनिख सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दौरान वांग यी और ब्लिंकन के बीच बैठक के दौरान इस घटना को उठाया गया था। विभिन्न कारणों से, बैठक में तनावपूर्ण आदान-प्रदान देखा गया[59]।

गुब्बारे की घटना एक और संकेतक थी कि दोनों पक्षों के पास मतभेदों को संभालने के लिए किसी भी सहमत तंत्र की कमी थी। नैंसी पेलोसी की यात्रा के बाद भी इसका सबूत मिला, जब चीनी समकक्षों ने कथित तौर पर अमरीकी रक्षा अधिकारियों के फोन नहीं उठाए। इससे कुछ संचार चैनलों और "गार्डरेल" को फिर से स्थापित करने की मांग तेज हो गई।

20 अप्रैल 2023 को वाशिंगटन में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में एक भाषण देते हुए, अमरीकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने कहा कि "हम जिस महत्वपूर्ण समय में हैं, जहां दुनिया यूरोप में युद्ध की पृष्ठभूमि में एक

साथ आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना कर रही है, वाशिंगटन और बीजिंग के बीच रचनात्मक जुड़ाव अनिवार्य है"[60]। यह स्वीकार करते हुए कि अमरीका-चीन संबंध 'तनावपूर्ण क्षण' में हैं, येलेन ने सुझाव दिया कि निर्यात नियंत्रण, प्रतिबंधों और विदेशी निवेश की समीक्षा के रूप में चीन के खिलाफ अमरीका की लक्षित कार्रवाई अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त करने के लिए निर्देशित थी, और प्रशासन विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में चीन में अमरीकी आउटबाउंड निवेश को प्रतिबंधित करने के लिए एक कार्यक्रम पर भी विचार कर रहा था।

हालांकि, उन्होंने कहा, "जैसा कि हम इन कार्यों को लेते हैं... ये राष्ट्रीय सुरक्षा कार्रवाइयां हमारे लिए प्रतिस्पर्धी आर्थिक लाभ हासिल करने, या चीन के आर्थिक और तकनीकी आधुनिकीकरण को दबाने के लिए डिज़ाइन नहीं की गई हैं। भले ही इन नीतियों के आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन वे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा विचारों से प्रेरित हैं। हम इन चिंताओं पर समझौता नहीं करेंगे, भले ही वे हमारे आर्थिक हितों के साथ व्यापार-बंद को मजबूर करें।

इन टिप्पणियों को आर्थिक और प्रौद्योगिकी प्रतिबंधों के दायरे को सीमित करने की मांग करके चीन के प्रति दृष्टिकोण में नरमी के संकेत के रूप में व्याख्या की गई थी।

27 अप्रैल को ब्रुकिंग्स में इसी तरह बोलते हुए, अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने 'बाइडन प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एजेंडे' पर विस्तार से बताते हुए कहा, "हमने चीन को सबसे उन्नत अर्धचालक प्रौद्योगिकी निर्यात पर सावधानीपूर्वक अनुरूप प्रतिबंध लागू किए हैं। ये प्रतिबंध सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर आधारित हैं... और हम एक प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा गठजोड़ के साथ संवेदनशील प्रौद्योगिकियों में आउटबाउंड निवेश को संबोधित करने में प्रगति कर रहे हैं[61]।

यूरोप के साथ समन्वय दिखाने का प्रयास करते हुए, सुलिवन ने कहा, "हम जोखिम कम करने और विविधता लाने के लिए हैं, न कि अलग होने के लिए। हम अपनी क्षमताओं में और सुरक्षित, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश करना जारी रखेंगे। हम अपने श्रमिकों और कंपनियों के लिए समान अवसर के लिए जोर देना जारी रखेंगे और दुरुपयोग के खिलाफ बचाव करेंगे।

येलेन ने 20 अप्रैल को अपने भाषण में जोर देकर कहा था कि चूंकि अमरीका और चीन क्रमश: सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और गहराई से एकीकृत हैं, इसलिए दोनों अर्थव्यवस्थाओं का 'अलग होना' 'बाकी दुनिया के लिए अस्थिर करने वाला होगा। हालांकि, उन्होंने चीन द्वारा "अमरीकी फर्मों को लक्षित करने वाली दंडात्मक कार्रवाइयों में हालिया वृद्धि" के बारे में भी चिंता व्यक्त की, खासकर ऐसे समय में जब चीन कहता है कि यह विदेशी निवेश के लिए फिर से खुल रहा है। ये टिप्पणियां माइक्रोन (सेमीकंडक्टर्स), ड्यू डिलिजेंस फर्म मिंट्ज और कंसल्टिंग फर्म बैन जैसी अमरीकी फर्मों के खिलाफ चीनी कार्रवाई के उत्तर में थीं। चीन ने डेटा और डिजिटल गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला पर राज्य नियंत्रण को मजबूत करने के लिए

अपने जासूसी विरोधी कानून का भी विस्तार किया है, जिससे विदेशी व्यापार के लिए चिंता पैदा हो गई है[62]।

यूरोप के साथ समन्वय दिखाने का प्रयास करते हुए, सुलिवन ने कहा, "हम जोखिम कम करने और विविधता लाने के लिए हैं, न कि अलग होने के लिए। हम अपनी क्षमताओं में और सुरक्षित, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश करना जारी रखेंगे। हम अपने श्रमिकों और कंपनियों के लिए समान अवसर के लिए जोर देना जारी रखेंगे और दुरुपयोग के खिलाफ बचाव करेंगे।

28 अप्रैल को, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ने चीन में कुछ अमरीकी व्यवसायों पर बीजिंग की कार्रवाई के उत्तर में एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया है, "हम चीनी सरकार को संशोधित कानून पर विदेशी व्यापार समुदाय के साथ परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और फिर उन नियमों को लागू करते हैं जो उचित स्पष्टता प्रदान करते हैं और निवेशकों के व्यावहारिक प्रश्नों का समाधान करते हैं[63]।

3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर वाशिंगटन पोस्ट से डेविड इग्नाटियस से बात करते हुए, अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संकेत दिया कि वाशिंगटन यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए एक समाधान खोजने में बीजिंग के साथ काम करने के लिए खुला हो सकता है। उन्होंने कहा, 'सैद्धांतिक रूप से इसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर हमारे पास कोई देश है, चाहे वह चीन हो या अन्य देश जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव है और जो न्यायसंगत और टिकाऊ शांति के लिए तैयार हैं।... हम इसका स्वागत करेंगे और यह निश्चित रूप से संभव है कि चीन को इस प्रयास में भूमिका निभानी होगी। और यह बहुत फायदेमंद हो सकता है[64]।

2 मई को विदेश मामलों द्वारा आयोजित एक वार्तालाप, 'एक महान-शक्ति युद्ध से कैसे बचें?' में, अमेरिकी संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले ने कहा कि रूसी और चीनी सेनाओं को एक-दूसरे के बारे में सही जानकारी नहीं हो सकती है और इसका श्रेय दोनों देशों के बीच कम संख्या में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों को दिया जा सकता है।

चीन पर अमरीकी नीति प्रगति पर है, क्योंकि यह वैश्विक प्रणाली में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने का प्रयास करता है, लेकिन अब एक विरोधी से निपट रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था अमरीका और पश्चिम के साथ गहराई से एकीकृत है, जिसके पास कई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में अग्रणी है, और सौ से अधिक देशों का अग्रणी व्यापारिक भागीदार है। जिसमें अमरीका के कुछ करीबी सहयोगी भी शामिल हैं।

जनरल मिले ने कहा, "वे जो भी अभ्यास करते हैं वह छोटे, अपेक्षाकृत महत्वहीन होते हैं। मेरा मतलब है, वे परिणाम के बिना नहीं हैं, लेकिन वे एक साथ विशाल सैन्य अभ्यास नहीं हैं। रूस को सैन्य समर्थन और घातक समर्थन के संदर्भ में, अभी तक वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। रूसियों ने निश्चित रूप से पूछा है; वे कई देशों से गोला-बारूद आदि की मांग कर रहे हैं। लेकिन ईरान और रूस के साथ एक संबंध, सैन्य संबंध है, उदाहरण के लिए-यह अच्छा नहीं है। लेकिन चीन के साथ यह बहुत, बहुत मामूली रहा है[65]।

निष्कर्ष

चीन पर अमरीकी नीति प्रगति पर है, क्योंकि यह वैश्विक प्रणाली में अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने का प्रयास करता है, लेकिन अब एक विरोधी से निपट रहा है जिसकी अर्थव्यवस्था अमरीका और पश्चिम के साथ गहराई से एकीकृत है, जिसके पास कई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में अग्रणी है, और सौ से अधिक देशों का अग्रणी व्यापारिक भागीदार है जिसमें अमरीका के कुछ करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। सभी अमरीकी सहयोगियों, विशेष रूप से यूरोप में, चीन से संबंधित एक समान सामरिक खतरे की धारणा नहीं है। जिन व्यवसायों ने चीन में भारी निवेश किया है, उस समय से जब इसे प्रोत्साहित किया गया था, या बाजार के अवसरों को देखते हुए, राजनीतिक तनाव या जोखिम को कम करने या अलग करने से असहज हैं। वास्तव में, टेस्ला जैसे कुछ ने नए निवेश की घोषणा की है। चीन अपनी नई ताकत का इस्तेमाल चुनिंदा कंपनियों या देशों को निशाना बनाने के लिए भी कर रहा है, दूसरों के लिए एक संदेश के रूप में भी। अब तक, चीन की बलपूर्वक कार्रवाई के लिए कोई प्रभावी समन्वित या सामूहिक धक्का नहीं दिया गया है।

अमरीकी एनएसए (एनएसए साजेके सुलिवन ने 10-11 मई, 2023 को वियना में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के विदेश मामलों के आयोग कार्यालय के निदेशक वांग यी से मुलाकात की), वाणिज्य सचिव (अमरीकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो ने 25 मई 2023 को वाशिंगटन में चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वेंताओ से मुलाकात की) के बीच कुछ हालिया संपर्क और बैठकें भी हुई हैं और विदेश मंत्री और उनके चीनी समकक्षों (विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आने वाले दिनों में ब्लिंकन की बीजिंग यात्रा से पहले 14 जून, 2023 को अपने चीनी समकक्ष किंग गैंग के साथ टेलीफोन कॉल की)। हालांकि, चीन ने जून की शुरुआत में शांगरी-ला वार्ता में अमरीकी रक्षा मंत्री के साथ बैठक से इनकार कर दिया था।

इसलिए, अमरीकी प्रशासन की रणनीति जबरदस्ती और जुड़ाव के मिश्रण को नेविगेट करेगी, जिसका उद्देश्य अपने सहयोगियों और भागीदारों को अधिक प्रभावशीलता के लिए समान रणनीतियों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। फिर भी, दीर्घकालिक आर्क चीन और अमरीका के बीच बढ़ती आर्थिक, तकनीकी और सामरिक प्रतिस्पर्धा में से एक होगा।◆

संयुक्त राज्य अमरीका-चीन प्रतिस्पर्धा पर परिप्रेक्ष्य

श्रीकांत कोंडापल्ली

चीन 2049 तक अपनी सेना को "विश्व स्तरीय" बनाने के लिए तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। चीन पहले ही संख्या के मामले में नौसैनिक क्षमताओं में अमरीका से आगे निकल चुका है।

संयुक्त राज्य अमरीका और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा आर्थिक निर्भरता के बावजूद वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर तीव्रता में बढ़ रही है। इन घटनाक्रमों का सत्ता परिवर्तन और उभरती विश्व व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, जो हाल ही में महामारी, यूक्रेन संघर्ष और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से प्रभावित हुई है। अमरीका और चीन दोनों वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख नायक हैं, सकल घरेलू उत्पाद के मामले में अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन 2010 के बाद से दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दोनों का वैश्विक व्यापार और निवेश और वैश्वीकरण प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। अमरीका और चीन दोनों तकनीकी नवाचार में अग्रणी हैं, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धि, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में। दोनों वैश्विक और क्षेत्रीय आदेशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, अमरीका अपनी वैश्विक नेतृत्व की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीन एशियाई क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर स्वयं को पहले स्थान पर रखता है।

दोनों दुनिया भर में महत्वपूर्ण सैन्य नायक हैं, हालांकि अमरीका ने कोसोवो, इराक, अफगानिस्तान और अन्य जैसे वैश्विक अभियानों में जबरदस्त क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। अमरीका के विदेशों में कई ठिकाने हैं, जबकि चीन 2015 से जिबूती में अपने ठिकाने जुटा पाया है। चीन 2049 तक अपनी सेना को "विश्व स्तरीय" बनाने के लिए तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है। चीन पहले ही की संख्या के मामले में नौसैनिक क्षमताओं में अमरीका से आगे निकल चुका है[66]। चीन ने अपने "दो शताब्दी" कार्यक्रम में अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दीर्घकालिक योजना अपनाई थी, हालांकि यह उस संरचनात्मक शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है जिसका अमरीका अभ्यास करता है[67]। वर्ष 2012 में शी चिनफिंग के सत्ता में आने के बाद से चीन की ओर से *'ताओगुआंगयांगहुई'* (अपनी क्षमताओं को छिपाने, समय के लिए बोली लगाने) से *'फेनफायूवेई'* (कुछ हासिल करने) की ओर सामरिक बदलाव के बाद चीन-अमरीका प्रतिस्पर्धा कई गुना बढ़ गई है। नीचे विवादित स्थान की एक संक्षिप्त रूपरेखा उस संदर्भ के साथ बनाई गई है जिसमें अमरीका-चीन मतभेद प्रकट हुए थे। चीन के दृष्टिकोण को सूचीबद्ध करने के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी की बहस और संबद्ध विद्वानों की धारणाओं की खोज करते हुए एक दो-स्तरीय विश्लेषण किया जाता है। यहां यह तर्क दिया जाता है कि अमरीका-चीन प्रतिस्पर्धाएं दिन-ब-दिन तेज होती जा रही हैं और भारत को इस पर ध्यान देने और शक्तियों के एक संयोजन और शक्ति संतुलन दृष्टिकोण के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

वर्ष 2012 में शी चिनफिंग के सत्ता में आने के बाद से चीन की ओर से *'ताओगुआंगयांगहुई'* (अपनी क्षमताओं को छिपाने, समय के लिए बोली लगाने) से *'फेनफायूवेई'* (कुछ हासिल करने) की ओर सामरिक बदलाव के बाद चीन-अमरीका प्रतिस्पर्धा कई गुना बढ़ गई है।

प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र

अमरीका और चीन के बीच विवाद के कई क्षेत्र हैं। इन बढ़ते घर्षणों का एक संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है। अमरीका-चीन प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और सामरिक क्षेत्रों में प्रकट होती है। द्विपक्षीय स्तर पर, लोकतंत्र और सत्तावादी पार्टी-राज्य मॉडल, मानवाधिकार, आर्थिक, व्यापार, निवेश, मुक्त व्यापार प्रस्तावों और अन्य पर मतभेद। क्षेत्रीय स्तर पर, एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह की प्रतिस्पर्धा ताइवान जलडमरूमध्य, सेनकाकू द्वीपों, दक्षिण चीन सागर और अन्य के लिए सक्रिय सैन्य प्रतिक्रियाओं में प्रकट होती है। चूंकि अमरीका पश्चिम एशियाई क्षेत्र से ऊर्जा पर कम निर्भर है, इसलिए चीन सऊदी-ईरान संबंधों के सामान्यीकरण को सुविधाजनक बनाने के अलावा, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सऊदी अरब की यात्रा और 2022 में जीसीसी देशों के साथ बैठकों में परिलक्षित शून्य को भरने का प्रयास कर रहा है। इससे पश्चिम एशियाई भू-राजनीति की रूपरेखा बदल रही है। जिबूती में चीन का एक सैन्य अड्डा भी है और उसने अदन की खाड़ी के 40 नौसैनिक मिशनों के जरिए हिंद महासागर में प्रवेश किया था। हंबनटोटा 2022 में अपने निगरानी जहाज युआन वांग 5 को डॉक करने के लिए काम में आया। अमरीका के करीब, दक्षिण अमरीका में, चीन दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और सबसे बड़ा निवेशक बन गया है और सिग्नल खुफिया सुविधाओं का निर्माण भी कर रहा है। अफ्रीका में भी, चीन सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और निवेशक बन गया है और कई देशों में हथियारों के हस्तांतरण में लगा हुआ है और नवजात अमरीकी अफ्रीकी के लिए चुनौती पैदा करता है। यूरोप में, बीआरआई परियोजनाओं और 5जी दूरसंचार सेवाओं के साथ चीन की दूसरी सबसे बड़ी व्यापारिक स्थिति और निवेशक, बहुध्रुवीय बहस के साथ ट्रांस-अटलांटिक संबंधों में सेंध लगा रहा है। मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ सीईईसी+16 की इसकी बहुपक्षीय पहल प्रमुख पश्चिमी यूरोपीय देशों को भी चुनौती दे रही है[68]। बेशक, फ्रांस में चीन के राजदूत लू शाये की पूर्व सोवियत देशों की वैधता पर टिप्पणी ने इस क्षेत्र में चीन का विरोध किया था। इनसे पता चलता है कि चीन वैश्विक शक्ति के लिए नजर रख रहा है, और अमरीका का प्रभावी ढंग से विरोध करने के लिए शक्ति के विभिन्न प्रमुख तत्वों का विश्लेषण कर रहा है, लेकिन अपनी कमजोरियों का भी विश्लेषण कर रहा है[69]।

संदर्भ

चीन का 1940 के दशक से अमरीका के साथ प्रतिकूल संबंध था, जब प्रत्येक ने दूसरे को दुश्मन के रूप में देखा था। अमरीकी व्यापार प्रतिबंध और रोकथाम नीति और कोरियाई युद्ध में सक्रिय चीनी विरोध के परिणामस्वरूप शीत युद्ध फ्रीज हो गया। हेनरी किसिंजर-रिचर्ड निक्सन की बीजिंग यात्रा और तत्कालीन सोवियत संघ के खिलाफ आम मोर्चे ने चीन और अमरीका को करीब लाया और एक "गैर-दुश्मन, गैर-दोस्त" अवधि शुरू हुई। तत्कालीन महाशक्तियों के साथ चीन की विदेश नीति निर्धारण और एक दूसरे के खिलाफ खेलने से बीजिंग के लिए जगह बन गई[70]। देंग शियाओपिंग ने 1979 में वाशिंगटन का दौरा किया और ताइवान जलडमरूमध्य में स्थिरता और आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में चीन के उदय के लिए अमरीका के आशीर्वाद के लिए एक सहमति पर मुहर लगाई। चीन और अमरीका विवादास्पद अमरीका-सोवियत द्विध्रुवीयता

के विपरीत "उपयोगी विरोधी" बन गए। देंग शियाओपिंग की *"ताओगुआंगयांगहुई"* की नीतियों के तहत चीन को काफी फायदा हुआ [जिसका अनुवाद "कम प्रोफ़ाइल रखना/अपनी क्षमताओं को छिपाना, समय के लिए बोली लगाना" के रूप में अनुवादित किया गया है] जिसमें अपनी भौतिक क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक समय अमरीका ने 1980 के पीस पर्ल प्रोग्राम के तहत चीन को सैन्य आपूर्ति पर भी विचार किया था, जिसके तहत अमरीका ने एवियोनिक्स, हेड-अप डिस्प्ले सिस्टम और अन्य को स्थानांतरित कर दिया था। नाटो ने अफगानिस्तान में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए चीन के लिए ब्रीफिंग सत्र प्रदान किए और सीआईए और चीन की सैन्य खुफिया ने मुजाहिदीन को प्रशिक्षित किया। हालांकि, जून 1989 में तियानमेन स्क्वायर की कार्रवाई ने पश्चिमी हथियार प्रतिबंध के साथ इन संबंधों को नीचे ला दिया। फिर भी, अमरीका में वाणिज्यिक और औद्योगिक लॉबी ने प्रभाव हासिल कर लिया और 1992 के डेंग के "दक्षिणी दौरे" के तुरंत बाद चीन के बाजार में अरबों डालना शुरू कर दिया[71]।

जियांग जेमिन के 1989 से 2002 के कार्यकाल ने क्लिंटन प्रशासन के तहत चीन-अमरीका संबंधों को "गैर-लक्ष्यीकरण" परमाणु समझौते, ईरान, उत्तर कोरिया और अन्य में क्षेत्रीय संघर्षों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमरीका के साथ सहयोग, अप्रसार व्यवस्थाओं में एक साथ काम करने, तस्करी और नशीले पदार्थों का मुकाबला करने और आर्थिक और व्यापार संबंधों में महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया। अमरीका ने 1995-96 में ताइवान जलडमरूमध्य संकट, मई 1999 में बेलग्रेड में चीनी दूतावास पर "आकस्मिक" बमबारी, 2001 में ईपी-3 निगरानी विमान दुर्घटना या "चिंता वाले देशों" के साथ चीन के प्रसार रिकॉर्ड के बावजूद चीन को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में शामिल होने में मदद की[72]।

राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ शी के समीकरण भी उतने ही ठंडे हैं। शी ने वास्तव में बाइडेन की चुनावी जीत को मान्यता देने में देरी की और दावोस में बोलते हुए, शी ने वैश्वीकरण प्रक्रिया के नेतृत्व का दावा करते हुए "नए शीत युद्ध" की शुरुआत का संकेत दिया।

हू जिंताओ के तहत यह प्रवृत्ति 2002 से 2012 तक "रचनात्मक और सहकारी" साझेदारी के तहत जारी रही और यहां तक कि "एक-दूसरे की ताकत पर भी ध्यान आकर्षित किया" जैसा कि हू ने अपने छह बिंदुओं में राष्ट्रपति बुश को बताया था[73]। वर्ष 2009 में भारत की यात्रा पर आए राष्ट्रपति बराक ओबामा को संबोधित करते हुए हू ने 'आपसी सामरिक विश्वास बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करने' और 'क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने' पर जोर दिया[74]। 2010 तक चीन दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था और जब उस वर्ष दोनों कोरियाई देशों के बीच चेओनान की घटना हुई, तो चीन ने पीले सागर में अपना "मोनरो सिद्धांत" लागू किया और अमरीका-दक्षिण कोरिया नौसैनिक अभ्यास को रोक दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में अमरीकी नौसेना पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया जब 2009 में यूएसएस त्रुटिहीन घटना हुई[75]। 2011 तक, हू ओबामा से कह रहे थे कि "चीन और संयुक्त राज्य अमरीका को एक-दूसरे के मूल हितों

और प्रमुख चिंताओं का सम्मान करना चाहिए" "समानता, आपसी विश्वास और मतभेदों को सुरक्षित रखते हुए सामान्य आधार की तलाश करने के सिद्धांत" के साथ। फरवरी 2012 में वाशिंगटन की अपनी यात्रा के दौरान तत्कालीन उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि विशाल प्रशांत महासागर में अमरीका और चीन जैसे दो बड़े देशों के लिए पर्याप्त जगह है।

वर्ष 2012 में सत्ता संभालने के बाद शी चिनफिंग ने ओबामा से मिलने के लिए सनीलैंड का दौरा किया और 'प्रमुख शक्ति/देश संबंध' तैयार किए और इस बात पर जोर दिया कि द्विपक्षीय संबंध 'परस्पर सम्मान और उभय जीत वाले सहयोग पर आधारित' होने चाहिए। तब से, चीन ने "गैर-संघर्ष और गैर-टकराव" को रेखांकित किया; आपसी सम्मान; और दशक के अंत तक अमरीका के साथ "जीत-जीत सहयोग"। फिर भी, शी-ट्रम्प अवधि में बड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है, जिसमें अमरीका ने 2017 में दक्षिण चीन सागर में चीन के कब्जे वाले कृत्रिम चट्टानों के 12 समुद्री मील के भीतर जहाजों को भेजा था, जबकि चीन ने इस क्षेत्र में एक अमरीकी पानी के नीचे ड्रोन पर कब्जा कर लिया था।

राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ शी के समीकरण समान रूप से ठंडे हैं, हालांकि उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने बाइडन को अपने 'पुराने मित्र' के रूप में संदर्भित किया जब बाइडन ने 2013 में चीन का दौरा किया था, जबकि तत्कालीन यूएसविस राष्ट्रपति ने उनकी "मित्रता" की बात की थी। शी ने वास्तव में बाइडेन की चुनावी जीत को मान्यता देने में देरी की और दावोस में बोलते हुए, शी ने वैश्वीकरण प्रक्रिया के नेतृत्व का दावा करते हुए "नए शीत युद्ध" की शुरुआत का संकेत दिया। स्टेट काउंसिलर यांग जिएची ने अलास्का की बैठक में हांगकांग और ताइवान पर ट्रम्प और उनकी नीतियों की कुछ सीधी आलोचना की। अमरीका के नए विदेश मंत्री ब्लिंकन ने शिनजियांग में उइगरों को 10 लाख लोगों द्वारा कैद किए जाने की भी आलोचना की, जबकि संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने 'आक्रामक चीन' का जिक्र किया, जो एक घातक ताकत है. शी और बाइडन ने फरवरी और सितंबर में दो फोन कॉल और 15 नवंबर, 2022 को वर्चुअल बैठक समाप्त की। दोनों ने बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन की बैठक में संक्षिप्त मुलाकात की, जिसमें बाइडन ने चीन से यूक्रेन में चल रहे संघर्ष में मास्को को "भौतिक समर्थन" प्रदान नहीं करने के लिए कहा। ये कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि का सुझाव देते हैं, जिसमें हाल ही में दोनों नेतृत्वों के बीच सामरिक संचार की खतरनाक कमी भी शामिल है[76]।

यह अवधि चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर के सैन्यीकरण के साथ भी मेल खाती है[77], अपने समुद्री यातायात सुरक्षा कानून (1984 के) में संशोधन करती है और इस क्षेत्र को अपने तट रक्षक के तहत घेरना शुरू कर देती है और अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने दक्षिण चीन सागर की चट्टानों तक पहुंच को बंद करने की धमकी दी है। अमरीकी रक्षा मंत्री मैटिस ने फरवरी 2017 में दक्षिण कोरिया और जापान का दौरा किया था ताकि इन देशों के साथ गठबंधन मजबूत करने के संकेत दिए जा सकें. नए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी गठबंधन पर अपने जापानी समकक्ष को आश्वासन दिया।

ताइवान लंबे समय तक एक विवादास्पद मुद्दा बना रहा, लेकिन जो बदल गया वह चीन की "सामरिक पहल" है जैसा कि शी जिनपिंग ने कहा कि इस मुद्दे को सामने लाया गया। अमरीका ने अक्तूबर 2008 में 6.4 अरब डॉलर के हथियारों के हस्तांतरण की घोषणा की थी और जनवरी 2010 में 10.7 अरब डॉलर की इसी तरह की पेशकश की थी। अक्तूबर 2002 में, जियांग जेमिन ने कहा कि "यदि संयुक्त राज्य अमरीका ताइवान को हथियारों की बिक्री बंद कर देता है, तो चीन जलडमरूमध्य क्षेत्रों में तैनात मिसाइलों को वापस ले लेगा। हालांकि, अमरीका ने इस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि चीन की मिसाइल तैनाती की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं है। ताइवान की राष्ट्रपति साई यिंग-वेन की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन करने पर चीन ने पलटवार करते हुए प्रतीकात्मक रूप से रूसी सीमाओं से डीएफ-41 अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया। राष्ट्रपति बाइडन ने ताइवान को 'ठोस समर्थन' दिया लेकिन 'वन चाइना' नीति को दोहराया, भले ही एक अमरीकी सैन्य परिवहन विमान ताइवान को टीके लेकर गया हो। अमरीकी सीनेट नेता नैन्सी पेलोसी की अगस्त 2022 में ताइवान की यात्रा पर चीन की सेना ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, जिसने ताइवान जलडमरूमध्य में बड़े पैमाने पर अभ्यास किया था। जबकि चीन द्वारा पहले भी बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों, परिवहनों, बमवर्षकों और एयर क्राफ्ट कैरियर को जुटाया गया था, ताइवान जलडमरूमध्य में हाल ही में जुटान अभूतपूर्व रहा है[78]।

चीन ने पहले भी बड़े पैमाने पर लड़ाकू विमानों, परिवहनों, बमवर्षकों और एयर क्राफ्ट कैरियर को जुटाया था, लेकिन ताइवान जलडमरूमध्य में हालिया लामबंदी अभूतपूर्व रही है।

अमरीका-चीन संबंधों के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक क्लिंटन प्रशासन के बाद से विकसित आर्थिक, व्यापार और निवेश है। हालांकि, हाल के दिनों में यह विवादास्पद भी हो गया है। यान ज़ुएतोंग के अनुसार, चीन ने *यिजिंगकुझेंग* की रणनीति में आर्थिक सहयोग के माध्यम से राजनीतिक संबंधों में सुधार किया है। हालांकि, "कायाकल्प" की दिशा में शी के तहत रणनीति में बदलाव के साथ, आर्थिक संबंधों में भी तनाव देखा गया[79]।

अमरीका-चीन संबंधों में आर्थिक मुद्दों ने फिर से उछाल लाया, जिसमें चीन को मुद्रा मैनिपुलेटर के रूप में आलोचना, बढ़ते व्यापार घाटे, राष्ट्रीय सुरक्षा और बौद्धिक संपदा चोरी पर चिंताएं, व्यापक भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और अमेरिकी नौकरियों के नुकसान के बारे में तर्क शामिल हैं[80]। अमरीका-चीन आर्थिक संबंधों में व्यापार घाटा तेजी से बढ़ रहा है जैसा कि दुनिया भर में चीन के अन्य आर्थिक भागीदारों के साथ है[81]। 1979 में जब दोनों पक्षों ने व्यापार शुरू किया, तो द्विपक्षीय व्यापार केवल 2 बिलियन डॉलर से अधिक था, लेकिन 1989 में $ 16 बिलियन, 1999 में $ 94 बिलियन, 2009 में $ 365 बिलियन और 2019 में $ 558 बिलियन हो गया। हालांकि, अमरीका को चीन का निर्यात कई गुना बढ़ गया है पृष्ठभूमि के लिए लिन चेंग-यी और डेनी रॉय, एड देखें। संयुक्त राज्य अमरीका, चीन और ताइवान संबंधों का भविष्य (न्यूयॉर्क: पालग्रेव

मैकमिलन, 2011); हार्टनेट, उथल-पुथल की एक दुनिया-संयुक्त राज्य अमरीका, चीन और ताइवान लंबे शीत युद्ध में (ईस्ट लैंसिंग: मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस, 2021) यान ज़ुएटोंग, नेतृत्व और महान शक्तियों का उदय (प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2019) पृष्ठ 34। इस विषय पर जॉन सी एमॉन, व्यापार मुद्दे, नीतियां और कानून अमरीका-चीन व्यापार परिप्रेक्ष्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव (न्यूयॉर्क: नोवा साइंस पब्लिशर्स, 2021); यून हेओ, मुक्त व्यापार और अमरीका-चीन व्यापार युद्ध एक नेटवर्क परिप्रेक्ष्य (न्यूयॉर्क: रूटलेज, 2023); पाक नुंग वोंग, तकनीकी-भू-राजनीति-अमरीका-चीन टेक युद्ध और डिजिटल स्टेटक्राफ्ट का अभ्यास (लंदन: न्यूयॉर्क, 2022); यू मियाओजी, चीन-अमरीका व्यापार युद्ध और व्यापार वार्ता (सिंगापुर: स्प्रिंगर, 2020) चीन को अमेरिकी निर्यात की तुलना में लियांग गुओयोंग और डिंग हाओयुआन, चीन-अमरीका व्यापार युद्ध (लंदन: रूटलेज, 2021) देखें। पिछले एक दशक से अधिक समय में चीन के पास औसतन $ 200 बिलियन से $ 300 बिलियन से अधिक का अधिशेष व्यापार था, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार को विनियमित करने का आह्वान किया गया था। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे यूरोपीय संघ, भारत और अन्य देशों ने भी बीजिंग के साथ उठाया है।

2022 में 690 अरब डॉलर के व्यापार में से, चीन ने अमरीका को लगभग 538 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि अमरीका ने चीन को 153 अरब डॉलर का निर्यात किया-चीन के पक्ष में लगभग 380 अरब डॉलर का व्यापार घाटा। इस तरह के घाटे एक दशक से अधिक समय से बढ़ रहे हैं, जिससे ट्रम्प को 2 मई, 2017 को यह तर्क देने के लिए उकसाया गया कि "हम चीन को हमारे देश का अनुचित करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं और यही वे कर रहे हैं। यह दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी चोरी है। 6-7 अप्रैल, 2017 को, अमरीका ने मार-ए-लागो में चीन के साथ व्यापार मतभेदों को हल करने के लिए 100-दिवसीय कार्य योजना की घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रम्प ने 8 से 10 नवंबर, 2017 तक "राज्य-यात्रा प्लस" पर बीजिंग का दौरा किया। चीन के साथ 250 अरब डॉलर के समझौते को लागू नहीं किए जाने के बाद ट्रंप ने कहा, 'मैं चीन को दोष नहीं देता। कौन एक ऐसे देश को दोष दे सकता है जो अपने नागरिकों के लाभ के लिए दूसरे देश का लाभ उठाने में सक्षम है? मैं चीन को बड़ा श्रेय देता हूं। फिर भी, यह मुद्दा अनसुलझा रहा। मार्च 2018 में अमरीका ने चीन सहित सभी इस्पात आयातों पर शुल्क लगाया था। 3 अप्रैल, 2018 को अमरीका ने 1334 उत्पादों पर टैरिफ लगाया और जल्द ही अप्रैल-जून, 2018 में चीन की दूरसंचार कंपनी जेडटीई मुद्दा सामने आया। जल्द ही संयुक्त राज्य अमरीका में विदेशी निवेश पर अमेरिकी समिति ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं पर 8 कंपनियों को अवरुद्ध कर दिया।

चीन ने अमरीका पर 'वैश्वीकरण को खत्म करने' और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को जिम्मेदार ठहराया जबकि निष्पक्ष व्यापार और बाजार पहुंच सिद्धांतों पर डब्ल्यूटीओ के नियमों का पालन नहीं किया। 18 अगस्त 2017 को, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के कार्यालय ने राष्ट्रपति ट्रम्प के अनुरोध के उत्तर में 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत चीन की जांच शुरू की। जांच का उद्देश्य "प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा और नवाचार से संबंधित चीन सरकार के कृत्यों, नीतियों और प्रथाओं" की जांच करना था।

अमरीका के साथ चीन का व्यापार युद्ध 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन व्यापार में असंतुलन, चीन द्वारा अमेरिकी वस्तुओं और उद्योग तक अपनी बाजार पहुंच से इनकार, मुद्रा हेरफेर, आईपीआर चोरी और अन्य मुद्दों पर कई वर्षों से चल रहा था। चीन ने घरेलू आर्थिक पुनर्गठन भी शुरू किया-इस संकेत के साथ कि वह अमरीका के साथ विघटन प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है।

अमरीका के साथ चीन का व्यापार युद्ध 2018 में शुरू हुआ था, लेकिन व्यापार में असंतुलन, चीन द्वारा अमेरिकी वस्तुओं और उद्योग तक अपनी बाजार पहुंच से इनकार, मुद्रा हेरफेर, आईपीआर चोरी और अन्य मुद्दों पर कई वर्षों से चल रहा था। चीन ने निर्यात-उन्मुख मॉडल से घरेलू खपत बढ़ाने के लिए घरेलू आर्थिक पुनर्गठन भी शुरू किया, मेड इन चाइना 2025 अभियान तकनीकी रूप से उन्नत देशों पर कम निर्भरता लेकिन घरेलू बाजार से सोर्सिंग-इस संकेत के साथ कि चीन अमरीका के साथ विघटन प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है। अमरीका और चीन के बीच आठ सामरिक और आर्थिक संवाद तंत्र दोनों पक्षों की संतुष्टि के लिए व्यापार विवादों को सफलतापूर्वक समाप्त करने में असमर्थ था। चीन आम तौर पर समय खरीदने, लाभ हासिल करने और दूसरे पक्ष का मुकाबला करने या सामरिक लाभ के लिए सामरिक रियायतें देने के लिए खुद को तैयार करने के लिए दूसरे पक्ष के साथ अंतहीन बातचीत का सहारा लेता है।

बीजिंग की ओर से कोई मध्य-पाठ्यक्रम सुधार नहीं किए जाने के प्रकाश में, जवाबी उपाय किए गए थे। 6 जुलाई, 2018 को, ट्रम्प प्रशासन ने चीन के उत्पादों पर टैरिफ लागू किया-818 उत्पादों पर लगभग 25 प्रतिशत टैरिफ। 14 अगस्त को, टैरिफ के दूसरे दौर की घोषणा की गई थी, जबकि चीन उसी दिन डब्ल्यूटीओ में सौर पैनल के मुद्दे को ले गया था। 22 अगस्त को अमेरिकी वित्त विभाग के अवर सचिव डेविड मालपास
और चीन के वाणिज्य उप मंत्री वांग शौवेन ने वाशिंगटन में मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा की। एक दिन बाद अमरीका द्वारा टैरिफ लागू किए गए-279 सामानों ($ 16 बिलियन मूल्य) पर लगभग 25 प्रतिशत टैरिफ और इसमें अर्धचालक, रसायन, प्लास्टिक, मोटरबाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर शामिल हैं। चीन ने अमरीका पर टैरिफ लगाकर तुरंत जवाबी कार्रवाई की-लगभग 333 सामानों पर जैसे कि कोयला, तांबा स्क्रैप, ईंधन, बस और चिकित्सा उपकरण।

कुल मिलाकर, 50 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर अमरीका के शुरुआती टैरिफ को बढ़ाकर 200 अरब डॉलर कर दिया गया - जिससे कुल शुल्क लगभग 300 अरब डॉलर हो गया। चूंकि चीन अमरीका से कम आयात करता है, इसलिए वह केवल सीमित संख्या में अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा सकता है। टैरिफ युद्ध ने अमरीका और चीन के बीच "विघटन" प्रक्रिया के लिए स्थितियां पैदा कीं। इसका इन देशों के साथ-साथ बाकी दुनिया में कारोबारी धारणा पर भी नकारात्मक असर पड़ा। अमरीका के लिए, चीन के टैरिफ का प्रभाव सोया किसानों, एलएनजी निर्यात, चीन में 70,000 अमेरिकी कंपनियों पर दबाव पड़ा क्योंकि वे चीन के बाजार में घरेलू स्तर पर $ 300 बिलियन की बिक्री उत्पन्न करते हैं। अमेरिकी सेवा क्षेत्र, विशेष रूप से यात्रा, होटल, खुदरा और मनोरंजन ने चीन के बाजार में $ 40 बिलियन से अधिक का लाभ कमाया है। चीन ने

अमेरिकी नीतियों पर दबाव बनाने के लिए इस अमेरिकी क्षेत्र का उपयोग करने की भी कोशिश की। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति शी ने स्टारबक के पूर्व प्रमुख हॉवर्ड शुल्ज को एक पत्र लिखा "उन्हें और स्टारबक्स को चीनी-अमेरिकी आर्थिक और व्यापार सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों के विकास को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए"[82]। हालांकि, अमरीका झुकने के मूड में नहीं है। ट्रम्प के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो के अनुसार, सामरिक प्रौद्योगिकियों में चीन का निवेश अमेरिकी विनिर्माण और रक्षा औद्योगिक आधार के लिए चुनौतियां पैदा करता है और वर्तमान टैरिफ चीन के हिंसक व्यापार प्रथाओं के खिलाफ रक्षा की एक महत्वपूर्ण पंक्ति है[83]। जबकि महामारी की शुरुआत और अन्य भू-राजनीतिक मुद्दों ने टैरिफ मुद्दे को पृष्ठभूमि में डाल दिया, जनवरी 2020 में एक अंतरिम समझौते के अलावा, टैरिफ युद्ध अभी भी जारी है[84]। अमरीका ने सेना से संबंध रखने वाली चीनी कंपनियों में निवेश को प्रतिबंधित कर दिया है और अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक चीनी पहुंच को सीमित करने के लिए कदम उठाए हैं[85]। अक्तूबर 2022 में, बाइडन प्रशासन ने चीन में सेमी-कंडक्टर चिप की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया।

अमरीका ने सेना से संबंध रखने वाली चीनी कंपनियों में निवेश को प्रतिबंधित कर दिया है और अमेरिकी प्रौद्योगिकी तक चीनी पहुंच को सीमित करने के लिए कदम उठाए हैं। अक्तूबर 2022 में, बाइडन प्रशासन ने चीन में सेमी-कंडक्टर चिप की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया।

चीन की मुद्रा-रेनमिनबी (आरएमबी) का दर्जा भी अमरीका-चीन संबंधों में दो कारणों से एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में विनिमय दर में हेरफेर है ताकि इसके निर्यात के लिए अनुचित लाभ प्राप्त किया जा सके। यह अनुमान लगाया गया है कि आरएमबी 20-40 प्रतिशत कम है। जब चीन ने सुधार और खोलने की नीतियों को शुरू किया, तो अमरीकी डॉलर के साथ आरएमबी विनिमय दर का अवमूल्यन किया गया ताकि चीन के निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार किया जा सके। उदाहरण के लिए, 1980 में, विनिमय दर आरएमबी 1.5 थी जो 1994 में घटकर 8.6 हो गई। जुलाई 2005 तक मामूली उतार-चढ़ाव जारी रहा जब खूंटी को उठाया गया। पिछले दशक में, आरएमबी यूएसडी के लिए 6 के आसपास मंडरा रहा था। चूंकि यह मुद्दा निर्यात से जुड़ा हुआ है, अमरीका (और यूरोपीय संघ, जापान, भारत और अन्य देश) चीन पर द्विपक्षीय रूप से और जी 20 जैसे बहुपक्षीय मंचों पर इस तरह के व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए एक समझौते को अपनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। चीन अब तक या तो टाल-मटोल करता रहा है या अस्थायी कदम उठाता रहा है।

एक दूसरा संबंधित मुद्दा चीन के व्यापार भागीदारों और बीआरआई परियोजनाओं के माध्यम से आरएमबी अंतर्राष्ट्रीयकरण है। इसे अमरीका द्वारा मुद्रा परिसंचरण में अमरीकी डॉलर की प्रमुख भूमिका को कम करने के उपाय के रूप में देखा जाता है।

विघटन प्रक्रिया ने दोनों देशों के साथ-साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी काफी प्रभाव डाला। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान पैदा हुआ, क्योंकि कंपनियां अन्य बाजारों विशेष रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में स्थानांतरित हो गईं ताकि उनके विनिर्माण और सोर्सिंग स्थानों में विविधता आ सके। यह नवाचार और तकनीकी विकास को भी प्रभावित कर रहा है।

चीन के दृष्टिकोण

चीन के "अग्रणी" अंग के रूप में, कम्युनिस्ट पार्टी अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह अमेरिकी नीति के बारे में निर्णय लेती है[86]। अन्य देशों के विपरीत, चीन में निर्णय लेने की प्रक्रिया अपारदर्शी और अत्यधिक केंद्रीकृत है[87]। पार्टी के महासचिव और पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के अन्य सदस्यों की अध्यक्षता वाले सेंट्रल स्मॉल लीडिंग ग्रुप और अन्य जैसे कि उप-प्रधानमंत्री, स्टेट काउंसिलर, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क विभाग, विदेश मंत्रालय, सेना, वाणिज्य, संस्कृति और मीडिया के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। फरवरी 2018 में, अमरीका सहित चीन की विदेश नीति मुद्राओं के बारे में निर्णय लेने के लिए एक केंद्रीय विदेश मामलों के आयोग की स्थापना की गई थी।

कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को चीन में सभी नीतियों का "शीर्ष" माना जाता है, जिसमें विदेश नीति भी शामिल है। विदेश मंत्रालय, विदेशों में उसके मिशन, थिंक टैंक और विश्वविद्यालय नीति निर्माण प्रक्रियाओं में योगदान करते हैं। एक संक्षिप्त उल्लेख नीचे किया गया है। पिछले दशक में, शी जिनपिंग ने 2012, 2017 और 2022 में तीन कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, जिसमें विदेश नीति "दिशानिर्देशों" में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए। 2012 में 18वीं सीसीपी कांग्रेस के बाद से, शी ने "कुछ हासिल करने" [*फेनफायूवेई*], चाइना ड्रीम, चाइना कायाकल्प और "नए युग" की दिशा में चीन की मुद्राओं में बदलाव किया। "नए प्रकार के प्रमुख शक्ति संबंधों" के साथ मुख्य हितों की सुरक्षा आदर्श बन गई। चीन की सेना को "उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति के अनुरूप" पुनर्स्थापित किया जाना है। नवंबर 2014 और जून 2018 के "विदेशी मामलों के कार्य सम्मेलनों" ने आउटरीच कार्यक्रमों और वैश्विक तैनाती को रेखांकित किया।

2012 में 18वीं सीसीपी कांग्रेस के बाद से, शी ने "कुछ हासिल करने" [*फेनफायूवेई*], चाइना ड्रीम, चाइना कायाकल्प और "नए युग" की दिशा में चीन की मुद्राओं में बदलाव किया। "नए प्रकार के प्रमुख शक्ति संबंधों" के साथ मुख्य हितों की सुरक्षा आदर्श बन गई। चीन की सेना को "उसकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति के अनुरूप" पुनर्स्थापित किया जाना है।

19वीं पार्टी कांग्रेस अधिक साहसी थी। 2013 में शुरू की गई बेल्ट एंड रोड पहल (बीआरआई) को अब पार्टी संविधान में रखा गया था। चीन ने पहले एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) भी लॉन्च

किया, जिसे बीआरआई के साथ अमरीका के नेतृत्व वाली उदार वित्तीय व्यवस्था के विकल्प के रूप में देखा जाता है[88]। 2017 में 19वीं सीसीपी कांग्रेस में शी ने 2049 तक चीन के लिए एक ठोस रोड मैप के साथ एक कदम आगे बढ़ाया था। उन्होंने चीन के "केंद्र मंच" की ओर बढ़ने के बारे में बात की-अमरीका को विस्थापित करने के संदर्भ में जो वर्तमान में 1945 से वैश्विक और क्षेत्रीय आदेशों के केंद्र में है और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से और भी अधिक। शी ने साझा भाग्य वाले समुदाय का निर्माण करने की कसम खाई-फिर से समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठबंधन के करीब साझेदारी बनाने के लिए एक व्यंजना। जून 2013 के "प्रमुख शक्ति संबंधों" के बजाय "नए प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों" का आह्वान किया गया था[89]। ताइवान को "6 नंबर" में घोषित किया गया था-अमरीका के लिए एक चेतावनी। तब से, चीन ने ताइवान पर अपना विस्तार करना शुरू कर दिया और ताइवान के साथ एक तीखी प्रतिस्पर्धा स्पष्ट हो गई।

2017 में 19वीं सीसीपी कांग्रेस में शी ने 2049 तक चीन के लिए एक ठोस रोड मैप के साथ एक कदम आगे बढ़ाया था। उन्होंने चीन के "केंद्र मंच" की ओर बढ़ने के बारे में बात की-अमरीका को विस्थापित करने के संदर्भ में जो वर्तमान में 1945 से वैश्विक और क्षेत्रीय आदेशों के केंद्र में है और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से और भी अधिक।

अक्तूबर 2022 में अगली पार्टी कांग्रेस में, शी ने कहा कि पार्टी ने "गंभीर, जटिल अंतर्राष्ट्रीय विकास और विशाल जोखिमों और चुनौतियों की एक श्रृंखला" का प्रभावी ढंग से उत्तर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन ने "आधिपत्य और सत्ता की राजनीति के सभी रूपों के खिलाफ एक स्पष्ट रुख अपनाया है, और हम एकतरफावाद, संरक्षणवाद और किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार के विरूद्ध अपने विरोध में कभी नहीं डगमगाए हैं। इसके अलावा, शी ने उल्लेख किया कि चीन "एकतरफावाद के सभी रूपों और विशेष देशों के खिलाफ लक्षित ब्लॉक और विशेष समूहों के गठन का विरोध करता है। कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में पहली बार इस कांग्रेस में अर्थव्यवस्था के बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा निगरानी शब्द बन गई। वास्तव में, शी ने घोषणा की कि राष्ट्रीय सुरक्षा चीन के कायाकल्प का आधार है[90]।

4-13 मार्च, 2023 को 14वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के समापन सत्र के दौरान, शी ने सुरक्षा को "विकास का आधार" बताया, जबकि स्थिरता समृद्धि के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है और पीएलए को "स्टील की महान दीवार" में बनाने का आह्वान किया जो चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और विकास त्मक हितों की रक्षा करता है। पोलित ब्यूरो की एक अन्य बैठक में शी ने मौजूदा अवधि को 'बेहद असामान्य और असाधारण अवधि' बताया और कहा कि 'अमरीका के नेतृत्व वाले पश्चिमी देशों ने हमें चौतरफा तरीके से नियंत्रित और दबाया है।' ये प्रत्यक्ष संदर्भ और शी की मास्को यात्रा बाद में आने वाले वर्षों में अमरीका के साथ अलगाव प्रक्रिया के तेज होने का संकेत देती है।

कुल मिलाकर शी ने अमरीका के साथ सहयोग और रचनात्मक जुड़ाव पर जोर दिया, विशेष रूप से वैश्विक

शासन और आर्थिक विकास के मुद्दों पर, वह वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से हाल की वैश्विक व्यवस्था में उथल-पुथल देखने के लिए भी महत्वाकांक्षी हैं। दूसरे शब्दों में शी 'सामरिक अवसरों' की तलाश में थे। शी के कार्यकाल के दौरान चीन-अमरीका टकराव कई गुना बढ़ गया।

पोलित ब्यूरो की मौजूदा स्थायी समिति के सदस्य वांग हुनिंग का चीन की अमेरिकी नीतियों को बनाने में काफी प्रभाव माना जाता है। वांग को अमेरिकी गिरावट के सिद्धांत के पीछे मुख्य व्यक्ति कहा जाता है जो चीन की विदेश नीति हलकों में गूंजता है। इससे पहले 1988 से 1989 में उन्होंने अमरीका का दौरा किया था और अमेरिकी समाज, राजनीति और आर्थिक एवं तकनीकी विकास की आलोचना की थी। उन्होंने राजनीतिक समानता, संवैधानिक गारंटी की घटना को रेखांकित किया लेकिन आय असमानताओं, टूटे हुए परिवारों, अश्वेतों और अन्य लोगों के भेदभाव के बारे में भी बताया[91]। वांग के विचारों को नेतृत्व के बीच व्यापक रूप से रखा जाता है और "नव-अधिनायकवाद" पर उनका काम चीन में जीवन के सभी क्षेत्रों पर कम्युनिस्ट पार्टी की पकड़ को तेज करने और इसके आर्थिक और तकनीकी विकास को बढ़ावा देने की वकालत करता है। अमेरिकी लोकतंत्र पर वांग की आलोचना ने विदेशों में पार्टी-राज्य "चीन मॉडल" को बढ़ावा देने के साथ-साथ विदेशों में लोकतंत्रों को नीचा दिखाने या यहां तक कि नष्ट करने का रूप भी लिया।

चीन में अन्य प्रमुख पार्टी-राज्य प्रतिनिधियों में हाल ही में सेवानिवृत्त पोलित ब्यूरो सदस्य और स्टेट काउंसिलर यांग जिएची, अमरीका में पूर्व राजदूत और बाद में विदेश मंत्री, वर्तमान स्टेट काउंसिलर और पूर्व विदेश मंत्री वांग यी और वर्तमान विदेश मंत्री किन गैंग शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में अमरीका में राजदूत के रूप में कार्य किया है। जबकि नीति "छोटे अग्रणी समूहों" पर निर्धारित की गई है और इस प्रकार, उपरोक्त तीन के लिए एक अत्यधिक केंद्रीकृत सेट-अप में व्यावहारिक स्थान सीमित है, भले ही वे निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा भी हों।

अमरीका में राजदूत के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, अमरीका पर यांग के विचार सामान्य रूप से व्यावहारिक थे और स्थिर संबंधों को बढ़ावा देते थे। कुछ अड़चनों के बावजूद, वे अमरीका-चीन संबंधों के सुनहरे दिन भी थे। यांग के कार्यकाल को मोटे तौर पर द्विपक्षीय संबंधों के प्रबंधन के रूप में कहा जा सकता है, भले ही उन्होंने ताइवान और अन्य मुद्दों के प्रति अमरीका की नीतियों पर आपत्ति व्यक्त की।

वर्तमान स्टेट काउंसिलर वांग यी को जापान विशेषज्ञ कहा जाता है, भले ही अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत में उन्होंने समान उपचार और गैर-हस्तक्षेप नीतियों पर जोर दिया था। वांग के कार्यकाल में अधिक "बहुध्रुवीय" बयान देखे गए जो अमेरिकी एकतरफा नीतियों की आलोचना करते थे।

चीन के वर्तमान विदेश मंत्री किन गैंग ने मार्च 2023 में अपनी पहली प्रेस ब्रीफिंग में अमरीका के बारे में अपने कठोर आकलन से कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था, भले ही अमरीका में राजदूत के रूप में उन्होंने कई समझौतावादी बयान दिए थे।

कई चीनी विद्वान चीन के अपरिहार्य उदय और अमरीका के पतन के लिए तर्क देते हैं। वे सत्ता परिवर्तन के लिए तर्क देते हैं जिसमें चीन अंततः उच्च पायदान पर कब्जा कर लेगा। वे सेनकाकू द्वीपों, दक्षिण चीन सागर विवाद या भारत-चीन सीमा प्रश्न पर चीन के आक्रामक रुख का उल्लेख किए बिना अमरीका की एकतरफा नीतियों, साम्राज्यवादी विस्तार और इस्लामी राज्यों में सॉफ्ट पावर के नुकसान की आलोचना करते हैं।

विद्वानों के विचार

लोकतंत्रों के विपरीत, चीन जैसे सत्तावादी पार्टी-राज्यों में, विद्वान समुदाय सत्ता प्रतिष्ठान की लाइन पर चलता है। वास्तव में, उनमें से अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं जो केंद्रीय समिति के फैसलों से जुड़े हैं। चीन में अकादमिक अनुसंधान प्रकृति में नीति उन्मुख है, कला पर 1942 की "यानान भावना" का पालन कला के लिए नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के लाभ के लिए। नीतिगत अंतर की एक संकीर्ण खिड़की मौजूद है, लेकिन सीमा पार करने के लिए प्रतिशोध विश्वविद्यालयों और थिंक-टैंक में विद्वानों को चुप कराने के लिए प्रभावी हैं। चीन में कई पार्टी समर्थित विद्वान भी शक्तियों के सलाहकार हैं। हू जिंताओ के समय से उन्हें आधिकारिक तौर पर पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति की बैठकों में अमरीका के साथ संबंधों सहित विशिष्ट विषयों पर ब्रीफिंग सत्र के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह प्रथा शी जिनपिंग के तहत जारी रखी गई थी जब चीन-अमरीका विवाद बढ़ गया था[92]। नीचे कुछ प्रमुख विद्वानों के विचार संक्षेप में दिए गए हैं जो चीन में अमरीका से संबंधित विषयों पर शोध-कार्य करते हैं।

कई चीनी विद्वान चीन के अपरिहार्य उदय और अमरीका के पतन के लिए तर्क देते हैं। वे सत्ता परिवर्तन के लिए तर्क देते हैं जिसमें चीन अंततः उच्च पायदान पर कब्जा कर लेगा। वे सेनकाकू द्वीपों, दक्षिण चीन सागर विवाद या भारत-चीन सीमा प्रश्न पर चीन के आक्रामक रुख का उल्लेख किए बिना अमरीका की एकतरफा नीतियों, साम्राज्यवादी विस्तार और इस्लामी राज्यों में सॉफ्ट पावर के नुकसान की आलोचना करते हैं[93]।
वे बल प्रयोग करके भी ताइवान पर चीन के "वैध" अधिकार के लिए तर्क देते हैं और ऐसे परिदृश्यों को अवरुद्ध करने के लिए अमरीका की आलोचना करते हैं। वे द्वीप विवाद पर कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की चिंता को अत्यधिक या अमेरिकी समर्थन से प्रेरित मानते हैं। वे चीन के बदलते "मूल हितों" को पवित्र मानते हैं और हर कीमत पर उनकी रक्षा करने की आवश्यकता है, हालांकि उन्हें अन्य एशियाई देशों के संप्रभुता के दावों पर कोई चिंता नहीं है। वे मानते हैं कि अमरीका बहुपक्षवाद और मुक्त व्यापार से पीछे हट गया है, भले ही वे चीन के विशेष बहुपक्षीय मुद्राओं का उल्लेख नहीं करते हैं और न ही डब्ल्यूटीओ नियमों के उल्लंघन में इसके संरक्षणवादी रुझानों का उल्लेख करते हैं। जबकि यान ज़ुएतोंग, वांग यिज़ौ, वांग यीवेई, शी यिनहोंग, नी लेशिओंग और अन्य को यथार्थवादी माना जाता है, वांग जिसी और जिनकैनरोंग चीन में सूक्ष्म "सामरिक अस्पष्टता" का हिस्सा हैं।

सिंघुआ विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में पढ़ाने वाले यान शुएतोंग को पश्चिमी विद्वानों द्वारा एक यथार्थवादी और चीनी सरकार के लिए "आक्रामक नीति सलाहकार" माना जाता है[94]। यान अमेरिकी नीतियों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि इससे वैश्विक स्थिरता कमजोर हुई है और चीन सहित अन्य देशों के साथ तनाव पैदा हुआ है[95]। यान का मुख्य तर्क यह है कि चीन वैश्विक शक्ति बनने के लिए कई संकेतकों में अमरीका के साथ "बराबर" कर रहा है। यान ने तर्क दिया कि 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से चीन की सापेक्ष वृद्धि और अमेरिकी गिरावट को चीन के राजनीतिक नेतृत्व की सुधार की क्षमता में देखा जा सकता है[96]। यान ने तर्क दिया कि"... चीन का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय संदर्भ पर निर्भर करेगा। युद्ध के समय में, इसे अपनी वर्चस्ववादी स्थिति को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए विश्वसनीय गठबंधन बनाने का प्रयास करना चाहिए। शांति के समय में, इसे एक मानवीय प्राधिकरण की तरह कार्य करने का प्रयास करना चाहिए"[97]। यान चीन में उन लोगों पर कटाक्ष करते हैं जो लाओ ज़ी के गैर-हस्तक्षेप दर्शन के अनुयायियों के रूप में अमरीका के साथ संघर्ष से बचना चाहते हैं[98]। यान ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वियतनामी या अन्य लोग चीन के कार्यों को वर्चस्ववादी क्यों मानते हैं। जबकि यान सोचते हैं कि अमरीका दुनिया भर में एकतरफा नीतियों का पालन कर रहा है, उन्हें नहीं लगता कि चीन अमरीका को हराने के लिए Asia.In में इसी तरह की एकतरफा नीतियों का पालन कर रहा है, यान का सुझाव है कि देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के अलावा, चीन को घरेलू और बाहरी दोनों तरह से "सामंजस्यपूर्ण विश्व" व्यवस्था को बढ़ावा देने और नैतिक शासन में भाग लेने के लिए एक उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए[99]। इसके अलावा, 1990 के दशक की बहुध्रुवीकरण की अवधारणा को खारिज करते हुए, यान ने तर्क दिया कि अमरीका और चीन के बीच द्विध्रुवी य प्रतिस्पर्धा 2019 के बाद से एक वास्तविकता है, और इस तरह की प्रतिस्पर्धा का मूल मुख्य रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकी में परिलक्षित होता है[100]। हालांकि, तर्क दिया कि 1990 के दशक की तुलना में जब वैश्विक उत्पादन में अमरीका का हिस्सा 26 प्रतिशत था, आज यह लगभग 25 प्रतिशत है, जबकि चीन का हिस्सा 1 से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया था। हाल ही में उन्होंने सुझाव दिया कि इस दशक में अमरीका की गिरावट संभव नहीं है[101]। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वर्तमान अवधि को "एक नए शीत युद्ध के बजाय असहज शांति" की विशेषता हो सकती है[102]।

बीजिंग विश्वविद्यालय के वांग यीझोऊ के अनुसार चीन ने कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है। चीन की व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को पहचानते हुए, अमरीका को ताइवान और अन्य मुद्दों पर चीन की मांगों को स्वीकार करना चाहिए। वांग ने तर्क दिया: "चीन को दूसरों के नीचे कैसे रखा जा सकता है, "दूसरों के पैरों के बीच रेंगने" का उल्लेख नहीं करना; विश्व मामलों के बढ़ते महत्व के बावजूद, आखिरकार, चीन पर केंद्रित पूर्व में सहायक प्रणाली बननी चाहिए, चीन मजबूत हो रहा है जबकि अन्य कमजोर हो रहे हैं; संप्रभुता विवाद में भूमि या पहले से ही कुछ वार्ताओं में दूसरों को आवंटित की गई भूमि, जल्द या बाद में मांग पर चीन को वापस कर दी जाएगी; संयुक्त राज्य अमरीका को अंततः चीन पर अपने सभी दिशात्मक अन्यायपूर्ण, अनुचित दबाव के लिए प्रतिशोध या सजा मिलेगी[103]।

पीपुल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले शी यिनहोंग ने सुझाव दिया कि राजनीतिक प्रणालियों, राष्ट्रीय प्रक्षेपवक्र, मूल्यों और हितों पर अमरीका और चीन के बीच मतभेदों को देखते हुए, दोनों देशों के बीच जुड़ाव प्रक्रिया की आवश्यकता है। वह अमेरिकी टैरिफ युद्धों के आलोचक हैं।

वांग जिसी का अमरीका के बारे में एक व्यावहारिक और बारीक दृष्टिकोण है, भले ही वह टैरिफ युद्धों पर अमरीका की आलोचना कर रहे थे, जो इसकी ताकत और कमजोरियों दोनों को पहचानते थे। वह मानते हैं कि अमरीका एक वैश्विक शक्ति है और इसकी अपरिहार्य गिरावट का आकलन गलत है[104]। वांग ने इस विचार को खारिज कर दिया कि अमरीका गिरावट की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने 2008 में सुझाव दिया था कि अमरीका 20-30 वर्षों तक एकमात्र महाशक्ति बना रहेगा[105]।

पीपुल्स यूनिवर्सिटी के अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग में पढ़ाने वाले जिन कैनरोंग अमरीका की एकतरफा नीतियों, सत्ता परिवर्तन और चीन के उदय में बाधा डालने के लिए उसकी आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि चीन और अमरीका को वार्ता प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए, एक दूसरे के साथ संवाद करना चाहिए और परमाणु अप्रसार वार्ता, आतंकवाद का मुकाबला करने और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के समाधान के माध्यम से वैश्विक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में चीन के उदय और अंततः अमरीका के विस्थापन की अनिवार्यता के लिए तर्क दिया।

नी लेशियोंग के अनुसार, अमरीका चीन को रोकने के लिए शीत युद्ध की रणनीति का पालन कर रहा है और प्रतिबंधों, सैन्य गठबंधनों को मजबूत करने, टैरिफ युद्ध और चीन को कमजोर करने के अन्य उपायों में परिलक्षित होता है। नी का मानना है कि अमरीका के साथ संबंधों में अविश्वास को दूर करने के लिए अमरीका के साथ सामरिक संचार आवश्यक है।

वांग यीवेई चीन के पड़ोस में अमेरिकी नीतियों और बीआरआई परियोजनाओं से संबंधित नीतियों के आलोचक रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अमरीका अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और सैन्य क्षेत्रों में चीन के साथ "सामरिक प्रतिस्पर्धा" का अनुसरण कर रहा है, लेकिन चाहता है कि दोनों "सामान्य आधार" तलाशें।

निष्कर्ष

अमरीका और चीन के बीच वर्तमान प्रतिस्पर्धा आर्थिक, तकनीकी, सैन्य और सामरिक क्षेत्रों में है। दोनों हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और फाइनेंस जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर हावी होने की योजना बना रहे हैं। दोनों देशों के बीच विवाद का एक अन्य क्षेत्र ग्लोबल कॉमन्स भी है। दोनों एशिया और उससे परे क्षेत्रीय अंतरिक्ष में भी हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की गहन प्रतिस्पर्धा का परिणाम शक्ति संतुलन, शक्ति संक्रमण और उभरती विश्व व्यवस्था में परिलक्षित होने की आशा है। कई विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि विभिन्न क्षेत्रों में अमरीका के साथ संघर्ष अपरिहार्य है और अमरीका द्वारा एक समझौता समाधान का सुझाव देते हैं[106]।

अमरीका-चीन प्रतिस्पर्धा के भारत सहित कई देशों के लिए निहितार्थ हैं। पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक दशक में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भारत आर्थिक, तकनीकी, सामरिक, सैन्य और वैश्विक तथा क्षेत्रीय क्षेत्रों में अमरीका और चीन के बीच उभरती प्रतिस्पर्धा के प्रति अभेद्य नहीं हो सकता। अमरीका और चीन दोनों के साथ भारत के संबंध सामरिक प्रकृति के हो गए हैं। हालांकि आज भारत के अमरीका के साथ कम मतभेद हैं, लेकिन क्षेत्रीय गतिरोध और एशिया और उससे परे चीन के आधिपत्य के दबाव का भारत के लिए बड़ा प्रभाव है। अमरीका-चीन प्रतिस्पर्धा से एशिया और उससे परे जगह सीमित होने की आशा है। इन परिस्थितियों में, शक्तियों का एक संगीत कार्यक्रम इस क्षेत्र को सामरिक स्थिरता प्रदान कर सकता है। भारत को एशिया में इस तरह के संतुलन के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। ◆

अमरीका-चीन संबंध

अस्थिर वर्तमान और परिवर्तनशील भविष्य

चिंतामणि महापात्रा

दुनिया को प्रभावित करने वाले गंभीर भू-राजनीतिक तनाव के बीच संयुक्त राज्य अमरीका-चीन संबंध आज बहुत अस्थिर हैं। जबकि अमेरिकियों ने सदियों से चीन को एक विशाल बाजार के रूप में देखा जो व्यापारियों और निवेशकों को लाभान्वित कर सकता है, उपनिवेशवाद के सुनहरे दिनों के दौरान अमेरिकी व्यवसायों को चीन में कोई भी लेनदेन करने से रोक दिया गया था। यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों ने चीन में प्रभाव के अलग-अलग क्षेत्रों की स्थापना की थी और किसी अन्य देश को अपने नियंत्रण और प्रभाव वाले क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति नहीं दी थी।

यह 20वीं शताब्दी के मोड़ पर था कि संयुक्त राज्य अमरीका एक युद्ध में स्पेन को हराकर और प्रशांत क्षेत्र में फिलीपींस के स्पेनिश उपनिवेश पर कब्जा करके एक नई औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। फिलीपींस पर कब्जा करने का वास्तविक अमेरिकी इरादा कभी भी व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना नहीं था। लक्ष्य इसे एक सामरिक आधार बनाना था जहां से अमरीका चीन में अमेरिकी व्यवसायों को पनपने की अनुमति देने के लिए चीन के लिए एक दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा। "ओपन डोर" नोट जो वाशिंगटन ने अमेरिकी व्यापारियों को अपने प्रभाव के क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए यूरोपीय शक्तियों को भेजा था, उसे खारिज कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध जीतने और वैश्विक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति स्थापित करने के बाद अमरीका ने एक बार फिर चीन में आर्थिक पैर जमाने की कोशिश की, लेकिन इस बार चीनी गृहयुद्ध आड़े आ गया। माओ त्से तुंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट ताकतों ने जनरल च्यांग काई शेक के नेतृत्व वाली अमरीका समर्थित राष्ट्रवादी ताकतों को हराया। और फिर राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने "साम्यवाद की रोकथाम" सिद्धांत को अपनाया, जो चीन के साथ व्यापार करने की किसी भी अमेरिकी इच्छा को विराम देता है।

शीत युद्ध के दौरान अमरीका-चीन व्यापार लगभग शून्य था और 1960 के दशक के अंत में निक्सन प्रशासन द्वारा माओ के चीन के साथ संबंध बनाने में सफल होने के बाद ही बदलना शुरू हुआ। प्रसिद्ध रणनीतिकार हेनरी किसिंजर द्वारा तैयार निक्सन प्रशासन का सामरिक लक्ष्य भारत-चीन में अमेरिकी हस्तक्षेप को समाप्त करना, चीनी सहयोग के साथ एशिया में सोवियत प्रभाव को रोकना और निश्चित रूप से, दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के साथ व्यापार करने से लाभ कमाने के लंबे समय से चले आ रहे सपने को साकार करना था। चीन के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से कई उतार-चढ़ाव के माध्यम से, अमरीका चीन-सोवियत दरार से लाभ उठाने में सक्षम था, अमरीका-चीन व्यापार, वाणिज्य और निवेश को बढ़ावा देने में सफल रहा, और चीनी घरेलू राजनीति को बदलने और नया रूप देने की महत्वाकांक्षा का मनोरंजन किया।

चीन के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से कई उतार-चढ़ाव के माध्यम से, अमरीका चीन-सोवियत दरार से लाभ उठाने में सक्षम था, अमरीका-चीन व्यापार, वाणिज्य और निवेश को बढ़ावा देने में सफल रहा, और चीनी घरेलू राजनीति को बदलने और नया रूप देने की महत्वाकांक्षा का उत्सव मनाया।

जबकि चीन के साथ व्यापार करने का अमेरिकी सपना आखिरकार सच हो गया है, चीन के साथ व्यापार घाटा संयुक्त राज्य अमरीका में झल्लाहट का एक लगातार स्रोत बन गया है।

आर्थिक प्रतियोगी के लिए व्यापार भागीदार

अपनी चीन नीति में संयुक्त राज्य अमरीका अमरीका का आर्थिक उद्देश्य एक शानदार सफलता की कहानी बन गया है। चीन संयुक्त राज्य अमरीका के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक बाजारों में से एक बन गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2021 में अमरीका-चीन व्यापार 657 अरब डॉलर से अधिक था। चीन दुनिया में अमेरिकी माल के आयात का सबसे बड़ा स्रोत था। इसके अलावा, 2021 तक चीन में कुल अमेरिकी निवेश $ 118 बिलियन डॉलर से अधिक था और संयुक्त राज्य अमरीका में चीनी निवेश $ 53 बिलियन से अधिक था[107]। जबकि चीन के साथ व्यापार करने का अमेरिकी सपना आखिरकार सच हो गया है, चीन के साथ व्यापार घाटा संयुक्त राज्य अमरीका में झल्लाहट का एक लगातार स्रोत बन गया है। चीन अमरीका से जितना सामान खरीदता है, उससे तीन गुना ज्यादा सामान बेचता है। अमेरिकी सांसद समय-समय पर चीन की तुलना में बढ़ते व्यापार घाटे की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। 'आर्थिक संबंधों में विषमताओं' पर चिंता और अमरीका की 'प्रतिस्पर्धात्मकता, राष्ट्रीय सुरक्षा और नेतृत्व[108]' को प्रभावित करने वाली चीनी आर्थिक प्रथाओं पर आशंकाएं अमरीका -चीन द्विपक्षीय संबंधों में एक मजबूत अड़चन बन गई हैं। जबकि ट्रम्प प्रशासन ने सचमुच चीन से अरबों डॉलर के आयात पर टैरिफ बढ़ाकर चीन के खिलाफ एक आर्थिक शीत युद्ध शुरू किया और बीजिंग की जवाबी कार्रवाई को उकसाया, उत्तराधिकारी बाइडन प्रशासन ने चीन के प्रति सख्त ट्रम्प आर्थिक नीति को बदलने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। वाशिंगटन ने चीनी सरकार पर "जबरन प्रौद्योगिकी हस्तांतरण" में शामिल होने, अमेरिकी व्यापार रहस्यों को चुराने, "भेदभावपूर्ण लाइसेंसिंग प्रथाओं" और "अमेरिकी संपत्तियों के राज्य वित्त पोषित सामरिक अधिग्रहण" में शामिल होने का आरोप लगाया है[109]।

अमरीका के नीति निर्माण हलकों में प्रमुख आर्थिक चिंताएं इस तथ्य से उत्पन्न होती हैं कि चीन अधिकांश अमेरिकी सहयोगियों का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है; उसने सड़क, वायु, जल, ऊर्जा और साइबर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स (बीआरआई) के तहत समझौतों पर हस्ताक्षर करके लगभग 149 देशों पर अपना आधिपत्य नियंत्रण बढ़ाया है, ताइवान का समर्थन करने वाले देशों को दंडित करने के लिए अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल किया है, उन देशों पर जुर्माना लगाया है जो उस पर

कोविड-19 वायरस को फैलाने का आरोप लगाते हैं; और, सबसे महत्वपूर्ण बात, कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित चीनी राज्य चीन के साथ-साथ विदेशों में सभी आर्थिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है।

अमरीकी लोकतांत्रिक राजनीति आज सत्तावादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रही है।

चीन, अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदकर संयुक्त राज्य अमरीका के लिए नंबर एक बैंकर और संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अंतरराष्ट्रीय संगठनों में एक बढ़ता प्रभावकर्ता और दुनिया के प्रमुख दाता देशों में से एक होने के नाते, अमरीका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था के लिए मजबूत चुनौतियां पेश करता है और मुकाबला करने की धमकी देता है। दुनिया के कई हिस्सों से अमेरिकी प्रभाव को कम करना या बदलना। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी एकमात्र निर्णय निर्माता है और विदेशों में अपने हितों को आक्रामक रूप से बढ़ावा देने के लिए देश की वित्तीय ताकत को सिंक्रनाइज़ करती है। यह अमेरिकी प्रणाली से काफी अलग है जहां अमेरिकी सरकार का निगमों और कंपनियों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं है। कच्चे माल, हाइड्रोकार्बन संसाधनों की भारी मात्रा में खरीदकर; कई देशों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण, और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में कई विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना, चीन ने दुनिया में पारंपरिक अमेरिकी प्रभाव का मुकाबला किया है। अमेरिकी लोकतांत्रिक राजनीति आज सत्तावादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रही है। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमरीका में चीन की आर्थिक जासूसी संयुक्त राज्य अमरीका के लिए एक और बड़ी चिंता है। 2018 में एक रिपोर्ट में, संघीय जांच ब्यूरो ने कहा कि "चीनी सरकार ने ऐतिहासिक रूप से आर्थिक जासूसी को प्रायोजित किया है, और चीन बौद्धिक संपदा अधिकारों का दुनिया का प्रमुख उल्लंघनकर्ता है। नकली सामान, पायरेटेड सॉफ्टवेयर और व्यापार रहस्यों के खतरे की अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए वार्षिक लागत $ 225 बिलियन से $ 600 बिलियन के बीच है[110]।

बढ़ती प्रतिद्वंद्विता के लिए सामरिक साझेदारी

यद्यपि डेमोक्रेटिक यूएसए चीनी गृहयुद्ध की समाप्ति के बाद शुरुआती वर्षों में कम्युनिस्ट चीन को विकसित करने में विफल रहा, लेकिन इसने चुपचाप चीन-सोवियत सहयोग में दरार लाने और सोवियत प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बीजिंग के साथ साझेदारी बनाने के लिए काम किया। हेनरी किसिंजर की कूटनीति ने फल दिया और चीन ने खुद को पूर्व सोवियत संघ के खिलाफ शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता में संयुक्त राज्य अमरीका के सामरिक भागीदार के रूप में पाया। सोवियत प्रभाव का मुकाबला करने के लिए चीनी आर्थिक ताकत बनाने में वाशिंगटन का एक सामरिक लक्ष्य था। इसके अलावा, एक छिपा हुआ अमेरिकी विश्वास यह था कि एक दोस्ताना और आर्थिक रूप से समृद्ध चीन अमरीका के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था में एक

हितधारक बन जाएगा। लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि सामरिक साझेदारी ने अपनी सीमाएं देख ली हैं और आज चीन को पहले से ही अमेरिकी नीति निर्माताओं द्वारा एक सामरिक प्रतियोगी के रूप में माना जाता है। 2022 की अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति रिपोर्ट कहती है: "पीआरसी एकमात्र प्रतियोगी है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से आकार देने के इरादे से है, और तेजी से... इसे करने की शक्ति[111]। माना जाता है कि चीन की महत्वाकांक्षा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने और दुनिया की अग्रणी शक्ति बनने की है[112]। अमेरिकी राष्ट्रीय-साइबर सुरक्षा-रणनीति रिपोर्ट, 2023 में यह भी बताया गया है कि "पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) अब सरकारी और निजी क्षेत्र के नेटवर्क दोनों के लिए व्यापक, सबसे सक्रिय और सबसे लगातार खतरा प्रस्तुत करता है" और "अमेरिकी हितों को खतरे में डालने की क्षमता" के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को फिर से आकार देने का इरादा और शक्ति दोनों है[113]।

चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत और सैन्य शक्ति के बारे में पिछले कुछ दशकों से अमरीका में सामरिक हलकों के बीच बहस और चर्चा के बावजूद, चीन की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रोफ़ाइल और प्रभाव पर सरकारी चिंताएं हाल तक खुले तौर पर सतह पर नहीं आईं। संबंधों में उतार-चढ़ाव आए हैं और वाशिंगटन और बीजिंग अंतरराष्ट्रीय मामलों में कई मुद्दों पर विपरीत पक्ष में खड़े हैं और चीन के हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी जासूसी विमान और एक चीनी विमान की टक्कर पर झगड़ते हैं; बेलग्रेड में चीनी दूतावास परिसर पर दुर्घटनावश अमेरिकी बमबारी, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में चीन का मुखर व्यवहार और संप्रभुता का दावा, अनुचित व्यापार प्रथाएं, बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन, मानवाधिकारों का उल्लंघन, चीनी नागरिकों द्वारा व्यापार रहस्यों की चोरी आदि। लेकिन अमेरिकी हितों और दुनिया में स्थिति के लिए चीन का खतरा तब बढ़ने लगा जब ट्रम्प प्रशासन ने शीर्ष आधिकारिक सरकारी रिपोर्टों में इसे उजागर किया। उदाहरण के लिए, 2017 में जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस की चिंता को प्रतिबिंबित किया कि "चीन और रूस अमेरिकी मूल्यों और हितों के खिलाफ दुनिया को आकार देना चाहते हैं" और "चीन हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमरीका को विस्थापित करना चाहता है, अपने राज्य-संचालित आर्थिक मॉडल की पहुंच का विस्तार करना चाहता है और क्षेत्र को अपने पक्ष में पुनर्व्यवस्थित करना चाहता है[114]। रिपोर्ट में कहा गया है, "दशकों से, अमेरिकी नीति इस विश्वास में निहित थी कि चीन के उदय के लिए समर्थन... चीन को उदार बनाएंगे। हमारी आशा के विपरीत, चीन ने दूसरों की संप्रभुता की कीमत पर अपनी शक्तियों का विस्तार किया[115]।

अमेरिकी हितों और दुनिया में स्थिति के लिए चीन का खतरा तब बढ़ने लगा जब ट्रम्प प्रशासन ने शीर्ष आधिकारिक सरकारी रिपोर्टों में इसे उजागर किया। उदाहरण के लिए, 2017 में जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति रिपोर्ट ने व्हाइट हाउस की चिंता को प्रतिबिंबित किया कि "चीन और रूस अमेरिकी मूल्यों और हितों के खिलाफ दुनिया को आकार देना चाहते हैं"।

यूक्रेन युद्ध और इसके प्रभाव

रूस-यूक्रेन युद्ध का समकालीन चीन के बारे में अमेरिकी धारणा पर बहुत प्रभाव पड़ा है। घटनाओं के दिलचस्प मोड़ में, अमरीका ने पहली बार शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान सोवियत और चीनी साम्यवाद दोनों को रोकने के लिए दोहरी नियंत्रण रणनीति बनाई थी; बाद में, अमेरिकी रणनीति ने चीन-सोवियत मतभेदों का भारी राजनीतिक लाभ उठाया; और 1960 के दशक के अंत तक चीन-अमेरिकी अलगाव का उद्देश्य चीन-सोवियत दरार को और गहरा करना था। 1980 के दशक तक, अमरीका के पास चीन को मजबूत करने और सोवियत विस्तारवाद के खिलाफ भागीदार बनाने की नीति थी। 1970 के दशक के मध्य में भारत-चीन से अमरीका की वापसी, 1970 के दशक के अंत में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण और 1970 के दशक के अंत में कंबोडिया में वियतनामी सैन्य हस्तक्षेप ने संयुक्त राज्य अमरीका और चीन के बीच संबंधों को और गहरा कर दिया।

जैसे-जैसे समय नजदीक आ रहा है, आज द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद के सामरिक परिदृश्य के पुनरुद्धार को देखा जा सकता है और एक बार फिर रूस और चीन ने घनिष्ठ ऊर्जा और रक्षा सहयोग बनाया है और अमरीका ने संयुक्त रूस-चीनी सामरिक साझेदारी से खतरे को महसूस करना शुरू कर दिया है। संयुक्त राज्य अमरीका के लिए, यूरोप और भारत-प्रशांत क्षेत्र दोनों इसकी सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। रूस एक मुखर नीति का पालन करके यूरोपीय सामरिक परिदृश्य को चुनौती दे रहा है, जैसा कि जॉर्जियाई संघर्ष, क्रीमिया पर उसके रुख में परिलक्षित होता है और चीन हिंद-प्रशांत में अपनी मुखर नीति से अमेरिकी आधिपत्य के लिए खतरा रहा है।

बाइडन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन के खतरे के आकलन के साथ कदम रखा है।

इस प्रकार ट्रम्प प्रशासन ने अपने वैश्विक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चीनी प्रतिस्पर्धा देखी और टैरिफ युद्ध शुरू करके चीन पर आर्थिक लागत लगाकर इसे रोकने के लिए कदम उठाए। बाइडन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन के खतरे के आकलन के साथ कदम रखा है। हालांकि, यूक्रेन में रूस के सैन्य हस्तक्षेप ने रूस-चीनी राजनीतिक मिलनसारिता और सामरिक साझेदारी के साथ संयुक्त राज्य अमरीका की खतरे की धारणा को और बढ़ा दिया है। जैसा कि बाइडन प्रशासन ने रूस पर प्रतिबंध लगाकर, यूक्रेन को परिष्कृत सैन्य उपकरण और गोला-बारूद प्रदान करके, रूसी सीमा के साथ फिनलैंड को शामिल करने के लिए नाटो के आगे विस्तार का समर्थन करके और नाटो की एकता, कौशल और संकल्प को बहाल करके यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ एक छद्म युद्ध शुरू किया, चीन निश्चित रूप से खुले तौर पर यूक्रेन में रूसी सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन किए बिना रूस के साथ खड़ा रहा। यूक्रेन पर हमला करने से कुछ हफ्ते पहले, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ओलंपिक खेलों के उद्घाटन को देखने के लिए बीजिंग का दौरा किया और रूस और चीन के बीच

"असीम" सहयोग की घोषणा के साथ लौट आए। इससे अमरीका में संदेह पैदा हो गया है कि पुतिन और शी जिनपिंग यूक्रेन युद्ध में एक साथ हैं, जो एक परिणामी युद्ध बन गया है और यूरोप में सामरिक परिदृश्य को फिर से आकार देता प्रतीत होता है। कई अन्य देशों की तरह, चीन ने रूसी आक्रमण की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रस्तावों से परहेज किया, रूस के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रतिबंधों का समर्थन नहीं किया, रूस के साथ व्यापारिक गतिविधियां जारी रखीं और अपना विचार व्यक्त किया कि पुतिन को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए रक्षात्मक उपाय करने के लिए पश्चिमी नीतियों द्वारा उकसाया गया था।

चीन ने न तो रूस को हथियारों की आपूर्ति की है और न ही यूक्रेन में उसकी सैन्य गतिविधियों का विरोध किया है। इसने परमाणु हथियारों पर रूसी बयानों के सामने परमाणु हथियारों के उपयोग का काफी विरोध किया है, जिसका वर्तमान भू-राजनीति में व्यापक प्रभाव है। अमरीका अभी भी आश्वस्त दिखाई दे रहा है कि चीन रूस का पक्ष ले रहा है। अगर चीन-अमरीका व्यापार संघर्ष नहीं हुआ होता और ट्रंप प्रशासन ने चीन के 'रचनात्मक जुड़ाव' के मंत्र को दोहराया होता, तो यूक्रेन मुद्दे पर चीन क्या नीति अपनाता, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। लेकिन चीन के प्रति ट्रम्प प्रशासन द्वारा अपनाए गए कठोर रुख और बाइडन प्रशासन द्वारा जारी ने निश्चित रूप से चीन को यूक्रेन युद्ध के लिए एक सूक्ष्म दृष्टिकोण रखने के लिए प्रेरित किया। यूक्रेन युद्ध से पहले, चीन-अमरीका सामरिक विचलन पहले से ही व्यापक हो रहे थे। जब पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप समूह के पास चीनी जहाज बार-बार दिखाई देते हैं, तो अमरीका जापान का समर्थन करता है, वाशिंगटन दक्षिण चीन सागर में पानी के विशाल हिस्सों पर संप्रभुता के चीनी दावे का जोरदार विरोध करता है, पेंटागन अक्सर प्रशांत क्षेत्र में चीन में और उसके आसपास नौसैनिक गश्त करता है, विदेश विभाग परमाणु और मिसाइल परीक्षणों पर उत्तर कोरिया पर दबाव डालने के लिए चीनी हिचकिचाहट के अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करता है और, ज़ाहिर है, अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ लगातार अपनी चिंताओं को आवाज देता है। दूसरी ओर, रूस और चीन के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेदों के बावजूद बहुत कम तकरार हुई है और इसके बजाय शंघाई सहयोग संगठन जैसे क्षेत्रीय तंत्र के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए उनके दृष्टिकोण का समन्वय किया गया है।

इस प्रकार वाशिंगटन यह आशा नहीं कर सकता था कि चीन यूक्रेन मुद्दे पर अपनी नीति का पालन करेगा। यूक्रेन युद्ध में चल रहे छद्म युद्ध के बीच चीन खुद को शांतिदूत के रूप में पेश करना चाहता है। चीन ने हाल ही में सऊदी-ईरान संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे संयुक्त राज्य अमरीका और अन्य जगहों पर भौंहें तन गई हैं। संयुक्त राज्य अमरीका के भीतर कई विश्लेषकों ने इस विकास को पश्चिम एशियाई राजनीति में अमेरिकी भूमिका के हाशिए के रूप में देखा। पश्चिम एशियाई शांति पहल में चीन की भूमिका का असर अमरीका में गहराई से महसूस किया गया और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक टिप्पणी में कहा गया, "अमेरिकी, जो पिछली तीन-चौथाई सदी से मध्य पूर्व में केंद्रीय नायक रहे हैं, लगभग हमेशा उस कमरे में जहां यह हुआ था, अब महत्वपूर्ण बदलाव के क्षण के दौरान खुद को किनारे पर पाते हैं। चीन, जिन्होंने वर्षों तक इस क्षेत्र में केवल एक द्वितीयक भूमिका निभाई थी, ने अचानक खुद को नए शक्ति नायक में बदल दिया है[116]।

यूक्रेन में छद्म युद्ध जारी रहने के बीच चीन खुद को कथित अमेरिकी आक्रामकता के विपरीत शांतिदूत के रूप में पेश करना चाहता है।

सऊदी क्राउन प्रिंस की कथित भूमिका के साथ सऊदी भूमि में एक अमेरिकी पत्रकार की हत्या के बाद से अमरीका-सऊदी संबंध पहले से ही बाधित थे और परमाणु मुद्दे पर जेसीपीओए में लौटने के लिए अमरीका-ईरान संबंध कहीं भी खत्म नहीं हो रहे थे। फिर भी, बाइडन प्रशासन ने चीन की भूमिका को तवज्जो नहीं दी. एक प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि यह केवल दूतावासों को फिर से खोलने के लिए एक समझौता था और कोई "शांति संधि" नहीं थी[117]। पश्चिम एशिया में अपने शांति उद्यम के तुरंत बाद, राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मास्को का दौरा किया और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए 12-सूत्री शांति योजना का प्रस्ताव रखा। राष्ट्रपति बाइडन ने तुरंत कहा, "मैंने योजना में ऐसा कुछ नहीं देखा है जो यह संकेत दे कि रूस के अलावा किसी और के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने आगे कहा कि "यह विचार कि चीन एक युद्ध के परिणाम पर बातचीत करेगा जो यूक्रेन के लिए पूरी तरह से अन्यायपूर्ण युद्ध है, तर्कसंगत नहीं है[118]। चीन ने अब तक रूस को हथियार बेचने से परहेज किया है। अमरीका यूक्रेन को सैन्य और भौतिक सहायता प्रदान करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करना जारी रखता है। अपने नाटो सहयोगियों से विमान और टैंक सहित यूक्रेन को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए कहते हुए, वाशिंगटन बीजिंग से मास्को की सैन्य सहायता नहीं करने का आह्वान करता है। चीन अब तक ऐसा करने से बचता रहा है, लेकिन वह रूस को सैन्य रूप से समर्थन देना शुरू करेगा या नहीं, यह आने वाले महीनों और वर्षों में अमरीका-चीन संबंधों की स्थिति पर निर्भर करेगा।

राष्ट्रपति बाइडन ने तुरंत कहा, "मैंने योजना में ऐसा कुछ नहीं देखा है जो यह संकेत दे कि रूस के अलावा किसी और के लिए फायदेमंद होगा।

लेकिन सबसे गंभीर अमेरिकी कार्रवाई जो बीजिंग को गंभीर रूप से परेशान करती है, वह ताइवान के साथ वाशिंगटन के जटिल और निरंतर संबंध हैं।

ताइवान-फ्लैश पॉइंट

ताइवान 1949 में कम्युनिस्ट जीत और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना के साथ चीनी गृह युद्ध की समाप्ति के बाद से अमरीका-चीन संबंधों में एक फ्लैशपॉइंट बना हुआ है। च्यांग काई-शेक के नेतृत्व में चीनी राष्ट्रवादी, ताइवान भाग गए और चीन के सही शासक के रूप में दावा किया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मान्यता के साथ एक स्वतंत्र देश स्थापित करने में विफल रहे। हालांकि, संयुक्त राज्य अमरीका ने ताइपे में सरकार को

चीन की सरकार के रूप में मान्यता देना जारी रखा। वाशिंगटन ने संयुक्त राष्ट्र में ताइपे के प्रतिनिधित्व का समर्थन किया, न कि बीजिंग का। यह चीन- अमरीका संबंध, "एक चीन नीति" को मान्यता देने वाले समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद ही समाप्त हुआ। अमेरिकी कांग्रेस ने 1979 ताइवान संबंध अधिनियम लागू किया और वाशिंगटन आज तक ताइवान के साथ अन्य क्षेत्रों में आर्थिक, सुरक्षा और सहयोग बनाए रखता है। अमरीका और चीन के बीच बनी सहमति के अनुसार, अमरीका दो प्रणालियों के साथ एक चीन के अस्तित्व को तब तक मान्यता देगा जब तक कि ताइवान का चीन के साथ एकीकरण केवल शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं हो जाता। इस प्रकार अमरीका लगातार कहता रहा है कि एकीकरण में बल का कोई उपयोग नहीं होना चाहिए और यह किसी भी बाहरी आक्रमण के खिलाफ खुद की रक्षा करने के लिए ताइवान की सहायता करेगा। अमरीका सैद्धांतिक रूप से चीन के इस रुख का विरोध करता है कि उसे बल प्रयोग करके मातृभूमि को एकजुट करने का अधिकार है। दूसरी ओर, चीन हमेशा कहता है कि केवल एक चीन है, कि ताइवान चीन का हिस्सा है और यह देश को एकजुट करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो बल का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विदेश नीति के लिए एक बलपूर्वक दृष्टिकोण अपनाया है, चीन की संप्रभुता के दावों पर जोर देने के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया है, छोटे देशों को डराने के लिए और यदि आवश्यक हो, तो ताइवान को बलपूर्वक हड़पने की कसम खाई है।

यहां संयुक्त राज्य अमरीका और चीन के बीच तनाव का मूल कारण है। अमरीका समय-समय पर ताइवान को उसकी रक्षा के लिए सैन्य हथियारों, विमानों और गोला-बारूद की आपूर्ति करता है। चीन अमरीका और ताइवान के बीच इस सुरक्षा संबंधों का पुरजोर विरोध करता है। ऐसे कई मौके आए हैं जब ताइवान के मुद्दे पर अमरीका-चीन के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, जिससे खुले सशस्त्र संघर्ष हो सकते हैं। अमरीका और चीन के बीच शीत युद्ध के समय की सामरिक समझ सोवियत संघ के अंत के बाद पांच साल से भी कम समय में परीक्षण के दायरे में आई। ताइवान जलडमरूमध्य को 1995-96 में चीनी सैन्य गतिविधियों के साथ संभावित सशस्त्र संघर्ष का सामना करना पड़ा। बिल क्लिंटन प्रशासन ने 1996 में चीनी आक्रामक सैन्य युद्धाभ्यास के सामने ताइवान की रक्षा के लिए विमान वाहक भेजा था[119]। उस समय चीन पीछे हट गया था। अमरीका उस समय एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था चला रहा था और चीन की सैन्य क्षमताएं इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की तुलना में सीमित थीं।

आज और चीन की आर्थिक उपलब्धियों और सैन्य आधुनिकीकरण में तेजी से आगे बढ़ना एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया है जहां चीन लगभग खुले तौर पर अमेरिकी शक्ति और आधिपत्य का मुकाबला करता है। चीन की नजर कभी भी ताइवान से दूर नहीं रही है और इसे मुख्यभूमि के साथ मिलाने की महत्वाकांक्षा हमेशा मेज पर रही है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विदेश नीति के लिए एक बलपूर्वक दृष्टिकोण अपनाया है, चीन की संप्रभुता के दावों पर जोर देने के लिए सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया है, छोटे देशों को डराने के लिए और यदि आवश्यक

हो, तो ताइवान को बलपूर्वक हड़पने की कसम खाई है। हाल ही में, महामारी के बीच, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग बल का उपयोग करने, ताइवान पर कब्जा करने और इसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक प्रांत बनाने के लिए बहुत उत्साहित दिखाई दिए। लगभग 149 चीनी लड़ाकू विमानों ने अक्तूबर 2021 के पहले सप्ताह में 4 दिनों में ताइवान के हवाई क्षेत्र के करीब उड़ान भरी और ताइवान को एक स्वतंत्र स्थिति की आकांक्षा न करने के लिए कड़ी चेतावनी जारी की[120]। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ताइवान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के लिए अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है, अगर ताइपे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेगा। चीन ने 1949 के बाद से कई बार ऐसी धमकियां दी हैं। लेकिन चीनी जुझारू सैन्य मुद्राएं कभी भी इतनी डरावनी नहीं थीं जितनी इस बार थीं।

संयुक्त राज्य अमरीका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि ताइवान से चीनी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ प्रतिक्रिया तेज थी और संभावित युद्ध पर चिंताएं थीं। चीन ने ऐसा क्यों किया? सबसे पहले, दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी। दूसरे, चीन के घरेलू विकास को शायद एक आउटलेट की आवश्यकता थी। ऊर्जा की कमी, आर्थिक गतिविधियों में मंदी, आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान और रियल एस्टेट ऋण संकट का मतलब है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग देश में असंतुष्ट जनता का ध्यान हटाने के लिए बाहरी रोमांच की तलाश कर रहे थे। शिनजियांग में उइगर मुस्लिम जनता के साथ व्यवहार, हांगकांग में लोकतांत्रिक राजनीति के विनाश[121], तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं का निरंतर दमन, दक्षिण चीन सागर में द्वीपों का अतिक्रमण, पूर्वी चीन सागर में बार-बार जापानी विरोधी नौसेना अभियान, और भारत के साथ सीमाओं पर शक्ति प्रदर्शन के खिलाफ वैश्विक आलोचना से दुनिया में चीनी छवि पहले से ही धूमिल हो रही थी। राष्ट्रपति शी की महत्वाकांक्षी मेगा परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को भी कुछ देशों में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। यह बहुत संभव था कि राष्ट्रपति शी ने ताइवान को अपने शब्दों में "एकीकरण" पर कब्जा करने की योजना बनाई थी- घर पर अपनी छवि को मजबूत करने के लिए, और फिर पार्टी और देश पर अपने सत्तावादी नियंत्रण को बनाए रखने के लिए। ताइवान मुद्दे पर एक अस्पष्ट सामरिक स्थिति बनाए रखने वाला संयुक्त राज्य अमरीका बाइडन प्रशासन के तहत ताइवान की रक्षा में अधिक आगे था।

सितंबर 2022 में, सीबीएस टेलीविजन को दिए एक साक्षात्कार में, राष्ट्रपति बाइडन ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि अगर कोई "अभूतपूर्व हमला" होता है, तो अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी।

अमरीका ने कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध और अफगान युद्ध अकेले नहीं लड़ा है। और वह अकेले चीन के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा। यदि जापान और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमरीका में शामिल हो जाते हैं, तो उनकी संयुक्त ताकत ताइवान में चीनी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ एक विश्वसनीय निवारक हो सकती है।

अमेरिकी नीति निर्माता समझते हैं कि ताइवान पर जबरन कब्जा करने में चीन की सफलता के कई प्रतिकूल प्रभाव होंगे। सबसे पहले, यह चीन की शक्ति प्रोफ़ाइल को बढ़ाएगा और इसे एक विश्वसनीय महाशक्ति बनाएगा। दूसरा, हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर चीन के वर्चस्व को कोई चुनौती नहीं मिलेगी। तीसरा, दक्षिण चीन सागर सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए चीनी झील बन सकता है। चौथा, चीन की राष्ट्रीय संपत्ति में काफी वृद्धि होगी, अगर कोई हांगकांग और ताइवान की संपत्ति को जोड़ देगा। अंत में, और महत्वपूर्ण रूप से, यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमरीका की शक्ति और प्रभाव के लिए एक बड़ा झटका होगा।

राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक से अधिक बार कहा है कि वह किसी भी हमले के खिलाफ ताइवान की रक्षा करेंगे। सितंबर 2022 में, सीबीएस टेलीविजन को दिए एक साक्षात्कार में, राष्ट्रपति बाइडन ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि अगर कोई "अभूतपूर्व हमला" होता है, तो अमेरिकी सेना ताइवान की रक्षा करेगी[122]। यद्यपि, संयुक्त राज्य अमरीका दशकों से ताइवान को हथियार दे रहा है और ताइवान के पास एक परिष्कृत सैन्य मशीन है, लेकिन यह वर्तमान चीनी सैन्य क्षमताओं का कोई मुकाबला नहीं है। शी जिनपिंग ने इसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया है और पीआरसी की स्थापना के सौ साल पहले निश्चित रूप से ताइवान को चीन का हिस्सा बनाने की समय सीमा है। हालांकि, अमरीका के पास ताइवान की रक्षा करने का मुश्किल काम है अगर एक अत्यधिक आधुनिक चीनी सेना बल का उपयोग करेगी।

यूक्रेन पर रूसी आक्रमण ने अटकलों को जन्म दिया कि चीन ताइवान में यूक्रेन को फिर से लागू करने की कोशिश कर सकता है। यदि अमरीका यूक्रेन का समर्थन करके रूसी को पर्याप्त रूप से नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होगा, तो यह ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन के मनोबल को बढ़ा सकता है। चीन रूस की ताकत, बड़े पैमाने पर पश्चिमी प्रतिबंधों से रूसी अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान और ताइवान पर कब्जा करने के लिए भविष्य में किसी भी सैन्य उपयोग की लागत और लाभ की सामरिक गणना कर रहा है।

संयुक्त राज्य अमरीका, आधुनिक चीनी सैन्य और परमाणु हथियार क्षमताओं और "हिंद-प्रशांत में संयुक्त राज्य अमरीका को प्रतिस्थापित करने की बीजिंग की महत्वाकांक्षा" से चिंतित है, ताइवान में बल का उपयोग करने के चीनी संकल्प का परीक्षण कर रहा है। चीन की बार-बार चेतावनी के बावजूद अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया और राष्ट्रपति साई इंग-सेन के साथ चर्चा की[123]। व्हाइट हाउस ने पेलोसी को अपनी यात्रा रद्द करने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए और चीन ने यह प्रदर्शित करने के लिए अभूतपूर्व सैन्य लाइव-फायर अभ्यास के साथ उत्तर दिया कि ताइवान को पूरी तरह से अवरुद्ध किया जा सकता है। हालांकि, चीन ने ताइवान पर आक्रमण नहीं किया और अमरीका ने चीन के साथ युद्ध के लिए उकसाया नहीं। ऐसा लग रहा था कि यह अमरीका के लिए चीन के संकल्प का आकलन करने के लिए एक परीक्षण गुब्बारा था। अमरीका इतने पर ही नहीं रुका। वर्तमान प्रतिनिधि सभा के नए रिपब्लिकन स्पीकर केविन मैकार्थी ने कैलिफोर्निया में ताइवान के राष्ट्रपति से मिलने का फैसला किया। चीन ने फिर से ऐसी बैठक के खिलाफ चेतावनी जारी की[124]। लेकिन बैठक हुई और चीन ने एक बार फिर लाइव-फायर सैन्य अभ्यास करके ताइवान को धमकी दी। कोई युद्ध नहीं था।

फिर भी, सबसे बड़ा प्रश्न यह है: क्या संयुक्त राज्य अमरीका ताइवान पर चीन के साथ युद्ध का जोखिम उठाएगा? यदि ऐसा होता है, तो क्या जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमेरिकी सहयोगी चीन के खिलाफ और ताइवान के लिए अमरीका के पक्ष में होंगे? अमरीका ने कोरियाई युद्ध, वियतनाम युद्ध और अफगान युद्ध अकेले नहीं लड़ा है। और वह अकेले चीन के साथ युद्ध नहीं लड़ेगा। यदि जापान और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमरीका में शामिल हो जाते हैं, तो उनकी संयुक्त ताकत ताइवान में चीनी सैन्य कार्रवाई के खिलाफ एक विश्वसनीय निवारक हो सकती है। चीन ने हांगकांग के साथ जो किया उस पर अगर ब्रिटेन अपनी खीझ निकालना चाहता है तो वह अमरीका का भी साथ दे सकता है। हालांकि, प्रश्न यह है: क्या ये सभी देश ताइवान की रक्षा के लिए चीन के साथ अपने आर्थिक संबंधों को जोखिम में डालेंगे? ये सभी देश लोकतंत्र हैं और इनमें से प्रत्येक देश में युद्ध पर निर्णय लेना एक जटिल खेल होगा। चीन एक अधिनायकवादी राज्य है और निर्णय लेना आसान होगा और इस प्रकार यह अन्य लोकतंत्रों के लिए चिंता का कारण होगा।

राष्ट्रपति शी खुद जानते हैं कि ताइवान पर किसी भी सैन्य आक्रमण से अन्य देशों के साथ पूर्ण पैमाने पर युद्ध हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव बहुत अधिक होगा और यहां तक कि आर्थिक परिणाम भी चीन के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। संयुक्त राज्य अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि यूरोपीय संघ की प्रतिक्रियाएं आर्थिक खतरे का प्रमाण हैं, जिससे राष्ट्रपति शी को निपटना होगा, अगर वह हवाई क्षेत्र के उल्लंघन से परे ताइवान स्ट्रेट में तनाव बढ़ाते हैं और वाकयुद्ध में शामिल होते हैं। प्रमुख शक्तियों में से कोई भी स्पष्ट कारणों से ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है: इसका मतलब आकर्षक चीनी बाजार में व्यवसाय खोना होगा। लेकिन अगर चीन ताइवान पर हमला करता है और उस पर कब्जा कर लेता है, तो कोई भी बड़ी शक्ति असहाय दर्शक होने की संभावना नहीं है। अमरीका और उसके सहयोगियों ने उइगर और तिब्बतियों के साथ चीनी दुर्व्यवहार और हांगकांग में लोकतंत्र की मौत को बर्दाश्त किया है, लेकिन अगर ताइवान को सैन्य रूप से कब्जा कर लिया जाता है तो वे चुप रहने की संभावना नहीं रखते हैं। चूंकि चीन के अगले कदम को लेकर हमेशा आश्चर्य की स्थिति बनी रहती है, इसलिए ताइवान में चिंता और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तनाव बरकरार रहेगा।

ट्रंप प्रशासन ने 2020 के दशक की शुरुआत से पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले कोविड-19 वायरस के बारे में दुनिया को संवेदनशील बनाने में चीन की विफलता को भी पेश करने की कोशिश की।

सॉफ्ट पावर का टकराव

हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका के बीच सूक्ष्म संघर्ष का एक और क्षेत्र सॉफ्ट पावर के क्षेत्र में रहा है। अमेरिकी सॉफ्ट पावर और गैर-लोकतांत्रिक देशों सहित दुनिया भर में इसका प्रभाव अच्छी तरह से जाना जाता है। लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का उपयोग संयुक्त राज्य

अमरीका द्वारा दशकों तक कम्युनिस्ट अधिनायकवाद को कमजोर करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में किया गया था। चीन के साथ वाणिज्यिक संबंध स्थापित करते समय, अमेरिकी विदेश विभाग और कुछ हद तक अमेरिकी कांग्रेस ने कभी-कभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए और कभी-कभी वाणिज्यिक कारणों से भी चीन के खिलाफ मानवाधिकार कार्ड खेलना जारी रखा, ताकि अमेरिकी लोगों को जबरन श्रम से रंगे चीनी उत्पादों को खरीदने के लिए हतोत्साहित किया जा सके।

ट्रंप और बाइडन प्रशासन के दौरान अमेरिकी मीडिया, कांग्रेस सदस्यों और सीनेटरों तथा अमेरिकी विदेश विभाग ने शिनजियांग, तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन और हांगकांग में लोकतंत्र के दमन के लिए चीन की बार-बार आलोचना की थी। अतीत के विपरीत, "भेड़िया योद्धा" कूटनीति के माध्यम से, चीन ने संयुक्त राज्य अमरीका के भीतर बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन को रेखांकित करते हुए अपनी मानवाधिकार रिपोर्ट प्रकाशित करके और यहां तक कि अमेरिकी लोकतंत्र की आलोचना करके, सामाजिक ध्रुवीकरण और यूएस कैपिटल में 6 जनवरी के विद्रोह को उजागर करके जवाबी कार्रवाई की, जिसने अमेरिकी लोकतांत्रिक आदर्शों को कमजोर कर दिया।

ट्रम्प प्रशासन ने 2020 के दशक की शुरुआत से पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाले कोविड 19 वायरस के बारे में दुनिया को संवेदनशील बनाने में चीन की विफलता को भी पेश करने की कोशिश की। लेकिन चीन के वुहान शहर में तबाही मचाने से पहले तक किसी ने भी इस कोविड-19 के बारे में नहीं सुना था। जबकि वैश्विक सहानुभूति उन चीनी नागरिकों के लिए थी जो बेरहमी से इस वायरस से पीड़ित थे या इस वायरल हमले से मर गए थे, सहानुभूति चीन के खिलाफ संदेह, चिंताओं और यहां तक कि क्रोध में बदल गई क्योंकि कोविड-19 दुनिया भर में फैल गया और महामारी का अनुपात ले लिया। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे 'चीन वायरस' करार दिया था। ट्रम्प के बयान ने अमरीका-चीन शीत टकराव को तेज कर दिया जो वर्षों से चल रहा था और "टैरिफ युद्ध" से तेज हो गया। राष्ट्रपति ट्रम्प के बयान ने चीनी सरकार को काले रंग में रंग दिया, इसकी सॉफ्ट पावर को कम कर दिया, इसके व्यापार लाभ को मिटा दिया, और दुनिया में चीन के सॉफ्ट पावर प्रभाव को कमजोर कर दिया। यद्यपि, चीन पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का शासन जारी रहा, लेकिन इसकी आर्थिक सफलताओं ने इसकी सॉफ्ट पावर को काफी हद तक बढ़ा दिया।

चीन ने वायरस के लक्षण वर्णन के परिणामों को 'चीन वायरस' के रूप में समझा और इसका मुकाबला करने के लिए एक राजनयिक आक्रामक रुख अपनाया। स्पेनिश फ्लू शब्द का उपयोग स्पेन के लिए ज्यादा परेशान करने वाला नहीं था। तब समय अलग था। लेकिन चीन ने अपनी छवि और व्यावसायिक संभावनाओं दोनों के संदर्भ में 'चीन वायरस' शब्द की कीमत को महसूस किया। हालांकि, काफी हद तक चीन देशों को 'चाइना वायरस' शब्द का इस्तेमाल करने से बचने के लिए राजी करने में सफल रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 'कोविड-19' शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसका इस्तेमाल बंद कर दिया। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिकी योगदान को निलंबित करके और चीन का समर्थन करने के लिए इस विश्व निकाय को दोषी ठहराकर, ट्रम्प प्रशासन ने चीन के साथ अपने टकराव को और बढ़ा दिया। चीन के लिए एक और चुनौती वायरस की उत्पत्ति की अंतरराष्ट्रीय जांच की बढ़ती मांगों का प्रबंधन करना था। यह सब

एक अमेरिकी सहयोगी, ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू हुआ, जिसने चीन की सीमाओं से परे वायरस की उत्पत्ति और प्रसार की एक स्वतंत्र जांच का आह्वान किया। इस तरह की मांग ने जल्द ही कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया और जंगल की आग के रूप में फैल गई। षड्यंत्र के सिद्धांत पहले से ही प्रचुर मात्रा में थे। चीन को कोसने वाले भी इसमें शामिल हो गए।

एक प्रमुख इतिहासकार एडवर्ड ली का विचार है कि कन्फ्यूशियस संस्थान "चीनी भाषा शिक्षा प्रदान करने वाले निर्दोष सांस्कृतिक केंद्र नहीं हैं जो वे होने का नाटक करते हैं। बल्कि, वे अमरीका के खिलाफ चीन के "नरम युद्ध" का एक प्रमुख स्तर हैं।

चीन ने किसी भी अंतरराष्ट्रीय जांच दल को अपने क्षेत्र में आमंत्रित करने से इनकार कर दिया। चीन के नजरिए से देखा जाए तो चीन की छवि खराब करने के लिए ट्रंप प्रशासन द्वारा चीन के खिलाफ प्रोपेगैंडा वॉर छेड़ दिया गया था। चीन इस बात से नाराज था कि उसके सुरक्षात्मक उपकरण और अन्य चिकित्सा उपकरण खरीदते समय, संयुक्त राज्य अमरीका सहित कई देशों ने महामारी के लिए चीन को दोषी ठहराना जारी रखा। लेकिन कोविड-19 महामारी के दो साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में बताया था कि "चीनी सरकार ने वैज्ञानिकों का मुंह बंद कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय जांच में बाधा डाली और महामारी की ऑनलाइन चर्चा को सेंसर कर दिया" और "अपनी सरकार के दबाव में चीनी वैज्ञानिकों ने डेटा को रोक दिया है, सार्वजनिक डेटाबेस से आनुवंशिक अनुक्रमों को वापस ले लिया है और जर्नल सबमिशन में महत्वपूर्ण विवरण बदल दिए हैं[125]।

सॉफ्ट पावर का एक और पहलू जिसने अमरीका-चीन के मतभेदों को जन्म दिया, वह शैक्षिक आदान-प्रदान और वित्त पोषण पर था। कूटनीति के एक उपकरण के रूप में शिक्षा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो गई है और प्रतिस्पर्धा के एक चरण में प्रवेश कर चुकी है। किसी देश की शिक्षा नीति, विशेष रूप से फैलोशिप की पेशकश करने, विश्वविद्यालय परिसरों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने, विदेशों में शैक्षिक संस्थानों के वित्तपोषण, विदेशी विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में कुछ पसंदीदा पाठ्यक्रम शुरू करने या अन्य देशों में कैंपस विस्तार खोलने के लिए फ्रैंचाइज़ी की मांग करने से संबंधित तेजी से प्रतिस्पर्धी हैं।

शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दशकों तक, कई देशों के छात्रों ने उच्च शिक्षा, अनुसंधान सहयोग और कौशल विकास के लिए संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और कई अन्य देशों के विश्वविद्यालयों का रुख किया। अभूतपूर्व आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप अपनी नई अर्जित संपत्ति के बाद चीन ने भी बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करना शुरू कर दिया और उन्हें चीन समर्थक बनाने की मांग की। हालांकि, जब चीन ने विदेशों में चीनी अध्ययन कार्यक्रमों को वित्त पोषित करना शुरू किया, तो यह संयुक्त राज्य अमरीका और चीन के बीच टकराव का क्षेत्र बन गया। चीन सरकार ने विभिन्न अमेरिकी विश्वविद्यालयों और निश्चित रूप से कई अन्य देशों में बड़ी संख्या में

कन्फ्यूशियस संस्थानों को वित्त पोषित किया[126]। एक प्रमुख इतिहासकार एडवर्ड ली का विचार है कि कन्फ्यूशियस संस्थान "चीनी भाषा शिक्षा प्रदान करने वाले निर्दोष सांस्कृतिक केंद्र नहीं हैं जो वे होने का नाटक करते हैं। बल्कि, वे अमरीका के खिलाफ चीन के "नरम युद्ध" का एक प्रमुख स्तर हैं[127]। अमेरिकी सांसदों को हाल ही में एहसास हुआ है कि चीन कक्षाओं में "अमेरिकी बच्चों को उकसाने" और "कम्युनिस्ट सरकार के प्रचार" को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। सीनेटर टेड क्रूज के अनुसार, "कम्युनिस्ट चीन अमेरिकी विश्वविद्यालयों में घुसपैठ कर रहा है ताकि हमारे पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप किया जा सके, उनके शासन की आलोचना को चुप कराया जा सके, और संवेदनशील दोहरे उपयोग वाले अनुसंधान सहित बौद्धिक संपदा की चोरी की जा सके," और "कन्फ्यूशियस संस्थान हमारे परिसरों में अपने अभियानों के लोहे की मुट्ठी के चारों ओर मखमली दस्ताने हैं। अमेरिकी सरकार को हमारे विश्वविद्यालयों और अनुसंधान की अखंडता की रक्षा करने और अकादमिक जासूसी को अवरुद्ध करने के लिए नए उपकरणों की आवश्यकता है[128]। क्रूज़ ने वास्तव में अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में विदेशी खुफिया संगठनों की गतिविधियों से निपटने के लिए सरकार की क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कानून पेश किया, जिसे 2018 का स्टॉप हायर एजुकेशन जासूसी और चोरी अधिनियम कहा जाता है[129]। संघीय जांच ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की-चीन:शिक्षा के लिए जोखिम-और चीनी सरकार पर "विभिन्न कारणों से अमेरिकी शिक्षा के लिए एक विशेष खतरा पैदा करने" का आरोप लगाया[130]। जल्द ही कुछ कन्फ्यूशियस संस्थानों को बंद करने और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के नाम पर चीनी धन के गैर-पारदर्शी प्रवाह को अवरुद्ध करने के प्रयास किए गए। अन्य देशों ने भी इसी तरह के कदम उठाए हैं, उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई सरकार देश में कन्फ्यूशियस संस्थानों पर नज़र रखने के लिए "विदेशी प्रभाव पारदर्शिता योजना" लेकर आई है। एक वर्ष में, लगभग 10 अमेरिकी विश्वविद्यालयों ने अपने कन्फ्यूशियस संस्थानों को बंद करने के लिए कदम उठाया[131]।

अमरीका ने यूक्रेन में रूसी आक्रामकता को आमने-सामने लेकर एक बार फिर वैश्विक मामलों पर हावी होने की अपनी क्षमता दिखाई है।

वाशिंगटन और बीजिंग दोनों सूक्ष्म तरीकों से दूसरे को एक की कीमत पर बढ़ने की अनुमति नहीं देने की कोशिश करेंगे। दोनों देशों द्वारा अपनाई गई एक प्रकार की परिष्कृत पारस्परिक नियंत्रण रणनीति अन्य देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय जल को जटिल बना देगी।

टिप्पणियों का समापन

जबकि अमरीका और चीन के बीच वर्तमान संबंध अस्थिर हैं, भविष्य स्थिर और तनाव मुक्त होने की संभावना नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका के सापेक्ष पतन और एक महाशक्ति के रूप में चीन के तेजी से उभरने पर हुई

बहसों को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। आर्थिक शक्ति और सैन्य कौशल के मामले में अमरीका की सापेक्ष गिरावट के सैद्धांतिक और अकादमिक औचित्य हो सकते हैं। लेकिन अमरीका ने यूक्रेन में रूसी आक्रामकता को गंभीरता से लेते हुए एक बार फिर विश्व मामलों पर हावी होने की अपनी क्षमता दिखाई है। सभी बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद पश्चिम संयुक्त राज्य अमरीका के साथ खड़ा रहा है। किसी भी अन्य देश के पास यूक्रेन में रूस का मुकाबला करने की क्षमता नहीं है। चीन का महाशक्ति का दर्जा हासिल करना लगभग तय लग रहा था और फिर कोविड-19 महामारी आ गई। चीन के आर्थिक रथ को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। चीन का सैन्य आधुनिकीकरण विश्वस्तरीय प्रतीत होता है। वह कथित तौर पर अपने परमाणु शस्त्रागार को अमरीका और रूस के बराबर लाने की दिशा में भी काम कर रहा है। लेकिन क्या चीन पश्चिमी नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय बाजार के बिना जा सकता है? क्या अमरीका और चीन गहरी आर्थिक निर्भरता के सामने शीत युद्ध जैसे संबंधों को बर्दाश्त कर सकते हैं?

अमरीका और चीन के बीच शीत युद्ध जैसे पुराने संबंध नहीं हो सकते। जटिल अन्योन्याश्रितता देशों के लिए इसे महंगा बना देगी। फिर भी, इन दोनों देशों के लिए स्थिर संबंध बनाए रखना मुश्किल होगा। अमरीका को वैश्विक शक्ति ढांचे में अपनी स्थिति खोने का डर बना रहेगा और चीन अपने दशकों के लंबे प्रयासों के बावजूद शीर्ष पर नहीं पहुंचने के बारे में चिंता करता रहेगा। अमरीका-चीन संबंधों में अस्थिरता दूर होगी। फिलहाल, न तो अमरीका और चीन के बीच युद्ध की कोई संभावना है, न ही शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की कोई संभावना है। ◆

लेखकों के बारे में

राजदूत अरुण के. सिंह

अरुण के. सिंह संयुक्त राज्य अमरीका (2015-2016), फ्रांस (2013-2015) और इज़राइल (2005-2008) में भारत के राजदूत थे। राजदूत सिंह के पास संयुक्त राज्य अमरीका, इजरायल और फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में दुनिया भर में व्यापक अनुभव है। भारतीय विदेश सेवा में अपने 37 साल के विशिष्ट करियर के दौरान, राजदूत सिंह ने प्रमुख वैश्विक राजधानियों में महत्वपूर्ण अवधि के दौरान सेवा की है, और भारत की नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से अमरीका-भारत संबंधों में निरंतर प्रगति; इजरायल के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध; और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से संबंधित भारत की नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन, जिसमें 9/11 के बाद की अवधि भी शामिल है।

राजदूत सिंह वर्तमान में अशोका विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर, अमरीका के जर्मन मार्शल फंड और कार्नेगी इंडिया में एशिया कार्यक्रम में एक प्रतिष्ठित अनिवासी वरिष्ठ फेलो हैं। 2017 के वसंत में, राजदूत सिंह ने दक्षिण एशिया में अमेरिकी विदेश नीति और वर्तमान वैश्विक रुझान और चुनौतियों पर अमेरिकी विश्वविद्यालय और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज दोनों में पाठ्यक्रम पढ़ाया। वह एमोरी विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित विजिटिंग प्रोफेसर और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडी ऑफ इंडिया भी थे। वह 2021-22 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे।

राजदूत सिंह ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की, जहां उन्होंने अर्थमिति, विकास नीति, मैक्रोइकॉनॉमिक्स और भारतीय आर्थिक इतिहास में विशेषज्ञता हासिल की।

प्रो श्रीकांत कोंडापल्ली

श्रीकांत कोंडापल्ली स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डीन और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में चीन अध्ययन के प्रोफेसर हैं। वह 2008-10, 2012-14, 2016-18 और 2018-20 तक सेंटर फॉर ईस्ट एशियन स्टडीज, एसआईएस, जेएनयू के अध्यक्ष थे। उन्होंने चीनी अध्ययन में पीएचडी के साथ भारत और चीन में चीनी अध्ययन में शिक्षा प्राप्त की है। उन्होंने बीजिंग भाषा और संस्कृति विश्वविद्यालय में चीनी भाषा सीखी और 1996-98 तक पीपुल्स यूनिवर्सिटी, बीजिंग में पोस्ट-डॉक्टरल विजिटिंग फेलो थे। वह 2004 में नेशनल चेंगची विश्वविद्यालय, ताइपे में विजिटिंग प्रोफेसर, मई 2007 में चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परारी इंटरनेशनल रिलेशंस, बीजिंग में विजिटिंग फेलो, 2009, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 और 2019 में शेडोंग विश्वविद्यालय, जिनान में मानद प्रोफेसर थे; 2014 में जिलिन विश्वविद्यालय, चांगचुन में और 2016 और 2017 में युन्नान यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, कुनमिंग में, 2014 से पीपुल्स यूनिवर्सिटी में एक अनिवासी वरिष्ठ फेलो और 2010 में साल्ज़बर्ग ग्लोबल सेमिनार में फेलो। उन्होंने दो किताबें लिखीं:

- *चीन की सेना:* 1999 में *संक्रमण में पीएलए* और
- 2001 में *चीन की नौसेना शक्ति।*

उन्होंने दो मोनोग्राफ लिखे, और छह खंडों का सह-संपादन किया:

- 2004 में *एशियाई सुरक्षा और चीन*
- 2010 में *चीन और उसके पड़ोसी*
- 2012 में *चीन की सेना और भारत*
- *चीन और ब्रिक्स:* 2016 में *एक अलग रसोई की स्थापना*
- *वन बेल्ट वन रोड-चीन की वैश्विक आउटरीच,* 2017 और
- *चीन और कोविद-19-घरेलू और बाहरी आयाम* 2020

और पत्रिकाओं और संपादित संस्करणों में कई लेख-सभी चीन पर। उन्हें *सामरिक और सुरक्षा अध्ययन में अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए 2010 में के. सुब्रमण्यम पुरस्कार* मिला।

प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा

चिंतामणि महापात्रा कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडो-पैसिफिक स्टडीज के संस्थापक और मानद अध्यक्ष हैं। वह *इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल* (एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमैट्स द्वारा प्रकाशित) *के संपादक* हैं।

वह मई 1999 से मई 2022 तक जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एक संकाय थे। उन्होंने 1 मार्च 2016 से 7 फरवरी 2022 तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रेक्टर (प्रो-वाइस चांसलर) के रूप में कार्य किया। उन्होंने सदस्य, यूजीसी समीक्षा समिति, क्षेत्र अध्ययन कार्यक्रम जैसे पदों पर कार्य किया है; अध्येतावृत्ति विशेषज्ञ समिति, आईसीएसएसआर के सदस्य; सदस्य, संपादकीय बोर्ड, सामरिक विश्लेषण, आईडीएसए।

हाल ही में, वह चीन के युन्नान विश्वविद्यालय में टैगोर चेयर प्रोफेसर थे। उन्होंने कई अमेरिकी राष्ट्रपति पुस्तकालयों (विशेष रूप से ट्रूमैन लाइब्रेरी, आइजनहावर लाइब्रेरी, जॉन एफ कैनेडी लाइब्रेरी और जॉनसन लाइब्रेरी) और वाशिंगटन, डीसी में यूएस नेशनल आर्काइव्स में शोध किया है; और लंदन में ब्रिटिश पब्लिक रिकॉर्ड ऑफिस।

महापात्र ने 8 पुस्तकों का लेखन/संपादन किया है, और 30 से अधिक संपादित पुस्तकों में अध्यायों का योगदान दिया है। उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में 70 से अधिक शोध लेख प्रकाशित किए हैं। उन्हें अमरीका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों में अनुसंधान करने के लिए फुलब्राइट फैलोशिप, कॉमनवेल्थ फैलोशिप और विजिटिंग फैलोशिप जैसे कई अंतरराष्ट्रीय फैलोशिप से सम्मानित किया गया है।

वह यूजीसी द्वारा संचालित कई अकादमिक स्टाफ कॉलेजों, विदेश मंत्रालय के विदेश सेवा संस्थान में विजिटिंग फैकल्टी रहे हैं। अफेयर्स, नेशनल डिफेंस कॉलेज, आर्मी वॉर कॉलेज, नेवल वॉर कॉलेज और कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर। वह अंतरराष्ट्रीय मामलों पर समाचार पत्रों और ऑडियो-विज़ुअल मीडिया में एक नियमित टिप्पणीकार भी हैं।

पाद-टिप्पणियां

[1] अर्थव्यवस्था, एलिजाबेथ। चीन पर रास्ता बदलना। वर्तमान इतिहास, 09, 2003. 243. 6 मई, 2023 को अभिगम्य। https://ceip.idm.oclc.org/ login?url=https://www.proquest.com/magazines/changing-course-on-china/docview/200751097/se-2

[2] बारबोजा, डेविड। "चीन जापान को दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पार करता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स। 24 मार्च को अभिगम्य, 2023.https:// www.nytimes.com/2010/08/16/business/global/16yuan.html.

[3] व्हाइट हाउस, प्रेस सचिव का कार्यालय। 2009. राष्ट्रपति ओबामा और चीन के राष्ट्रपति हू द्वारा संयुक्त प्रेस वक्तव्य। 17 नवंबर. 8 मार्च को अभिगम्य। https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/joint-press-statement-president- obama-and-president-hu-china "एपेक सीईओ शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति ओबामा की टिप्पणी, "व्हाइट हाउस, प्रेस सचिव का कार्यालय, 10 नवंबर, 2014, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/10/remarks-president-obama- apec-ceo-summit "राष्ट्रपति ओबामा और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति हू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, "व्हाइट हाउस, प्रेस सचिव का कार्यालय, 19 जनवरी, 2011, https://obamawhitehouse. archives.gov/the-press-office/2011/01/19/press- conference-president-obama-and-president-hu-peoples-republic-china

[4] व्हाइट हाउस, प्रेस सचिव का कार्यालय। 2015. राष्ट्रपति ओबामा और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति शी द्वारा एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में टिप्पणी। 25 सितंबर 9 मार्च को अभिगम्य। https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/09/25/remarks-president-obama-and-president-xi-peoples-republic-china-joint

[5] 2010. "राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2010। ओबामा व्हाइट हाउस अभिलेखागार 24 मार्च को अभिगम्य, 2023. https://obamawhitehouse. archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf.

[6] "फैक्ट शीट: 2015 राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति", व्हाइट हाउस, प्रेस सचिव का कार्यालय, 6 फरवरी, 2015, https:// obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/02/06/fact-sheet-2015-national-security-strategy

[7] 2009. "अमेरिका-एशिया संबंध: हमारे भविष्य के लिए अपरिहार्य।. 24 मार्च को अभिगम्य, 2023. https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2009a/02/117333.htm.

[8] ब्रैनिगन, तानिया। "क्लिंटन वैश्विक आर्थिक संकटों से निपटने के लिए चीन केसाथ आम सहमति चाहते हैं। *द गार्डियन*. 24 मार्च को अभिगम्य, 2023. https://www.theguardian.com/world/2009/feb/21/hillary-clinton-china-economy-human-rights.

[9] क्लिंटन, हिलेरी. 2011. "अमेरिका की प्रशांत सदी। विदेश नीति. 9 मार्च को अभिगम्य। https://foreignpolicy.com/2011/10/11/ americas-pacific-century/.

[10] 2011. "अमेरिका की प्रशांत सदी" अमेरिकी विदेश विभाग (अमेरिकी विदेश विभाग) 24 मार्च को अभिगम्य, 2023. https://2009-2017.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2011/11/176999.htm.

[11] 2012. "अमेरिकी वैश्विक नेतृत्व को बनाए रखना: 21वीं सदी की रक्षा के लिए प्राथमिकताएं। रक्षा विभाग. 26 मार्च को अभिगम्य। https://www.globalsecurity.org/military/library/policy/dod/defense_guidance-201201.pdf.

[12] 2015. " फैक्ट शीट: एशिया और प्रशांत में पुनर्संतुलन को आगे बढ़ाना। व्हाइट हाउस. 08 मई, 2023 को अभिगम्य। https:// obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/11/16/fact-sheet-advancing-rebalance-asia-and-pacific.

[13] 2013. "चीनी विदेश मंत्री ने चीन, अमेरिका के बीच नए प्रकार के महान शक्ति संबंधों के निर्माण के लिए सक्रिय, व्यापक प्रयासों का आह्वान किया। संयुक्त राज्य अमेरिका में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का दूतावास 25 मार्च को अभिगम्य। http://us.china-embassy.gov. cn/eng/zmgxss/201307/ t20130702_4368671.htm.

[14] 2013. " राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसान ई. राइस द्वारा डिलीवरी के लिए तैयार की गई टिप्पणी। व्हाइट हाउस, प्रेस सचिव का कार्यालय। 25 मार्च को अभिगम्य। https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2013/11/21/remarks-prepared-delivery-national-security-advisor-susan-e-rice.

[15] 2014. " संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति ओबामा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की टिप्पणी। व्हाइट हाउस, प्रेस सचिव का कार्यालय. 25 मार्च को अभिगम्य। https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/12/remarks-president-obama-and-president-xi-jinping-joint-press-conference.

[16] कोरासंती, निक, अलेक्जेंडर बर्न्स और बिन्यामिन अप्पेलबाम। "डोनाल्ड ट्रम्प ने व्यापार सौदों को तोड़ने और चीन का सामना करने की कसम खाई। द न्यूयॉर्क टाइम्स. 25 मार्च को अभिगम्य। https://www.nytimes.com/2016/06/29/us/politics/donald-trump-trade-speech.html.

[17] 2017. "राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। ट्रम्प व्हाइट हाउस अभिलेखागार। 8 मार्च को अभिगम्य। https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.

[18] 2020. "पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का रणनीतिक दृष्टिकोण। ट्रम्प व्हाइट हाउस अभिलेखागार। 29 मार्च को अभिगम्य। https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2020/05/U.S.-Strategic-Approach-to-The-Peoples-Republic- of-China-Report-5.24v1.pdf.

[19] 2018. “2018 राष्ट्रीय रक्षा रणनीति का सारांश, "अमेरिकी रक्षा विभाग। 8 मार्च को अभिगम्य। https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf

[20] न्यूमैन, स्कॉट। "सैन्य नाम परिवर्तन में, अमेरिकी प्रशांत कमान अमेरिकी हिंद-प्रशांत कमान बन जाती है। NPR. 29 मार्च को अभिगम्य। https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/05/31/615722120/in-military-name-change-u-s-pacific-command-becomes-u-s-indo-pacific-command.

[21] स्टीवेन्सन, एलेक्जेंड्रा। "विल्बर रॉस, चीन यात्रा से ताजा, 'एकतरफा' व्यापार संबंधों की चेतावनी देता है। द न्यूयॉर्क टाइम्स। 28 मार्च को अभिगम्य। https://www.nytimes.com/2017/09/27/business/wilbur-ross-china-trade.html.

[22] 2020. “चीन एशिया में 'प्रमुख सैन्य, आर्थिक खतरा': अमेरिकी वाणिज्य मंत्री एएनआई समाचार. 28 मार्च को अभिगम्य। https://www.aninews.in/news/world/us/china-a-principal-military-economic-threat-in-asia-says-us-commerce-secretary20201208163612/.

[23] 2020. “सेक्रेटरी माइकल आर पोम्पेओ ने टिप्पणी की "कम्युनिस्ट चीन और मुक्त विश्व का भविष्य"। 28 मार्च को अभिगम्य। https://cl.usembassy.gov/secretary-michael-r-pompeo-remarks-communist- china-and-the-free-worlds-future/.

[24] ग्लास, एंड्रयू। "ट्रम्प ने ट्रांस-पैसिफिक व्यापार समझौते को विफल कर दिया, 23 जनवरी, 2017। राजनीतिक। 9 मार्च को अभिगम्य। https://www. politico.com/story/2019/01/23/trans-pacific-trade-pact-2017-1116638.

[25] 2019. “एक स्वतंत्र और खुला ऑन-प्रशांत: एक साझा दृष्टि को आगे बढ़ाना। 8 मार्च को अभिगम्य। https:// www.state.gov/wp-content/uploads/2019/11/Free-and-Open-Indo-Pacific-4Nov2019.pdf.

[26] थायर, कार्ल। "एशिया आश्वासन पहल अधिनियम: एक अमेरिकी हिंद-प्रशांत रणनीति के लिए रूपरेखा"?” *द डिप्लोमेट।* 8 मार्च को अभिगम्य। https://thediplomat.com/2020/01/asia-reassurance-initiative-act-framework-for-a-us-indo-pacific-strategy/.

[27] 2017. “संयुक्त राष्ट्र महासभा में राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रम्प: अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति की रूपरेखा। ट्रम्प व्हाइट हाउस अभिलेखागार। 9 मार्च को अभिगम्य। https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/president- donald-j-trump-united-nations-general-assembly-outlining-america-first-foreign-policy/

[28] डिंगली, शेन। "एक टेस्टी ओपनिंग डायलॉग। चीन, अमेरिका का फोकस। 8 मार्च को अभिगम्य। https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/a-testy-opening-dialogue.

[29] 2022. “फैक्ट शीट: बिडेन: हैरिस प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। व्हाइट हाउस। 9 मार्च को अभिगम्य। https:// www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/12/fact-sheet-the-biden-harris-administrations-national-security-strategy/.

[30] टूल्सी, नाहल, अलेक्जेंडर वार्ड, और क्विंट फोर्गे। "पुतिन राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में देरी कर रहे हैं।” *पॉलिटीको* 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.politico.com/newsletters/national-security-daily/2022/02/10/putin-delaying-national-security- strategy-00007916.

[31] 2021. “अंतरिम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक मार्गदर्शन। व्हाइट हाउस. 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/ 03/03/interim-national-security-strategic-guidance/.

[32] रक्षा, अमेरिकी विभाग। "डीओडी ने राष्ट्रीय रक्षा रणनीति, मिसाइल रक्षा, परमाणु मुद्रा समीक्षा” 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3202438/dod-releases-national- defense-strategy-missile-defense-nuclear-posture-reviews/.

[33] 2022. “हिंद-प्रशांत रणनीति। व्हाइट हाउस। 10 फरवरी, 2023 को अभिगम्य। https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf.

[34] क्रिस्पिन, शॉन डब्ल्यू। "चीन हार रहा है, अमेरिका थाईलैंड में महत्वपूर्ण जमीन हासिल कर रहा है। एशिया टाइम्स। 9 मार्च को अभिगम्य। https:// asiatimes.com/2022/06/china-losing-us-gaining-crucial-ground-in-thailand/.

[35] स्ट्रैंगियो, सेबेस्टियन। "थाई पीएम ने सुरक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्री से मुलाकात की।” *द डिप्लोमेट.* 9 मार्च को अभिगम्य। https://thediplomat.com/2022/06/thai-pm-meets-us-defense-secretary-in-a-bid-to-advance-security-ties/.

[36] 2022. “रणनीतिक गठबंधन और साझेदारी पर संयुक्त राज्य अमेरिका-थाईलैंड की विज्ञप्ति। 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.state.gov/united-states-thailand-communique-on-strategic-alliance-and-partnership/.

[37] 2022. “रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन III की थाईलैंड के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री प्रयुत चान-ओ-चा के साथ बैठक का रीडआउट। 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.defense.gov/News/Releases/Release/ Article/3060226/readout-of-secretary-of-defense-lloyd-j-austin-iii-meeting-with-thailand-prime/#:~:text=Austin%20III%20traveled%20to%20Thailand,defense%20personnel%20working%20in%20Thailand.

[38] अबुजा, जचारी। "अमेरिका को थाईलैंड के साथ अपने गठबंधन के बारे में यथार्थवादी होना चाहिए।” वॉर ऑन रॉक्स। 9 मार्च को अभिगम्य। https://warontherocks.com/2020/01/america-should-be-realistic-about-its-alliance-with-thailand/

[39] ग्रॉसमैन, डेरेक। "चीन के साथ दुतेर्ते का गठबंधन खत्म हो गया है। रैंड ब्लॉग। 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.rand.org/

blog/2021/11/dutertes-dalliance-with-china-is-over.html.

[40] लेमा, करेन। "फिलीपींस चीन की चिंताओं के बीच अमेरिका को ठिकानों तक अधिक पहुंच प्रदान करता है। रायटर। 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.reuters.com/world/philippines-grants-us-greater-access-bases-amid-china-concerns-2023-02-02/.

[41] सेलिगमैन, लारा और रॉबी ग्रामर। "ट्रम्प ने टोक्यो को जापान में अमेरिकी सैनिकों के लिए भुगतान को चौगुना करने के लिए कहा। विदेश नीति. 9 मार्च को अभिगम्य। https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-asks-tokyo-quadruple-payments-us-troops-japan/.

[42] 2022. "जापान की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। जापान के विदेश मंत्रालय। 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000081.html.

[43] 2022. "जापान की ऐतिहासिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन का बयान। व्हाइट हाउस। 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/12/16/statement-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-japans-historic-national-security-strategy/.

[44] 2021. " प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति बाइडन और जापान के प्रधानमंत्री सुगा की टिप्पणी। व्हाइट हाउस। 25 मार्च को अभिगम्य। https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/16/remarks-by-president-biden-and-prime-minister-suga-of-japan-at-press-conference/.

[45] कैरोल, क्रिस्टोफर एडवर्ड। "ओकिनावा में अमेरिकी समुद्री तैनाती में प्रस्तावित परिवर्तनों के पीछे क्या है"?" *द डिप्लोमेट।* 25 मार्च को अभिगम्य। https://thediplomat.com/2023/02/whats-behind-proposed-changes-to-us-marine-deployments-in- okinawa/.

[46] 2022. "जापान-अमेरिका संयुक्त नेताओं का बयान: मुक्त और खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करना। व्हाइट हाउस। 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/05/23/japan-u-s-joint-leaders-statement-strengthening-the-free-and-open-international-order/.

[47] 2021. "द्विपक्षीय बैठक से पहले राष्ट्रपति बाइडन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मॉरिसन की टिप्पणी। व्हाइट हाउस। 25 मार्च को अभिगम्य। https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/09/21/remarks-by-president-biden-and-prime-minister-morrison-of-australia-before-bilateral-meeting/#:~:text=The%20United%20States%20has%20no,accomplished%20together%20over%2070%20years.

[48] 2022. "चीन के खतरे को देखते हुए अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा संबंधों को 'गहरा' करेगा। फाइनेंशियल टाइम्स। 8 मार्च को अभिगम्य। https:// www.ft.com/content/4e9b 58e6-11aa-4c85-b38c-e7be07f39a25.

[49] 2023. " AUKUS पर संयुक्त नेताओं का बयान। व्हाइट हाउस. 25 मार्च को अभिगम्य। https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/13/joint-leaders-statement-on-aukus-2/.

[50] 2019. "हिंद-प्रशांत रणनीति रिपोर्ट। रक्षा विभाग. 8 मार्च को अभिगम्य। https://media.defense.gov/ 2019/ Jul/01/2002152311/-1/-1/1/DEPARTMENT-OF-DEFENSE-INDO-PACIFIC-STRATEGY-REPORT-2019.PDF.

[51] येओ, एंड्रयू। "दक्षिण कोरिया-जापान तालमेल हिंद-प्रशांत में नए अवसर पैदा करता है। ब्रूकिंग्स। 08 मई, 2023 को अभिगम्य। https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2023/03/17/korea-japan-rapprochement-creates-new- opportunities-in-the-indo-pacific/.

[52] शेपर्डसन, डेविड। "पांच चीनी कंपनियां अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती हैं: एफसीसी" रायटर। 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.reuters.com/article/us-usa-china-tech-idUSKBN2B42DW.

[53] टैन, जोआना। "अलास्का में अमेरिका और चीन के बीच गर्म आदान-प्रदान से मुख्य आकर्षण यहां दिए गए हैं। सीएनबीसी। 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.cnbc.com/2021/03/19/here-are-the-highlights-from-the-heated-us-china-exchange-in-alaska.html.

[54] ज़ेंगरले, पेट्रीसिया और माइकल मार्टिना। "अमेरिकी सांसदों ने चीन का मुकाबला करने के लिए द्विदलीय प्रयासों को तेज किया। रायटर. 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-lawmakers-look-advance-sweeping-bid-counter- china-2021-04-21/

[55] फ्रैंक, थॉमस। "सीनेट ने चीन का मुकाबला करने के उद्देश्य से $ 250 बिलियन द्विदलीय तकनीक और विनिर्माण विधेयक पारित किया। सीएनबीसी. 8 मार्च को अभिगम्य। https://www.cnbc.com/2021/ 06/08/senate-passes-bipartisan-tech-and-manufacturing-bill-aimed-at- china.html.

[56] रेन्स, विलियम एलन। "निर्यात नियंत्रण: बहुत अधिक या बहुत कम?" CSIS. 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.csis.org/analysis/export-control-too-much-or-too-little.

[57] 2022. "विदेश मंत्रालय ने नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में जवाबी उपायों की घोषणा की। विदेश मंत्रालय, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. 9 मार्च को अभिगम्य। https://www.fmprc.gov.cn/eng/ zxxx_662805/202208/t20220805_10735706.html.

[58] पामर, जेम्स। "कैसे एक चीनी जासूस गुब्बारे ने एक महत्वपूर्ण अमेरिकी राजनयिक यात्रा को उड़ा दिया। विदेश नीति। 8 मार्च को

अभिगम्य। https://foreignpolicy.com/2023/02/03/china-spy-balloon-surveillance-montana-us-nuclear-blinken/.

[59] 2023. “ब्लिंकन-वांग यी की बैठक में तीखे शब्दों और टकराव की भेंट” रेस्पॉंसिबल स्टेटक्राफ्ट 9 मार्च को अभिगम्य। https://responsiblestatecraft.org/2023/02/20/blinken-wang-yi-meeting-marked-by-sharp-words-and-confrontation/.

[60] 2023. " जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में अमेरिका-चीन आर्थिक संबंधों पर ट्रेजरी सचिव जेनेट एल येलेन की टिप्पणी. 08 मई, 2023 को अभिगम्य। जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज में अमेरिका-चीन आर्थिक संबंधों पर ट्रेजरी सचिव जेनेट एल येलेन की टिप्पणी। https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1425

[61] 2023. " ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन में अमेरिकी आर्थिक नेतृत्व के नवीनीकरण पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन की टिप्पणी। व्हाइट हाउस. 08 मई, 2023 को अभिगम्य। https://www.whitehouse.gov/ briefing-room/speeches-remarks/2023/04/27/remarks-by-national-security-advisor-jake-sullivan-on-renewing-american-economic-leadership-at-the-brookings-institution/.

[62] यांग, विलियम। "चीन: जासूसी विरोधी कानून विदेशी फर्मों के लिए जोखिम बढ़ाता है। डीडब्ल्यू। 08 मई, 2023 को अभिगम्य। https://www. dw.com/en/china-anti-espionage-law-heightens-risks-for-foreign-firms/a-65528537#:~:text=China's%20rubber%2Dstamp%20 parliament%20last,deemed%20related%20to%20national%20security.

[63] "पीआरसी निवेश जलवायु पर चिंताओं पर यूएस चैंबर का बयान" यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स. 28 अप्रैल, 2023 को अभिगम्य। https://www.uschamber.com/international/u-s-chamber-statement-on-concerns-over-prc-investment-climate.

[64] 2023. " प्रतिलेख: विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। वाशिंगटन पोस्ट लाइव। 08 मई, 2023 को अभिगम्य। https://www.washingtonpost.com/ washington-post-live/2023/05/03/transcript-world-press-freedom-day/.

[65] 2023. " एक महान-शक्ति युद्ध से कैसे बचें: जनरल मार्क मिले के साथ एक बातचीत। विदेश मामले 08 मई, 2023 को अभिगम्य। https://www.foreignaffairs.com/podcasts/how-to-avoid-great-power-war-mark-milley.

[66] ताई मिंग चेउंग और थॉमस जी महनकेन, रक्षा तकनीकी और औद्योगिक विकास में द गैदरिंग पैसिफिक स्टॉर्म इमर्जिंग यूएस-चाइना रणनीतिक प्रतियोगिता (न्यूयॉर्क: कैम्ब्रिया हाउस, 2018); जेम्स जॉनसन, ओबामा राष्ट्रपति पद के दौरान अमेरिका-चीन सैन्य और रक्षा संबंध (पालग्रेव मैकमिलन,2018)

[67] जाइ हो चुंग, एड. चीन की शक्ति का आकलन (न्यूयॉर्क: पालग्रेव मैकमिलन, 2015)

[68] संकट में बहुपक्षवाद-अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ का असहज त्रिकोण (लंदन: रूटलेज;, 2023)

[69] हालांकि, अपनी व्यापक राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने के बावजूद, चीन अभी तक अमेरिका की "संरचनात्मक शक्ति" से उबर नहीं पाया है। देखें स्टीव चैन, थंडर के रंबल्स: पावरशिफ्ट्स और चीन-अमेरिकी युद्ध का खतरा (न्यूयॉर्क: कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस 2023)

[70] जॉन इकेनबेरी, वांग जिसी, और झू फेंग, अमेरिका, चीन, और विश्व व्यवस्था विचारों, परंपराओं, ऐतिहासिक विरासत और वैश्विक दृष्टि के लिए संघर्ष (न्यूयॉर्क: पालग्रेव मैकमिलन, 2015); झाओ सुशेंग, चीन और पूर्वोत्तर एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोग और प्रतिस्पर्धा (न्यूयॉर्क: पालग्रेव मैकमिलन, 2008); झू झिकुन, 21 वीं सदी में अमेरिका-चीन संबंध-शक्ति संक्रमण और शांति (लंदन: रूटलेज), 2006);

[71] एंड्रू टी.एच. टैन, हैंडबुक ऑफ यूएस-चाइना रिलेशंस (चेल्टेनहम, यूके: एडवर्ड एल्गर पब्लिशिंग, 2016)

[72] देखें 对抗，博弈，合作 - 中美安全危机管理案例分析 [टकराव, गेमिंग, सहयोग-चीन-अमेरिकी सुरक्षा संकट प्रबंधन में क्लासिक मामले] (बीजिंग: विश्व ज्ञान प्रकाशन), 2007)

[73] गाइ रॉबर्ट्स, अमेरिकी विदेश नीति और चीन-श का पहला कार्यकाल (लंदन: रूटलेज), 2015)

[77] एडेन वॉरेन और एडम बार्टले, बुश, ओबामा और ट्रम्प प्रशासन के दौरान अमेरिकी विदेश नीति और चीन सुरक्षा चुनौतियां (एडिनबर्ग: एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी प्रेस), 2021)

[75] फेंग हुइयुन और हे काई, अमेरिका-चीन प्रतियोगिता और दक्षिण चीन सागर विवाद (लंदन: रूटलेज), 2018)

[76] झोउ जिंगहाओ, चीन-अमेरिका संबंधों के नए सामान्य के रूप में महान शक्ति प्रतियोगिता (पालग्रेव मैकमिलन, 2023); एशियाई भू-राजनीति और अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता (लंदन: रूटलेज, 2022); रेनाटो जी फ्लोरेस जूनियर, द वर्ल्ड कोरोना ने न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर में अमेरिका, चीन और मध्य शक्तियों को बदल दिया (न्यूयॉर्क: रूटलेज;, 2022)

[77] जेम्स सी सियुंग, दक्षिण चीन सागर विवाद और अमेरिका-चीन प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय कानून और भू-राजनीति (सिंगापुर: विश्व वैज्ञानिक प्रकाशन), 2018)

[78] पृष्ठभूमि के लिए देखें लिन चेंग-यी तथा डेनी रॉय, एड। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ताइवान संबंधों का भविष्य (न्यूयॉर्क: पालग्रेव मैकमिलन, 2011); हार्टनेट उथल-पुथल की दुनिया-संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ताइवान लंबे शीत युद्ध में (ईस्ट लैंसिंग: मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेस, 2021)

[79] यान ज़ुएटोंग, नेतृत्व और महान शक्तियों का उदय (प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2019) पृष्ठ 34.

[80] इस विषय पर देखें जॉन सी एमॉन, व्यापार मुद्दे, नीतियां और कानून अमेरिका-चीन व्यापार परिप्रेक्ष्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव (न्यूयॉर्क: नोवा साइंस पब्लिशर्स, 2021); यून हेओ, मुक्त व्यापार और अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध एक नेटवर्क परिप्रेक्ष्य

(न्यूयॉर्क: रूटलेज, 2023); पाक नुंग वोंग, तकनीकी-भू-राजनीति-अमेरिका-चीन टेक युद्ध और डिजिटल स्टेटक्राफ्ट का अभ्यास (लंदन: न्यूयॉर्क, 2022); यू मियाओजी, चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध और व्यापार वार्ता (सिंगापुर: स्प्रिंगर, 2020)

[81] देखें लियांग गुओयोंग और डिंग हाओयुआन, चीन-अमेरिका व्यापार युद्ध (लंदन: रूटलेज, 2021)

[82] "चीन के राष्ट्रपति शी ने स्टारबक्स के पूर्व सीईओ हॉवर्ड शुल्ज़ को बीजिंग के साथ अमेरिकी संबंधों को सुधारने में मदद करने के लिए कहा" एनबीसी न्यूज 15 जनवरी, 2021 <https://www.nbcnews.com/business/business-news/china-s-president-xi-asks-former-starbucks-ceo-howard- schultz-n1254414>

[83] "साक्षात्कार प्रतिलेख: अमेरिका-चीन वार्ता, व्यापार पर पीटर नवारो" वीओए समाचार 6 दिसंबर, 2018 <https://www.voanews.com/a/transcript-peter-navarro-us-china-talks-trade/4689880.html> देखें

[84] मारिया एडेल कैरई, जेनिफर रूडोल्फ और माइकल स्ज़ोनी एडस में हुआंग युकोन, "अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध में कौन जीतता है और कौन हारता है?" चीन प्रश्न 2-अमेरिका-चीन संबंधों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि (कैम्ब्रिज: मास: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2022) देखें।

[85] हुआवेई कंपनी विवाद पर माइक ब्लैंचफील्ड और फेन ओस्लर हैम्पसन, द टू माइकल्स-अमेरिका-चीन साइबर युद्ध में निर्दोष कनाडाई बंदी और उच्च दांव जासूसी देखें (टोरंटो: सदरलैंड हाउस, 2021)

[86] पु ज़ियाओयू, "चीन अमेरिका को कैसे देखता है" मारिया एडेल कैरई, जेनिफर रूडोल्फ और माइकल स्ज़ोनी एडस में। चीन प्रश्न 2-अमेरिका-चीन संबंधों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि (कैम्ब्रिज: मास: हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2022)

[87] काई ज़िया, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नजर में चीन-अमेरिका संबंध-एक अंदरूनी परिप्रेक्ष्य सीजीआरपी सामयिक पेपर सीरीज़ नंबर 1 जून 2021 हूवर इंस्टीट्यूशन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी; हाओ युफान और सू लिन, चीन की विदेश नीति बनाने वाली सामाजिक शक्ति और चीनी अमेरिकी नीति (न्यूयॉर्क: रूटलेज, 2005) और गिल्बर्ट रोजमैन, चीन की विदेश नीति कौन इसे बनाता है, और यह कैसे बनाया जाता है? (न्यूयॉर्क: पालग्रेव मैकमिलन, 2012)। अमेरिका के विचारों के लिए देखें, ताओ वेनझाओ एड। शीत युद्ध के बाद चीन के लिए अमेरिकी नीति बनाने की प्रक्रिया - अमेरिकी थिंक टैंक और कूटनीति की भूमिका (सिंगापुर: स्प्रिंगर, 2018)

[88] बीआरआई और एआईआईबी ने अपने इतिहास में पहली बार कई महाद्वीपों के बीच पार्टी-राज्य को पेश किया, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सहायता, वित्त, दूरसंचार क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में अमेरिका को चुनौती दी। जबकि अमेरिका और अन्य ने "बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड" पहल शुरू की, बीआरआई ने महामारी से पहले बहुत प्रगति की। बीआरआई परियोजनाओं में चीन द्वारा 950 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया गया था। चीन ने 500 अरब डॉलर से अधिक की सहायता वितरित की जो आईएमएफ और विश्व बैंक के संवितरण से अधिक है। सेठ शिंडलर और जेसिका डिकार्लो को देखें। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट का उदय-कैसे अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता दुनिया भर में राजनीति और स्थान को आकार देती है (ब्रिस्टल: ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2022)

[89] शी चिनफिंग ने 18 अक्तूबर 2017 को कहा, "सभी मामलों में एक मध्यम समृद्ध समाज के निर्माण में निर्णायक जीत हासिल करें और एक नए युग के लिए चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद की महान सफलता के लिए प्रयास करें" <http://www.xinhuanet.com/english/ download/Xi_Jinping's_report_at_19th_CPC_National_Congress.pdf>

[90] शी जिनपिंग, "चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद के महान बैनर को ऊंचा रखें और सभी मामलों में एक आधुनिक समाजवादी देश बनाने के लिए एकता में प्रयास करें-चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20 वीं राष्ट्रीय कांग्रेस को रिपोर्ट करें" 16 अक्तूबर, 2022 को <https://english.www.gov.cn/news/topnews/202210/25/ content_WS6357_df20c6d0a757729e1bfc.html>

[91]वांग हुनिंग, [अमेरिका के खिलाफ] (शंघाई: वेनी प्रकाशन, 1991) में उद्धृत किया गया है कि <https: aaa.inversify.="" cn/=""> एक व्याख्या के अनुसार "अमेरिका के खिलाफ अमेरिका" भी वॉल स्ट्रीट, अमेरिकी वाणिज्यिक लॉबी और उद्यमों को प्रभावित करना है ताकि अमेरिकी समाज में विभाजन को तेज करते हुए चीन को समृद्ध करना जारी रखा जा सके। देखें वू यिजुन, "王 沪宁将从"美国反对美国" 进入"台湾反对台湾"" [वांग हुनिंग "अमेरिका के खिलाफ अमेरिका" से "ताइवान के खिलाफ ताइवान" में चले जाएंगे] शांगबाओ 13 मार्च, 2023 को <https: www-secretchina-com.translate.goog/news/gb/2023/03/13/1030929.="" html="">। यह भी देखें ""王 ","," "वांग हुनिंग "अमेरिका के पतन" के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति है, चीन समाचार 15 फरवरी, 2023 को <https:news.creaders.net/china/2023/02/15/2577781.html =""></https:></https:></https:>

[92] चीन की विदेश नीति और विद्वानों के विचारों के विभिन्न पहलुओं पर देखें फेंग हुइयुन, हे काई और यान शुएटोंग, एड. चीनी विद्वान और विदेश नीति-अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बहस (लंदन: रूटलेज, 2019)।

[93] सुसान, एल.;शिर्क, ओवररीच-कैसे चीन ने अपने शांतिपूर्ण उदय को पटरी से उतार दिया (न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2023); एस्ले टोजे, एड। क्या चीन का उदय शांतिपूर्ण होगा? सुरक्षा, स्थिरता और वैधता (न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2018)

[94] यान ज़ुएटोंग, प्राचीन चीनी विचार, आधुनिक चीनी शक्ति (प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011) डैनियल ए बेल और सन झे द्वारा संपादित। पृष्ठ 2.

[95] यान ज़ुएटोंग, "चीन-अमेरिका संबंधों की अस्थिरता" अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के चीनी जर्नल, 2010, पृष्ठ 1-30

[96] यान ज़ुएटोंग, नेतृत्व और महान शक्तियों का उदय (प्रिंसटन: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2019)

[97] यान 2011, पृष्ठ 16;

[98] यान 2019 पृष्ठ 34

[99] यान ज़ुएतोंग, "中国如何打败美国" [चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को कैसे हराया] 28 नवंबर, 2011 को <https://**Error! Hyperlink reference not valid.**页/20111128-阎学通：中国如何打败美国**>**

[100] यान ज़ुएतोंग, "中美战略竞争将走向何方" [चीन-अमेरिका रणनीतिक प्रतिस्पर्धा कहां जा रही है] 1 मई, 2023 को <https://www. aisixiang.com/data/ 142440.html**>**Yan

[101] यान ज़ुएटोंग, "美国还没走向绝对衰落,10年内被超越的可能性极小" [संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्ण गिरावट में नहीं गया है, और 10 वर्षों के भीतर पार होने की संभावना बहुत कम है] सोहू 29 दिसंबर, 2020 <https://www. sohu.com/a/ 441138463_100160903**>**

[102] यान शुएतोंग, "युद्ध से बचना, लेकिन हमेशा चिंतित" चीन-अमेरिका फोकस 28 दिसंबर, 2021 <https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/ avoiding-war-but-always-worried**>**

[103] वांग यिज़ौ, रचनात्मक भागीदारी-चीन की कूटनीति में एक नई दिशा (न्यूयॉर्क: रूटलेज, 2017) (पृष्ठ 20)

[104] वांग जिसी, "एक भव्य रणनीति के लिए चीन की खोज: एक उभरती हुई महान शक्ति अपना रास्ता खोजती है" विदेश मामलों के खंड 90, नंबर 2 (मार्च/अप्रैल 2011), पृष्ठ 68-79.

[105] वांग जिसी, "यूएस पावर/यूएस गिरावट और यूएस-चीन संबंध" झाओ लिंगमैन द्वारा साक्षात्कारद एशिया-पैसिफिक जर्नल-जापान फोकस 1 नवंबर, 2008, खंड 6 अंक 11 <https://apjjf.org/-Wang-Jisi/2950/article.html**>**

[106] यह ग्रीम एलिसन की 'डेस्टिनीड फॉर वॉर' या सैमुअल हंटिंगटन की क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन डिबेट के साथ चीन के उदय पर अमेरिका में चल रही चर्चाओं का प्रतिबिंब है. दूसरी ओर, अन्य अमेरिका से एक उदार प्रतिक्रिया का सुझाव देते हैं। केविन को रुड, परिहार्य युद्ध-अमेरिका और शी जिनपिंग के चीन के बीच एक विनाशकारी संघर्ष के खतरे (न्यूयॉर्क: पब्लिक अफेयर्स, 2022); गोल्डस्टीन, चीन से मिलना: उभरते अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता को कैसे खत्म किया जाए देखें (जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2015)

[107] https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11284

[108] पूर्वोक्त

[109] पूर्वोक्त

[110] संघीय जांच ब्यूरो, "चीन: शिक्षा के लिए जोखिम, 2018, https://www.fbi.gov/file-repository/china-risk-to-academia-2019.pdf/view

[111] राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, अक्तूबर 2022, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन, डीसी https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf

[112] पूर्वोक्त

[113] राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति, मार्च 2023, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन, डीसी https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2023/03/National-Cybersecurity-Strategy-2023.pdf

[114] संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति, दिसंबर 2017, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन, डीसी, https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/ nss/ NSS2017.pdf?ver=CnFwURrw09pJ0q5EogFpwg%3d%3d

[115] पूर्वोक्त

[116] पीटर बेकर, "चीनी-मध्यस्थता सौदा मध्यपूर्व कूटनीति और अमेरिका को चुनौती देता है," न्यूयॉर्क टाइम्स, 11 मार्च 2023। https://www.nytimes.com/2023/03/ 11/us/politics/saudi-arabia-iran-china-biden.html

[117] https://www.axios.com/2023/03/15/saudi-relations-biden-better-iran-china-deal

[118] https://www.reuters.com/world/not-rational-china-negotiate-outcome-ukraine-war-biden-2023-02-25/#:~:text=2%20months%20ago-,'Not%20rational'%20for%20China%20to%20negotiate%20outcome,of%20Ukraine%20war%2C%20Biden%20says&text=Feb%2024%20 (Reuters)%20%2D%20U.S.,peace%20plan%20for%20the%20conflict.

[119] विवरण के लिए, डगलस पोर्च देखें, "1996 का ताइवान स्ट्रेट संकट: संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के लिए रणनीतिक निहितार्थ," नेवल वॉर कॉलेज रिव्यू, खंड 52, नंबर 3, समर 1999।

[120] https://fapa.org/1005-extra-edition-149-chinese-warplanes-entering-taiwans-adiz-over-four-days-u-s-grave-concern-over-chinas-pressure- against-taiwan/

[121] विवरण के लिए देखें, लिंडसे मैज़लैंड, "झिंजियांग में उइगरों का चीन का दमन," विदेश संबंध परिषद, https://www.cfr.org/backgrounder/china-xinjiang-uyghurs-muslims-repression-genocide-human-rights

[122] https://www.theguardian.com/world/2022/sep/19/joe-biden-repeats-claim-that-us-forces-would-defend-taiwan-if-china-attacked#:~:text= Asked%20in%20October%20last%20year,the%20means%20to%20defend%20itself.

[123] "एक विस्तृत विश्लेषण के लिए, देखें पॉल हेनेल और नाथनियल शेर, "कैसे पेलोसी की ताइवान यात्रा ने अमेरिका-चीन तनाव के लिए एक नई स्थिति निर्धारित की है," https://carnegieendowment.org/2022/08/17/how-pelosi-s-taiwan-visit-has-set-new-status-quo-for-u.s-china- tensions-pub-87696

[124] “ताइवान के राष्ट्रपति साई ने चीन की चेतावनियों के बावजूद केविन मैकार्थी से मुलाकात की”, https://www.npr.org/2023/04/05/1167872114/kevin- mccarthy-taiwan-president-tsai-meeting-california-china

[125] "चीनी सेंसरशिप चुपचाप कोविड-19 की कहानी को फिर से लिख रही है," न्यूयॉर्क टाइम्स, 23 अप्रैल 2023। https://www.nytimes.com/2023/04/23/world/ europe/chinese-censorship-covid.html

[126] 2004 में स्थापित, कन्फ्यूशियस संस्थानों ने 146 देशों और क्षेत्रों में 525 संस्थानों में नौ मिलियन से अधिक छात्रों को नामांकित किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 100 से अधिक संस्थान खोले गए हैं, जिनमें कोलंबिया और स्टैनफोर्ड जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय शामिल हैं। ली एडवर्ड्स, "कन्फ्यूशियस संस्थान: चीन का ट्रोजन हॉर्स," कमेंट्री, द हेरिटेज फाउंडेशन, 27 मई 2021। https:// www.heritage.org/homeland-security/commentary/confucius-institutes-chinas-trojan-horse

[127] पूर्वोक्त

[128] वाशिंगटन पोस्ट, 22 मई 2018. विधेयक में चीन का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यह अमेरिकी कानून प्रवर्तन समुदाय को अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों के अंदर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विस्तार से निपटने के लिए अधिक उपकरण देने का एक स्पष्ट प्रयास है। https://www.washingtonpost.com/news/josh-rogin/wp/2018/ 05/22/preventing-chinese-espionage-at-americas-universities/

[129] पूर्वोक्त

[130] n.4

[131] https://www.insidehighered.com/news/2019/01/09/colleges-move-close-chinese-government-funded-confucius-institutes-amid-increasing

आईसीडब्ल्यूए के बारे में

भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए) की स्थापना 1943 में सर तेज बहादुर सप्रू और डॉ. एच.एन. कुंजरू के नेतृत्व में प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों के एक समूह द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर एक भारतीय परिप्रेक्ष्य बनाना और विदेश नीति के मुद्दों पर ज्ञान और चिंतन के भंडार के रूप में कार्य करना था। परिषद आज एक इन-हाउस संकाय के साथ-साथ बाहरी विशेषज्ञों के माध्यम से नीति अनुसंधान करती है। यह नियमित रूप से सम्मेलनों, संगोष्ठियों, गोलमेज चर्चाओं, व्याख्यानों सहित बौद्धिक गतिविधियाँ आयोजित करती है और प्रकाशन करती है। इसमें सुभंडारित पुस्तकालय, एक सक्रिय वेबसाइट है, और 'इंडिया क्वार्टरली' पत्रिका का प्रकाशन करती है। आईसीडब्ल्यूए ने अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और अनुसंधान संस्थानों के साथ 50 से अधिक समझौता ज्ञापन किए हैं। परिषद की भारत में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों, थिंक टैंक और विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी भी है।

भारतीय वैश्विक परिषद
सप्रू हाउस, नई दिल्ली

/आईसीडब्ल्यूए_नई दिल्ली i /सप्रू हाउस
/भारतीय वैश्विक परिषद1
/आईसीडब्ल्यूए नई दिल्ली i

www.icwa.in